कार की उड़ान

उड़ने वाली कार का ख्वाब पुराना है और इसे पूरा करने की दिशा में टेस्ला कंपनी की महत्वपूर्ण पहल स्वागत-योग्य है। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शुमार उद्यमी एलन मस्क ने खुद ऐसी कार या रोडस्टर का अनावरण करते हुए दावा किया है कि अब कार उड़ सकती है। एक इंसान के बैठने की क्षमता वाली इस रोडस्टर में चारों ओर कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगे हैं, जिनकी ताकत से यह ऊपर उठ सकती है और आगे बढ़ सकती है। हालांकि, यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि यह उड़ने वाली कार नहीं, बल्कि सुरक्षित छलांग लगाने वाली कार है। करीब दस साल की मेहनत से बनी यह रोडस्टर कुछ फीट ऊंचाई और कुछ फीट की दूरी उड़कर तय कर सकती है। बेशक, यह एक बेहतरीन प्रयोग है, जिसमें मोटर विज्ञान को रॉकेट विज्ञान के साथ मिला दिया गया है। इस रोडस्टर को हम पूरी तरह से उड़ने वाली कार तो नहीं कह सकते, लेकिन यह उड़ने वाली कारों की पहली पीढ़ी का एक सराहनीय आगाज है। इसमें कोई दोराय नहीं, टेस्ला एक ऐसी आधुनिक कंपनी है, जो वाहन विज्ञान के साथ ही विमानन में भी अपनी महारत साबित करती रही है। अपनी नई कामयाबी के लिए टेस्ला की जरूर तारीफ होनी चाहिए।

कोई संदेह नहीं, एलन मस्क दुनिया में अपनी तकनीकी कुशलता और मार्केटिंग की वजह से ही अमीर हुए हैं और रोडस्टर को पेश करते हुए भी उन्होंने अपनी व्यावसायिक कुशलता का भरपूर परिचय दिया है। ध्यान रहे, टेस्ला ने इस कार के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और यह तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी। परफॉर्मेंस और थ्रस्ट वेरिएंट की बिक्री ज्यादा व्यावहारिक मानी जा रही है, क्योंकि ये दोनों वेरिएंट सड़क के लिए ही मुफीद हैं, जबकि रॉकेट वेरिएंट में छलांग लगाने की क्षमता है। हालांकि, अभी भी रॉकेट कारों पर प्रयोग जारी हैं और इन्हें उपयोगिता के हिसाब से सुरक्षित बनाया जा रहा है। साल 2029 में ये रॉकेट जैसी गुणवत्ता रखने वाली कारें सड़कों पर दिखने लगेंगी, पर कार को सचमुच हवा में देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यह कार सिर्फ आमंत्रण पर ही उपलब्ध हो सकेगी। जहां तक भारत की बात है, तो यहां छलांग लगाने या उड़ने वाली कार को आने में काफी वक्त लग सकता है। भारत में पिछले वर्ष जुलाई में ही टेस्ला के कारों की बिक्री शुरू हुई है और कीमत 50 लाख रुपये से भी ज्यादा है। इस कंपनी को अपेक्षाकृत कीमती कारों के निर्माण के लिए जाना जाता है। टेस्ला ने अपनी रॉकेट कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है, पर अनुमान अगर लगाएं, तो इसकी कीमत चार करोड़ रुपये के आस-पास ठहरेगी। यहां यह भी बताते चलें कि अभी बाजार में एक अच्छा चार सीटों वाला हेलीकॉप्टर चार करोड़ रुपये में उपलब्ध है।

करीब दस साल की मेहनत से बनी टेस्ला की यह रोडस्टर कुछ फीट की दूरी हवा में उड़कर तय कर सकती है। बेशक, यह एक बेहतरीन प्रयोग है।

यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि भारत जैसे विकासशील देश में बहुत महंगे वाहनों का बाजार बहुत बड़ा नहीं हुआ है। वैसे भी, भारत में सौ में से केवल आठ परिवारों के पास कार है, जबकि बिहार जैसे राज्य में सौ में से केवल तीन परिवार के पास कार है। पूरे साल में देश में 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की बमुश्किल 60 हजार कारें ही बिक पाती हैं। भारत में संपन्नता बढ़ी है, भारतीय भी धीरे-धीरे महंगी गाड़ियां खरीदने में सक्षम हो रहे हैं। स्थानीय वाहन कंपनियां यहां के हालात के मुताबिक बेहतर वाहन बनाने में जुटी रहती हैं। भारत के लिए रोडस्टर या रॉकेट कार अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन यहां की कार निर्माता कंपनियों को टेस्ला जैसे प्रयोगों से जरूर सीखना चाहिए। लोग अपनी जेब के अनुरूप बेहतर से बेहतर वाहनों का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस की भूमिका सुधरनी चाहिए


यहां स्कैन करें

यशोवर्द्धन झा आजाद | पूर्व आईपीएस अधिकारी

देश में सुधार की शुरुआत पुलिस के भीतर से होनी चाहिए। उसमें अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और भीड़ से संवाद-कौशल का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

किसी भी सफल लोकतंत्र में पुलिस की सबसे कठिन परीक्षा नाराज नागरिकों के सामने संयम बनाए रखने की होती है। प्रदर्शनकारियों के मामले में कानून का पालन करते हुए उनके अधिकारों को भी सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक होता है। हालिया विरोध-प्रदर्शनों ने इसी कसौटी पर पुलिस के रवैये और राजनीतिक नेतृत्व की समझ, दोनों को कठघरे में खड़ा किया है।

अभी पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं दिखता। सरकार को लगता है कि वह पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती, विपक्ष को उसकी लगभग हर कार्रवाई अनुचित लगती है, लेकिन पुलिस को अधिक पेशेवर, सक्षम और जवाबदेह बनाने वाले सुधारों पर सबकी चुप्पी बनी रहती है। हर टकराव के बाद बहस लाठीचार्ज पर शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। उस राजनीतिक विफलता पर कम चर्चा होती है, जो समस्या को समय रहते सुलझाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देती है।

पिछले तीन महीनों के घटनाक्रम को तीन चरणों में देखना उपयोगी होगा। पहला चरण नीट से जुड़े सवालों पर कांकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर मंतर आंदोलन था। तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले धरने के दौरान कोई प्रभावी संवाद-प्रक्रिया विकसित नहीं हुई। 20 जुलाई को जब संसद मार्च घोषित हुआ, तब टकराव की आशंका थी। प्रतिबंधित रास्ते, बैरिकेड और उत्तेजित भीड़- यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई थी। समय रहते यदि बातचीत होती, तो शायद सड़क पर शक्ति-परीक्षण की नौबत टल सकती थी।

बैरिकेड तोड़ना, पुलिस को उत्तेजित करना या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे सफल प्रदर्शन का संकेत भी मानते हैं। हालांकि, बैरिकेड टूटने से अंधाधुंध लाठीचार्ज का अधिकार भी नहीं मिल जाता। कार्रवाई आवश्यक, आनुपातिक और नियंत्रित होनी चाहिए। उद्देश्य खतरे को रोकना होना चाहिए, भीड़ को सबक सिखाना नहीं, मगर 'हल्का लाठीचार्ज' जैसा कोई वाक्यांश पुलिस शब्दावली में नहीं होता और सिर्फ कह देने से चोट हल्की नहीं होती।



जुलाई की कार्रवाई में महिलाओं से दुर्व्यवहार, राहगीरों को पीटने और सादे कपड़ों में डंडे चलाने जैसे आरोप गंभीर हैं। इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। भीड़ नियंत्रण में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। सादे कपड़ों में सूचनाएं जुटाना अलग काम है; पर पहचान छिपाकर बल प्रयोग करना जवाबदेही को कमजोर करता है। इसी तरह, घायल पुलिसकर्मियों और उनके विरुद्ध हिंसा की अनदेखी भी नहीं हो सकती। निष्पक्षता का अर्थ दोनों पक्षों के आचरण की जांच है।

दूसरा चरण 10 अक्तूबर का प्रदर्शन था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियों के साथ व्यापक रोकथाम की व्यवस्था की गई। खबरों के अनुसार, 245 रेलगाड़ियां रद्द हुईं और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। मेट्रो के 40 से अधिक स्टेशनों पर प्रवेश-निकास संबंधी प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट सेवाएं मध्य नई दिल्ली में बंद कर दी गईं।

पुलिस का पक्ष समझना जरूरी है। उसने पिछली हिंसा, आयोजकों द्वारा नियम-पालन में कमी और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे का हवाला दिया, पर असली प्रश्न यह है कि क्या इन जोखिमों का सामना सीमित, लक्षित प्रतिबंधों से किया जा सकता था? किसी प्रदर्शन से आसन्न व्यवधान को रोकने के लिए प्रशासन स्वयं कितनी बड़ी रोकथाम को उचित मान सकता है? यदि आयोजकों से स्थान, समय, संख्या और मार्ग पर सहमति बनाई जाती, प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी तय होती और हिंसा रोकने की स्पष्ट शर्तें रखी जातीं, तब जवाबदेही उनकी बनती। इसके बजाय एक स्थान तक पहुंच रोकने से प्रदर्शनकारी अनेक जगहों पर बिखर गए। एक संगठित सभा संभालने की तुलना में बिखरे टकराव को रोकना अधिक कठिन होता है।

यहां पुलिस आयुक्त की पेशेवर भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें उपलब्ध खुफिया सूचनाओं और वास्तविक जोखिम के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की वैध भूमिका है, लेकिन पुलिस कमिश्नर की कार्यकारी स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि निर्णयों का आधार कानून और खतरे का आकलन हो।

तीसरे चरण में विपक्ष का संयुक्त मार्च हुआ। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी, दोनों ने अपेक्षाकृत संयम बरता। हालांकि, रास्ते में पुलिस अवरोध और रोक भी रही, फिर भी यह तुलना उपयोगी है कि बड़ी भीड़ अपने-आप हिंसा का पर्याय नहीं होती। नेतृत्व, संवाद और तैनाती का ढंग घटनाक्रम को प्रभावित करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर की निषेधाज्ञाएं रिकॉर्ड में रखने और सीसीटीवी सहित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भी जवाब मांगा गया है। इससे पुलिस दोषी सिद्ध नहीं हो जाती, पर कार्रवाई की वैधता और अनुपात की जांच का रास्ता जरूर खुलता है। ऐसी जांच पुलिस और नागरिक, दोनों का विश्वास बढ़ा सकती है।

पश्चिमी लोकतंत्र भी इस समस्या से मुक्त नहीं हैं। फ्रांस में हालिया छात्र प्रदर्शनों के दौरान गंभीर चोटों और पुलिस बल प्रयोग पर सवाल उठे; सरकार ने स्टन ग्रेनेड के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में 2024 के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रोफेसर को जमीन पर गिराकर गिरफ्तार करने की घटना विवाद और मुकदमे तक पहुंची। ब्रिटेन एक दूसरा सबक देता है: नवंबर 2023 में लंदन पुलिस प्रमुख ने राजनीतिक दबाव के बावजूद फलस्तीन समर्थक मार्च पर प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीर अल्पसंख्यक को पर्याप्त आधार नहीं माना। विदेशों के ये उदाहरण पेशेवर निर्णय और जवाबदेही की दिशा दिखाते हैं।

भारत में सुधार की शुरुआत पुलिस के भीतर भी होनी चाहिए। अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, तनाव में निर्णय और संवाद-कौशल का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए समय, संसाधन और नेतृत्व चाहिए। गैर-पुलिस ड्यूटी में उलझे बल से निरंतर पेशेवर प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे की जाए?

आंदोलनकारियों को समझना होगा कि पुलिस वाले शत्रु नहीं हैं। सरकारों को समझना होगा कि राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर हमेशा निषेधाज्ञा नहीं होता। पुलिस भीड़ संभाल सकती है, राजनीतिक असंतोष का समाधान नहीं कर सकती। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि सत्ता ने कितने प्रदर्शन रोके, बल्कि इससे कि उसने कितनी असहमति सुरक्षित रहने दी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत


यहां स्कैन करें

हिमांशु | एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू

भारत के अधिकांश ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, गांवों में मिलने वाली मजदूरी। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से गहरे जुड़े होने के कारण ग्रामीण मजदूरी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट को दर्शाने वाले उन चुनिंदा संकेतकों में से एक है, जिनके आंकड़े लगातार उपलब्ध होते रहे हैं।

श्रम ब्यूरो द्वारा साल 1998 से ही हरेक महीने 12 कृषि और 13 गैर-कृषि व्यवसायों के आंकड़े जारी किए जाते रहे हैं। जुलाई 2025 से इस शृंखला में बदलाव किया गया। श्रम ब्यूरो ने वेतन डाटा इकट्ठा करने और रिपोर्ट के दायरे एवं तरीके (मेथडोलॉजी), दोनों में बदलाव किए। इस बदलाव के तहत गांवों की संख्या बढ़ाई गई है और इसे कृषि मजदूरों के लिए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएल) से भी जोड़ा गया है। जुलाई 2025 से शुरू हुई इस नई शृंखला का दायरा बढ़ाकर इसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जबकि पहले इसमें केवल 20 प्रमुख राज्य शामिल थे। जाहिर है, इसका मतलब यह भी है कि नई शृंखला की तुलना पुरानी से नहीं की जा सकती। इस शृंखला में एक तरह का 'ब्रेक' आ गया है। बहरहाल, 2025 के मध्य तक के ग्रामीण इलाकों के आंकड़े बताते हैं कि कृषि और गैर-कृषि, दोनों तरह की पारिश्रमिक में ठहराव था।

ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई पहले ही आठ प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है, ऐसे में महंगाई की कोई नई आशंका हालात और बिगाड़ देगी।

जुलाई 2015 से जून 2025 के दशक में कृषि क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में यह सालाना 0.2 फीसदी की दर से बढ़ी। आजादी के बाद से एक दशक की अवधि में यह वृद्धि दर सबसे धीमी है। अगर हम कोविड के बाद की अवधि, यानी जुलाई 2019 से शुरू होने वाले आंकड़ों को देखें, तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में इसमें सालाना 0.1 फीसदी की गिरावट आई।

नई शृंखला के तहत जुलाई और अगस्त 2026 के डाटा अब उपलब्ध हैं। ये बताते हैं कि जुलाई में कृषि व्यवसायों की वास्तविक मजदूरी में 1.5 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों की मजदूरी में 1.6 फीसदी की गिरावट आई। अगस्त में इनमें और गिरावट आई, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि व्यवसायों में 1.9 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों में 2.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि कार्यों की मजदूरी में पुरानी शृंखला में देखी गई मामूली वृद्धि के मुकाबले गिरावट आई है। इसी तरह, गैर-कृषि कार्यों की दिहाड़ी में गिरावट की दर कहीं अधिक तेज हुई है। ये आंकड़े अन्य स्रोतों से सामने आए ग्रामीण संकट के और गहराने की पुष्टि करते हैं। साफ है, अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को लेकर देश के शहरी इलाकों में जो उत्साह है, वह ग्रामीण इलाकों में नदारद है। गौर कीजिए, जुलाई-अगस्त में न केवल अलनीनो के कारण कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि ये दोनों महीने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जीरामजी) के लागू होने के शुरुआती दो महीने भी थे।

इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोनों ही इंजन- खेती-किसानी और गैर-कृषि व्यावसायिक गतिविधियां- प्रभावित होते दिख रहे हैं। असल में, खेतिहर मजदूरी की तुलना में गैर-कृषि कार्यों में मिलने वाली मजदूरी में कहीं ज्यादा गिरावट आई है। ऐसे में, हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई पहले ही आठ प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में, महंगाई में होने वाली अब कोई भी बढ़ोतरी गैर-कृषि क्षेत्र की नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इससे गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी।

इसलिए सरकार को वीबी-जीरामजी के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए अपने कुछ नए प्रावधानों में ढील देनी होगी। साथ ही, गरीब राज्यों को वित्तीय सहायता की भी जरूरत होगी। वीबी-जीरामजी को मजबूत करना न केवल ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए जरूरी है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी यह आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रामीण खपत में वृद्धि जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आपका शरीर तीर्थस्थल

कर्मांशय का अर्थ है, समस्त संस्कारों की समष्टि। हम जो भी कार्य करते हैं, वह हमारे चित्त रूपी सरोवर में एक लहर उठा देता है। हम सोचते हैं कि इस काम के समाप्त होते ही वह लहर भी चली जाएगी; पर वास्तव में वैसा नहीं होता। वह तो बस सूक्ष्म आकार धारण कर लेती है, पर रहती वहीं है। जैसे ही हम उस कार्य को स्मरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, वह फिर से उठ जाती है और लहर रूप धारण कर लेती है। इससे यह स्पष्ट है कि वह मन के ही भीतर छिपी हुई थी; यदि ऐसा न होता, तो स्मृति ही संभव न होती।

मनुष्य का हर एक कार्य, हर एक विचार, वह चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ, मन के गहरे प्रदेश में जाकर सूक्ष्म भाव धारण कर लेता है और वहीं संचित रहता है। शुभ और अशुभ, दोनों प्रकार के विचार को क्लेश कहते हैं, क्योंकि योगियों के मतानुसार दोनों से ही अंत में दुख उत्पन्न होता है। याद रखिए, इंद्रियों से जो सुख मिलता है, वह अंत में दुख ही लाता है; क्योंकि भोग से और अधिक भोग की तृष्णा होती है और इसका अनिवार्य फल होता है दुख।

मनुष्य की वासना का कोई अंत नहीं है; वह लगातार वासना पर वासना रचता जाता है, और जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है, जहां उसकी वासना पूर्ण नहीं होती, तो उसका फल होता है- दुख। इसीलिए योगी शुभ या अशुभ समस्त संस्कारों की समष्टि को क्लेश कहते हैं; ये क्लेश आत्मा की मुक्ति में बाधक होते हैं।

हमारे सारे कार्यों के सूक्ष्म मूल संस्कारों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वे कारण स्वरूप होकर इहजीवन अथवा परजीवन में फलप्रसव करते हैं। विशेष स्थलों पर ये संस्कार, अधिक प्रबल रहने के कारण बहुत शीघ्र अपना फल दे देते हैं; अल्पोत्कट (अत्यधिक) पुण्य या पाप कर्म इहजीवन में ही अपना फल सामने ला देता है। योगी कहते हैं कि जो मनुष्य इहजीवन में ही अत्यंत प्रबल शुभ संस्कार उपार्जित कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु तक बाट जोहने की आवश्यकता नहीं होती। वे इसी जीवन में अपने शरीर को देवशरीर में परिणत कर सकते हैं।

शरीरशास्त्र के अनुसार, भोजन का अर्थ है- सूर्य से शक्ति ग्रहण। वह शक्ति पहले वनस्पति में प्रवेश करती है, उस वनस्पति को कोई पशु चर लेता है, फिर उस पशु को मनुष्य। इसे वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करना हो, तो कहना पड़ेगा कि हमने सूर्य से कुछ शक्ति ग्रहण करके उसे अपने अंगीभूत कर लिया। योगियों का कहना है कि वे केवल मन की शक्ति से शक्ति-संग्रह कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हम बिना किसी साधारण उपाय का अवलंबन किए यथेष्ट शक्ति भीतर ले सकते हैं। हम मकड़ी की तरह क्यों बद्ध हों?

जो मनुष्य इहजीवन में ही अत्यंत प्रबल शुभ संस्कार उपार्जित कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु तक बाट जोहने की जरूरत नहीं होती। वे इसी जीवन में अपने शरीर को देवशरीर में परिणत कर सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद

वीपी मलिक | पूर्व सेनाध्यक्ष



कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा लगाए गए रक्षा प्रतिबंधों और हाल ही में उसके द्वारा थोपे गए टैरिफ को देखते हुए मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी दूरसंचार व्यवस्था किसी विदेशी स्वामित्व वाली प्रणाली पर निर्भर रहे।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 17 अक्तूबर, 1951

कांग्रेस की विजय

दिल्ली म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस ने जो शानदार विजय प्राप्त की है उसे अभूतपूर्व अथवा आशातीत कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी। पहले कांग्रेस-क्षेत्रों में यह अनुमान प्रकट किया गया था कि 50 स्थानों में से 30 स्थान तक कांग्रेस के अधिकार में आ जाएंगे लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के मन्त्री ने घोषित किया है कि 42 स्थानों पर कांग्रेस विजयी हुई है। जन संघ के केवल 5 उम्मीदवार विजयी हुए। यदि एक स्वतन्त्र उम्मीदवार को जन संघ के पक्ष में मान लें, जैसा कि उसका दावा है, तो संख्या 6 हो जाती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों में केवल 3 निर्वाचित हुए। समाजवादियों तथा संयुक्त प्रगतिशील दल ने क्रमशः 18 तथा 13 उम्मीदवार खड़े किये थे किन्तु एक स्थान पर भी उनका अधिकार न हुआ।

वयस्क मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक नगरपालिका के चुनावों की दृष्टि से उनको स्थानीय महत्व देना ठीक नहीं। चुनावों के परिणाम बता देते हैं कि हवा का रुख किधर है। जन संघ तथा हिन्दू महासभा वालों ने इन चुनावों में विजय प्राप्ति के उद्देश्य से एड़ी-चोटी का पसीना एक किया। महीनों से वे तैयारी में जी-जान से जुटे हुए थे। संघ ने अपनी सारी शक्ति दिल्ली पर केन्द्रित कर दी थी। राजधानी से बाहर दूर के स्थानों से भी जन संघ के स्वयंसेवक जिनकी तादाद 5000 आंकी जाती है, दिल्ली में एकत्र हुए। अतएव हिन्दू महासभा तथा भारतीय जन संघ को इस बारे में कोई शिकायत नहीं रह जाती कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। केवल संख्या की दृष्टि से ही इन संस्थाओं की करारी हार न हुई बल्कि उनके दो नेता ओं को साधारण कांग्रेसजनों के मुकाबले पराजय का मुंह जोहना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ-चालक श्री हरिचन्द 20 वर्षों से सदस्य रहते आये हैं। उनका प्रभाव भी अधिक है। लाल दरवाजा जहां से कि वह खड़े हुए थे, उनका 'गढ़' कहा जाता है। फिर भी वह हार गये। इसी तरह दिल्ली प्रदेश हिन्दू महासभा के अध्यक्ष प्रो. रामसिंह भी निर्वाचन में असफल रहे। चुनावों परिणामों की विवेचना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाताओं ने उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्थिति की अपेक्षा उन सिद्धांतों का ध्यान रखा जिनके आधार पर वे खड़े हुए थे।

असहमति की आवाज को दबाने की चाल

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है। इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को धरना-प्रदर्शन के लिए नए स्थानों के रूप में निर्धारित किया गया है। इससे संसद और प्रमुख सरकारी संस्थानों के आसपास प्रदर्शन करने की व्यावहारिक संभावनाएं निश्चित रूप से प्रभावित होंगी।

रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीटी शाहदरा से क्या असहमति के स्वर देश की संसद तक पहुंचेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि राजधानी की सड़कों पर कितने प्रदर्शन हुए, बल्कि इससे मापी जाती है कि सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को कितनी गंभीरता से सुनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग अपनी शिकायत लेकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच ही न सकें।

जन आंदोलनों को सत्ता केंद्रों से दूर धकेलने की यह पुरानी प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1988 तक बोट क्लब पर देश के सबसे बड़े और चर्चित प्रदर्शन हुआ करते थे, जो संसद और राष्ट्रपति भवन की ठीक नाक के नीचे है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 1988 में जब लाखों किसानों ने बोट क्लब पर डेरा डाला, तो सरकार ने सुरक्षा-व्यवस्था का हवाला देकर वहां विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगानी शुरू कर दी और वर्ष 1993 में जंतर मंतर को नया स्थल बनाया गया। एनजीटी ने 2017 में पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देकर जंतर मंतर पर भी आंशिक पाबंदियां लगाईं, और अब इसे पूरी तरह से सूची से हटा दिया गया है।

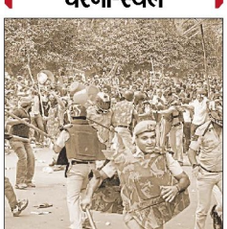
बोट क्लब से जंतर मंतर और अब जंतर मंतर से बुराड़ी, कड़कड़डूमा के मैदानों तक का यह सफर वास्तव में सत्ता के गलियारों से आम जनता को दूर रखने की चाल है। लोकतंत्र में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का मूल उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिये अपनी बात देश के सामने रखना होता है। जंतर मंतर की भौगोलिक स्थिति उसे यह विशेष महत्व देती थी।

इसके विपरीत, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी या पूर्वी दिल्ली का कड़कड़डूमा क्षेत्र दिल्ली के मुख्य प्रशासनिक केंद्रों से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बाहरी इलाकों में प्रदर्शनों को स्थानांतरित करने से प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में जरूर आसानी होगी, पर जन आंदोलनों की दृश्यता और प्रभावशीलता कम हो जाएगी। जब विरोध की आवाज सत्ता के केंद्र से दूर चली जाएगी, तो उसकी अनदेखी करना तंत्र के लिए और आसान हो जाएगा। इसीलिए यह परिवर्तन किए गए हैं।

अमन कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

धरना-स्थल



छोटी जगह हो, तो भीड़ नियंत्रण मुश्किल

देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल में स्थित जंतर मंतर पिछले 33 वर्षों से लोकतांत्रिक चेतना, जन आक्रोश और नागरिक उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। किंतु अब इसे अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक स्थल से प्रदर्शनों को हटाने के पीछे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अपने तर्क दिए हैं।

तात्कालिक कारणों पर नजर डालें, तो वर्ष 2026 के जून और जुलाई माह में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर लगभग 36 दिनों तक चला विशाल छात्र आंदोलन इस फैसले का मुख्य आधार बना। उस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की सीमित क्षमता के विपरीत एक लाख से अधिक प्रदर्शनकारी जुट गए थे। जब इस भारी भीड़ ने संसद भवन की ओर कूच करने का प्रयास किया, तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़पों में 118 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों छात्र घायल हुए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और युवा संगठनों द्वारा फिर से जंतर मंतर पर बड़े घेराव की तैयारी की जा रही थी। नए संसद भवन और कर्तव्य पथ के आसपास अति विशिष्ट व्यक्तियों के निरंतर आवागमन और संवेदनशील मंत्रालयों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का मानना है कि इतनी कम दूरी पर अनियंत्रित भीड़ का जुटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

सुरक्षा के अलावा स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों की दैनिक परेशानियां भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण बनी हैं। जंतर मंतर राजधानी के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र- कनॉट प्लेस और जनपथ के ठीक बगल में स्थित है। जब भी यहां कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, तो एहतियात के तौर पर आसपास की मुख्य सड़कें और रेल के भूमिगत स्टेशन बंद कर दिए जाते थे। इससे न केवल घंटों लंबा यातायात जाम लगता था, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों की गाड़ियां छूट जाती थीं। स्थानीय व्यापार मंडलों ने लंबे समय से यह शिकायत की थी कि लगातार होने वाले धरनों और नाकेबंदी के कारण कनॉट प्लेस के व्यापार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्व में यह सुझाव दिया था कि प्रदर्शनों के लिए ऐसी खुली और बड़ी जगह तलाशी जानी चाहिए, जहां आम जनजीवन प्रभावित न हो और प्रदर्शनकारियों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

कांग्रेस नेता ने छात्रों के साथ बातचीत का वीडियो साझा किया

पुलिस की बर्बरता को यूं ही नहीं जाने देंगे: राहुल

निशाना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर छात्रों पर हुए हमलों के मामले में दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता को यूं ही जाने नहीं दिया जाएगा। पार्टी अदालतों में हर कानूनी रास्ता अपनाएगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एनएसयूआई और दूसरे छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया है। करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में छात्र और युवा पुलिस पिटाई की अपनी आपबीती सुना रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों की पिटाई करने वाले अफसरों पर जबरस्त दबाव डालेंगे। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यह किया है उन पर ऐसा दबाव डालें कि अगला व्यक्ति ऐसा नहीं करे। छात्रा अपनी बातचीत में महिला पुलिसकर्मी चंचल यादव का कई बार जिक्र करती है। चंचल का नाम लेते हुए राहुल गांधी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उसे हम उदाहरण बनाएंगे, पूरे देश में दबाव बनाएंगे। इसके साथ सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि केरल की अथिरा और राजस्थान की रितु समेत कई अन्य युवतियों को दिल्ली पुलिस ने पीटा है। उन्होंने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है। केरल में पहले ही एक जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ केरल, राजस्थान और अदालतों में हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे।



लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र ने उन्हें अपनी चोट दिखाई।

सरोजिनी नायडू का उदाहरण दिया : स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 1930 धरासना में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में निहत्थे सत्याग्रहियों ने पुलिस की लाठियों का सामना किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी किसी सत्याग्रही ने हाथ नहीं उठाया। पूरी दुनिया ने यह देखा।

अराजकता से सत्ता चाहता है विपक्ष : नितिन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन (रिजिम चेंज) के आह्वान पर शुक्रवार को भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए विपक्ष पर अराजकता फैलाकर किसी भी तरह सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया है।

पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि अब यह साफ है कि यह कुत्सित प्रयास विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने के अर्बन नक्सल एजेंडे का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस बार बार संविधान व जनादेश को अपमानित कर रही है।



भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला

असली एजेंडा देश के सामने स्पष्ट रूप से उजागर : भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों के प्रयोग से विपक्ष का असली एजेंडा देश के सामने स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का यह कुत्सित प्रयास अर्बन नक्सल के एजेंडे का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधार,एसआईआर या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए है।

नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से होकर गुजरता है, अराजकता से नहीं। भारत की राष्ट्रभक्त जनता और भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगी।

देश 30 S

दिल्ली पुलिस क्या कर रही है : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सीजेपी नेता अभिजीत दीपके की पुलिस हिरासत की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को जबरन दबाया जा रहा। एक्स पर पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है?

मतदान के अधिकार से रोका जा रहा : द्रमुक

चेन्नई। द्रमुक सांसद कनिमोझी ने शुक्रवार एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को केंद्र सरकार देश विरोधी करार दे देती है।

अनियमितता का विरोध होगा : डीएमके

चेन्नई। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा के बाद राजनीति गरमा गई है। विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का यह कदम व्यापक एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद विपक्षी दलों को शांत करना है।

सरकार परिवर्तन कराना ही हमारा मकसद: कांग्रेस

नई दिल्ली, वि.सं./एजेंसी। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी ने साफ कहा कि सरकार और सत्ता परिवर्तन ही विपक्ष का मकसद, आधार और जिम्मेदारी है।

पार्टी का कहना है कि विपक्ष चुनाव के जरिए सत्ता बदलने की बात कर रहा। कोई व्यक्ति इससे नाराज या खिलाफ है वह संविधान के खिलाफ है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष चुनाव के जरिए सरकार बदलना है चाहता है पर भाजपा इस अभियान से परेशान है। क्योंकि, भाजपा को अब लोकतंत्र की आदत नहीं रही है। बांग्लादेश के जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हम आरएसएस की तरह प्रतीक उधार नहीं लेते। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान याद दिलाने की जरूरत: कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी राजनाथ सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस बयान को याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम विरोध करना, सच्चाई सामने लाना और सरकार को सत्ता से हटाना है।

आमने-सामने

भाजपा बोली- प्रदर्शन का सच किसी से छिपा नहीं

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है।

प्रधान ने कहा कि खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है। विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है। भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

सिर्फ चुनावों से हो सकता है बदलाव : फडणवीस

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि देश में जब तक संविधान मौजूद है, तब तक सत्ता परिवर्तन केवल चुनावों के जरिए ही हो सकता है और फैसले संसद में लिए जाएंगे। सीएम का यह बयान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सत्ता परिवर्तन संबंधी टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच आया है।

रेलवे ने स्टेशन मास्टर भर्ती की आयुसीमा बढ़ाई

नई दिल्ली, एजेंसी। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है, जो 7 अक्तूबर से लागू हो गई है। बोर्ड ने 'इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल' में संशोधन किया है। इसमें पहले आयु सीमा 18-30 वर्ष निर्धारित थी।

सात अक्तूबर को जारी एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करने का निर्णय लिया है। यह सूचना सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों तथा रेलवे भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को भेजी गई है। यह संशोधन इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

जो मामले पहले से ही प्रक्रिया में हैं (जहां केंद्रीय रोजगार अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है), उन पर पुरानी भर्ती नियमावली के अनुसार ही कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें आगे कहा गया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए) ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एसोसिएशन की एक लंबे समय से लंबित मांग बताया है।

सुप्रीम कोर्ट सुनेगा पत्रकार का मामला

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के दौरान कथित तौर पर एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का देने का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने याचिका का उल्लेख करते हुए इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

संजय राउत समेत दो को नोटिस भेजे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से उनके खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सांसद राउत और पत्रकार वागले को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमाननना कार्यवाही शुरू की जाए। हालांकि, पीठ ने फिलहाल उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है।



सीजेआई और न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का मामला

सीजेआई ने कहा कि जब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या किसी अधिकार पर खतरा आता है, तो लोग मदद के लिए अदालत का रुख करते हैं। अदालतों ने हमेशा इन अधिकारों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर वही लोग अदालतों की निंदा करें, आलोचना करें या उन पर तीखे हमले करें, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण।''

राउत बोले-जरूरत पड़ी तो माफी मांगने को तैयार : मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कोई अनुचित टिप्पणी की है, तो भारतीय संविधान की रक्षा करने वाली इस संस्था से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि न तो उनका और न ही उनकी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का कोई इरादा था। राउत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

कारण बताओ नोटिस

सेवा नं. TA-42815H मेजर हिमांशु रुस्तोगी

1. **जबकी**, आपको 13 मई 2011 को प्रादेशिक सेना में कमीशन प्रदान किया गया था।
2. **और जबकि**, 115 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) महार द्वारा प्रादेशिक सेना नियम, 1948 (संशोधित संस्करण 1964) के नियम 20 के अंतर्गत सैन्य सेवा हेतु बुलाए जाने के लिए निम्नलिखित कॉल–अप नोटीस जारी किए जाने के बावजूद, आप प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होने में विफल रहे हैं।
3. **और जबकि**, आपने लगातार दो प्रशिक्षण वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में न तो भाग लिया है और न ही वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने से छूट प्राप्त की है।
4. **और जबकि**, प्रादेशिक सेना नियम 1948 (संशोधित संस्करण 1964) के नियम 14(डी) में प्रावधान है की, ''प्रादेशिक सेना के ऐसे अधिकारी, जो इन नियमों के नियम 20 के उप नियम (2) में प्रावधानित छूट प्राप्त किए बिना लगातार दो वर्षों तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में उपस्थित नहीं होते हैं तथा अपनी अनुपस्थिति के औचित्य के संबंध मे कोई वैध कारण प्रस्तुत नही कर सकते हैं, उन्हे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने पर प्रादेशिक सेना की सेवा से सेवामुक्त किया जा सकता है।''
5. **अतः अब**, आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है की आप, यदि कोई बचाव पक्ष हो, तो लिखित रूप में प्रस्तुत करें कि प्रादेशिक सेना नियम 1948 (संशोधित संस्करण 1964) के नियम 14(डी) के अनुसार आपको प्रादेशिक सेना की सेवा से सेवामुक्त क्यों न किया जाए।
6. यदि इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा की आपके पास प्रादेशिक सेना की सेवा से अपनी सेवामुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत करने हेतु कोई कारण नहीं है तथा यथोचित कार्रवाई एकपक्षीय रूप से की जाएगी।

महुआ मोइत्रा दौरे से पहले सूचित करें

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वे नादिया जिले के अपने दौरे से एक दिन पहले वहां के जिला प्रशासन को सूचित कर दें, ताकि वे प्रोटोकॉल के अनुसार आवास सहित जरूरी इंतजाम कर सकें।

शीर्ष अदालत ने मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मोइत्रा ने जिला प्रशासन के 1 सितंबर के एक सर्कुलर का मुद्दा उठाया था, जिसमें सांसदों और विधायकों से कहा गया था कि वे अपने प्रस्तावित दौरे से कम से कम तीन-चार दिन पहले सूचना दें, ताकि प्रशासन उचित इंतजाम कर सके।

भाजपा नेता रोजाना मुलाकात करेंगे

रणनीति

- भाजपा मुख्यालय में शुरू हो रही संवाद करने की नई व्यवस्था

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भाजपा मुख्यालय में आने वाले पार्टी कार्यकर्ता अब आसानी से वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकेंगे।

पार्टी संवाद की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिसमें महासचिव समेत प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारी मुख्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं से नियत दिनों में मुलाकात कर अपने सुझाव देने के साथ समस्याओं के समाधान भी हासिल कर सकेंगे। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार के दिनों में लागू रहेगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालने के बाद लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते है। चूंकि अध्यक्ष के तमाम प्रवास कार्यक्रमों व बैठकों की व्यस्तता को देखते हुए पार्टी ने अब महासचिवों समेत अन्य पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की नियमित व्यवस्था शुरू की है। अध्यक्ष भी समय समय पर कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहेंगे। सूत्रों के अनुसार नई व्यवस्था में सोमवार को महासचिव विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी, मंगलवार को सुनील बंसल और गजेंद्र पटेल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बुधवार को विप्लव कुमार देव और संजय भाटिया, जबकि गुरुवार को स्मृति ईरानी और मुख्तार प्रभारी तरुण चुग मुलाकात के लिए उपलब्ध रहेंगे। शुक्रवार को सतीश पूनिया के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। यह नेता कार्यकर्ताओं के लिए सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक उपलब्ध रहेंगे।

इनके अलावा,राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों की भी मुलाकात व संवाद की जिम्मेदारी तय की गई है। केंद्रीय मंत्रियों के कार्यकर्ताओं से मिलने की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। गौरतलब है कि पहले भी पार्टी कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लेकिन अब दिन के हिसाब से जिम्मेदारी तय की जा रही है।

जनता का धन बर्बाद : चिदंबरम

नई दिल्ली,एजेंसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर को संभालने के तरीकों को लेकर आलोचना की। उन्होंने मतदाता सूची से लाखों नाम सिस्टम से हटाए जाने पर सवाल उठाया और जवाबदेही की मांग की।

एक्स पर किए पोस्ट में चिदंबरम ने कहा कि विवादित एसआईआर को लेकर सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस गलत तरीके से लागू की गई प्रक्रिया में जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। इस दोहरे खर्च का पूरा पैसा ज्ञानेश कुमार से लेना चाहिए।

साइबर सेल ने हनी सिंह से दो घंटे तक पूछताछ की

मुंबई, एजेंसी। गायक-रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह, जिन्हें 'यो यो हनी सिंह' के नाम से जाना जाता है, शुक्रवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए। यह मामला एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। उन्होंने दो घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद गायक महाराष्ट्र साइबर सेल के कार्यालय से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकले। इससे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल ने यो यो हनी सिंह की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 22 अक्तूबर को पेश होने की अनुमति मांगी थी।



महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें समन भेजा गया था। महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के अनुसार, तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद हनी सिंह पेश नहीं हुए।

निर्वाचितों के खिलाफ भी शिकायत का अधिकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आम नागरिक, चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने वाले निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि 'दंड प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) की धारा 195 के तहत लगाई गई पाबंदियां, ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने के रास्ते में नहीं आएंगी। सीआरपीसी की धारा 195 अदालतों को कुछ खास अपराधों का सीधे संज्ञान लेने से रोकती है, जब तक कि किसी अधिकृत लोक सेवक या संबंधित अदालत द्वारा औपचारिक रूप से लिखित शिकायत दर्ज न कराई जाए। पीठ ने कहा कि अगर किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज की जाती है या उसमें बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो देश के कानून सक्षम मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देते हैं कि वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकें।

टीएमसी के विरोधी गुटों की सुनवाई 30 को होगी : ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विरोध गुटों के मामले पर चुनाव आयोग 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। यह मामला पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा है।

Branded
T.SHIRT SALE
MEN, WOMEN & KIDS
upto 60% off
Pooja Offer
Till 20 Oct.
Introducing huge range of Shorts & Lowers
By Economy Sales: 9212758425
ARROW PARK AVENUE ColorPlus SMART CASUALS Reebok Levi's
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 330/टीएल/2026 दिनांक : 14.10.2026

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (जिसे इसके पश्चात् 'आरटीएम' कहा गया है) मोड के अधीन 'मंदसौर पीएस पर आईई उत्पादन परियोजनाओं में संयोजकता प्रदान करने के लिए परियोजना' (जिसे इसके पश्चात 'परियोजना' कहा गया है) शामिल करने हेतु पीएमटीएल को मौजूदा आरटीएम परिषण अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 16 के अधीन आवेदन किया गया है। उस परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए परिषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परिषण योजना का कार्यक्षेत्र	मद का विवरण	कार्यान्वयन समय–सीमा	कुल अनुमानित लागत (रु. करोड़)
क.	**मैसर्स ईसक्ला क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (2200001037) के 200 मेगावाट आरएचजीएस के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 220 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन**			
1.	मैसर्स ईसक्ला क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (2200001037) के 200 मेगावाट आरएचजीएस के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 220 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन	220 केवी लाइन बे–1 नं. (सेक– I)	30.06.2028 (नोट क का संदर्भ लें)	5.73
ख.	**मैसर्स एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. (2200000824) के 600 मेगावाट आरपीपी के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 400 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन**			
2.	मैसर्स एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. (2200000824) के 600 मेगावाट आरपीपी के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 400 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन	400 केवी लाइन बे (मौजूदा हाफ डायमीटर में) – 1 नं.	31.12.2029 (नोट ख का संदर्भ लें)	11.93
	कुल अनुमानित लागत:			**17.66 (मई'25 कीमत स्तर पर (पीएल))**

नोट:

क. कार्यान्वयन समय–सीमा को हैक्सा क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. की उसकी 200 मेगावाट आरएचजीएस (आवेदन सं. 2200001037) के लिए संयोजकता के अंतिम अनुदान हेतु सूचना के अनुसार संयोजकता की आरंभ तारीख के साथ संरेखित किया गया है।

ख. कार्यान्वयन समय–सीमा को एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. की उसकी 600 मेगावाट आरपीपी (आवेदन सं. 2200000824) के लिए संयोजकता के अंतिम अनुदान हेतु सूचना के अनुसार संयोजकता की आरंभ तारीख के साथ संरेखित किया गया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 24.6.2026 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 330/टीएल/2026 में दिनांक 14.10.2026 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबध एव अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निधारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **22.10.2026** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **23.10.2026** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्ववियेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुरी)
सचिव

विज्ञा. सं. 2/2026-27

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007
टेली. - 011-27402400, 27667102, फैक्स नं. - 011-27666549
वेबसाइट: www.vpci.org.in

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रायोजित परियोजना **नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज** के तहत वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007 में एक वर्ष की अवधि (समेकित वेतन पर) के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद	पद की सं.	पात्रता/योग्यता	ऊपरी आयु सीमा	समेकित मासिक वेतन
कंसलटेंट (नन–मेडिकल)	01	सेवानिवृत्ति के समय पीबी2: रु. 9300-34800 + जीपी रु. 5400 और अधिक में भुगतान पानेवाले किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ और प्रशासन, वित्त और लेखा मामलों में कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव रखनेवाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी।	70 वर्ष	रु. 60,000/-
स्टेटिस्टिशियन	01	सांख्यिकी में मास्टर्स डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल के कार्य अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातक।	30 वर्ष	रु. 31,000/-
काउंसलर	07	**अनिवार्य:** I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातक। II. व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी बोलने/लिखने में निपुण होना चाहिए। III. चुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। **वांछनीय:** तंबाकू से संबंधित कार्य में अनुभव के साथ मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर।	35 वर्ष	रु. 25,000/-

योग्य उम्मीदवार विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से **21 दिनों** के भीतर डिप्टी रजिस्ट्रार, वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007 के कार्यालय में प्रमाण पत्रों/प्रशंसापत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: **www.vpci.org.in/vacancies** देखें। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन आवश्यक हैं। लिफाफे पर **"नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विस (एनटीक्यूएलएस) के पद हेतु आवेदन"** लिखा होना चाहिए।

सीबीसी 17169/11/0003/2627 निदेशक

जब तक मजबूत होना ही आपके पास एकमात्र विकल्प न हो, तब तक आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता।

– बाब मार्ले

कसौटी पर भरोसा

अब यह एक तरह से साफ हो चुका है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के मसले पर निर्वाचन आयोग अपने रुख की वजह से चौतरफा सवालों से घिरा है और इसका कोई हल निकालने को लेकर सरकार के भीतर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। एक ओर निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एसआइआर की गड़बड़ियां सामने आने के बावजूद इस समूची प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं दिखते हैं, दूसरी ओर सरकार समाधान तलाशने के बजाय इस मुद्दे पर आंदोलन और विरोध के स्वर को कमजोर करने के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी जब कांग्रेस ने प्रदर्शन का आह्वान किया, तो वहां फिर से पुलिस का सख्त रवैया ही सामने आया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हैरानी की बात यह है कि देश में एसआइआर के मसले पर उठे विरोध का दायरा और फैलता जा रहा है, वहीं अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस हल सामने आता नहीं दिख रहा।

विचित्र यह भी है कि शीर्ष अदालत इस मामले में कोई स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाने के बजाय शायद सिर्फ नोटिस जारी करके यह मान लेना चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदालत में एसआइआर से संबंधित मामले लंबित हैं और यह कहा जा सकता है कि फैसला आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक विरोध का मुद्दा बनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इससे संबंधित कोई स्पष्ट रेखा खींचना और जल्दी फैसला देना जरूरी तथा प्राथमिक दायित्व नहीं लग रहा। सही है कि एसआइआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस की सख्ती पर अदालत ने नाराजगी जताई है। मगर पिछले कुछ समय से अनेक मामलों में यह लगातार देखा गया है कि अदालत की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया आकर्षक और संवेदनशील होती हैं, लेकिन वे निर्णय या आदेशों में नहीं झलकतीं। इससे विचित्र क्या होगा कि पश्चिम बंगाल में जब एसआइआर में बाहर किए गए मतदाताओं के पात्र होने और उन्हें चुनाव में मताधिकार से वंचित किए जाने का सवाल उठा, तो उस पर भी अदालत ने कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया। यह बेवजह नहीं है कि सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों में जमीन पर उसका कोई ठोस असर नहीं दिखता।

लोकतंत्र का जीवन तभी तक कायम है, जब तक नागरिकों के वोट देने के अधिकार की हर हाल में रक्षा की जाती है। मगर ऐसा लगता है, सरकार ने मान लिया है कि एसआइआर में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रही विपक्षी पार्टियां पुलिस की ओर से व्यापक अवरोध खड़े किए जाने और मांगों की अनदेखी करने से थक कर शांत हो जाएंगी। मगर विपक्षी दलों की ओर से अलग-अलग स्वरूप में विरोध जारी रखने या सिर्फ कुछ दिनों का विराम लेने को लेकर अब तक जो संकेत उभरे हैं, उससे साफ है कि लोगों के बीच असंतोष कम नहीं हुआ है। इसका संकेत शुक्रवार को भी सामने आया जब एसआइआर को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस सबके बावजूद सरकार ने एक तरह से उदासीनता का रवैया अख्तियार किया हुआ है। ऐसे में आम जनता का भरोसा कायम रहे, इसलिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को फौरी निर्देशों से आगे बढ़ कर स्पष्ट और त्वरित कार्रवाई का रास्ता तैयार करना चाहिए।

खेल का हित

एशियाई खेलों में एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपेक्षित पदक नहीं मिले, तो खेल मंत्रालय समीक्षा बैठक करता है। पिछली एशियाई खेलों के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में कमी निश्चित रूप से चिंता का मामला है। मगर क्या कभी उन लोगों की जवाबदेही भी तय होती है, जिनके हाथों में खेलों का प्रशासन है? खिलाड़ियों से पदक जीतने की अपेक्षा की जाती है, तो क्या खेल संगठनों के पदाधिकारियों से नतीजों का हिसाब मांगा जाता है? देश के अनेक खेल संघों में ऐसे लोग शीर्ष पदों पर काबिज हैं, जिनकी खेलों में कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। प्रशासनिक अनुभव जरूरी है, लेकिन खेल की बारीकियों, खिलाड़ियों की समस्याओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों की समझ भी नेतृत्व की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। विडंबना है कि खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े फैसले लेने वाली व्यवस्था में कई बार उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। सवाल है कि पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा और जवाबदेही तय करने का प्रभावी तंत्र क्यों नहीं है? जब पद प्रतिष्ठा व प्रभाव का माध्यम बन जाएं, तो खेल हित का पीछे छूटना लाजिमी है।

दूसरी बड़ी चुनौती प्रतिभाओं की खोज है। गांवों और छोटे कस्बों में अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो उचित प्रशिक्षण, उपकरण और अवसर मिलने पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर सकते हैं। मगर प्रतिभाओं की पहचान अगर संयोग पर निर्भर हो, तो यह व्यवस्था की विफलता है। कितने ही संभावित और बेहतरीन खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में खेल छोड़ देते हैं। कितनों को केवल इसलिए अवसर नहीं मिलता कि उनके पास उच्च संपर्क नहीं हैं। प्रतिभा को शुरुआती स्तर पर पहचानने और उसे निखारने की व्यवस्थित पहल के बिना पदक बढ़ाने के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे। खेलों में सुधार के लिए बजट और घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा। खेल संगठनों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रतिभा खोज की जवाबदेह व्यवस्था बनानी होगी। मंत्रालय को समीक्षा बैठकों के निष्कर्षों पर कार्रवाई का हिसाब भी सार्वजनिक करना चाहिए। जब तक खेल व्यवस्था में खिलाड़ी सर्वोपरि नहीं होंगे, तब तक पदक की महत्त्वाकांक्षा और उपलब्धियों के बीच की दूरी बनी रहेगी।

विकास बनाम सामाजिक सुरक्षा



भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है, लेकिन ईपीएफओ विस्तार के साथ योजनाओं की पहुंच, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक पेंशन के तंत्र को मजबूत करना जरूरी है।

जयंतीलाल भंडारी

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर सौ करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच गया है और उन्हें किसी न किसी रूप में इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन आम आदमी और असंगठित क्षेत्र के विशाल श्रमबल के लिए यह कवच अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ केवल किसी योजना में पंजीकरण नहीं, बल्कि बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना और आय में अचानक आई कमी के समय सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी है। इस कसौटी पर भारत को अभी लंबी दूरी तय करनी है।

देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का करीब 1.9 फीसद है। नतीजतन, गंभीर बीमारी का इलाज परिवारों की बचत पर भारी पड़ता है और कई बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी नकद सहायता की राशि भी बढ़ती महंगाई के मुकाबले अपर्याप्त है। दूसरी ओर, श्रमबल का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक, देश में करीब 61.6 करोड़ का श्रमबल है, जिसमें लगभग 87 फीसद हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है। दैनिक वेतनभोगी, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार की अनिश्चितता के साथ पेंशन, भविष्य निधि और बीमा जैसी दीर्घकालिक सुरक्षा का अभाव है।

'गिग और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था' ने रोजगार के नए अवसर जरूर पैदा किए हैं, लेकिन यहां भी स्थायी आय, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा और पेंशन का ढांचा अभी कमजोर है। ठेका और आउटसोर्सिंग की बढ़ती प्रवृत्ति ने नौकरी की स्थिरता को और प्रभावित किया है। भारत सामाजिक सुरक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसद खर्च करता है, जबकि वैश्विक औसत इससे कहीं अधिक है। सीमित सार्वजनिक व्यय का असर योजनाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के बीच वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक निर्भरता भी बढ़ रही है। डिजिटल विभाजन, दस्तावेजी जटिलता और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ई-श्रम जैसे पोर्टल के बावजूद अनेक पात्र लोग योजनाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पा रहे हैं।

इस परिदृश्य में संगठित क्षेत्र के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा बढ़ाना महत्त्वपूर्ण कदम है। 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने से बड़ी संख्या में नए कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आएंगे। सितंबर 2014 के बाद यह सीमा में पहला बड़ा संशोधन है। दरअसल, कई राज्यों में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन पहले ही 15,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका था। ऐसे में पुरानी सीमा के कारण अनेक कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा से बाहर रह जाते थे।

नई सीमा से करीब 51 लाख नए कर्मचारियों के अनिवार्य ईपीएफओ के दायरे में आने की उम्मीद है। इसका लाभ केवल भविष्य निधि में बचत तक सीमित नहीं है। कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का योगदान और पेंशन तथा बीमा से जुड़े प्रावधान मिलकर एक व्यापक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। ईपीएफ में नियमित योगदान से सेवानिवृत्ति के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला कोष तैयार होता है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाला लाभ वृद्धावस्था में आय का आधार बन सकता है, जबकि कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना परिवार को कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहारा देती है।



> विकसित भारत का लक्ष्य केवल ऊंची जीडीपी या बड़े निवेश से हासिल नहीं होगा। उसकी असली कसौटी यह होगी कि बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी और वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में कोई नागरिक आर्थिक असुरक्षा के कारण सम्मानजनक जीवन से वंचित न हो। इसलिए संगठित क्षेत्र के सुधारों के साथ असंगठित और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को आकर्षक बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाना और सामाजिक पेंशन को महंगाई से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा खर्च को बोझ नहीं, उत्पादक निवेश मानना होगा। तभी विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

हालांकि इस बदलाव के कुछ तात्कालिक असर भी हैं। पंद्रह हजार से पच्चीस हजार रुपए के वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारियों की हाथ में मिलने वाली आय पीएफ कटौती बढ़ने से कुछ कम हो सकती है। दूसरी ओर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कपड़ा, खुदरा और लाजिस्टिक्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर नियोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा। सरकार पर भी पेंशन संबंधी दायित्व बढ़ सकते हैं। फिर भी श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने और घरेलू बचत में वृद्धि से इसके व्यापक आर्थिक लाभ हो सकते हैं। ईपीएफओ के बढ़े हुए कोष का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और विकास से जुड़े साधनों में होने से अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक पूंजी भी मिलती है।

इसके अलावा, अटल पेंशन योजना, पीएम-किसान, पीएम-पोषण और 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना जैसी पहल भी सुरक्षा कवच को विस्तार देती हैं। मगर योजनाओं की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। असली चुनौती यह है कि जरूरतमंद व्यक्ति तक सही समय पर सही लाभ पहुंचे। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल को सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत खिड़की बनाना उपयोगी होगा, जहां पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं की जानकारी तथा आवेदन की सुविधा एक जगह मिले। संयुक्त सेवा केंद्र और पंचायतों के जरिए आसान पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय भाषाओं में प्रचार, श्रव्य-दृश्य सामग्री और जनजागरूकता अभियान चलाने होंगे। कागजी कार्रवाई न्यूनतम कर सीधे लाभ अंतरण को प्रभावी बनाना होगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए ऐसी सामाजिक सुरक्षा जरूरी है, जो राज्य बदलने पर भी बाधित न हो।

यह भी जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा नीतियों में महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों और मौसमी श्रमिकों की अलग जरूरतों को समझा जाए। महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, सुरक्षित कार्यस्थल और आय सुरक्षा के प्रावधान मजबूत हों। निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोषों का उपयोग पारदर्शी बनाया जाए और पंजीकरण तथा लाभ लेने की प्रक्रिया सरल हो। छोटे शहरों और गांवों में बैंकिंग, इंटरनेट और पहचान संबंधी अड़चनों को दूर किए बिना डिजिटल व्यवस्था पूरी तरह कारगर नहीं हो सकती। सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण भी होना चाहिए, ताकि यह पता चले कि योजनाओं का लाभ वास्तव में किस वर्ग तक पहुंच रहा है और कौन अब भी छूट गया है। यही असली परीक्षा है।

असंगठित श्रमिकों के लिए योगदान आधारित पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना सुरक्षा का लचीला स्वरूप बनाना समय की जरूरत है। नीति आयोग ने भी गिग अर्थव्यवस्था के विस्तार के बीच सामाजिक सुरक्षा के नए ढांचे की आवश्यकता रेखांकित की है। अगस्त 2021 में शुरू ई-श्रम पोर्टल पर अगस्त 2026 तक 31.89 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। अब प्राथमिकता पंजीकरण से आगे बढ़कर वास्तविक लाभ पहुंचाने की होनी चाहिए।

विकसित भारत का लक्ष्य केवल ऊंची जीडीपी या बड़े निवेश से हासिल नहीं होगा। उसकी असली कसौटी यह होगी कि बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी और वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में कोई नागरिक आर्थिक असुरक्षा के कारण सम्मानजनक जीवन से वंचित न हो। इसलिए संगठित क्षेत्र के सुधारों के साथ असंगठित और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को आकर्षक बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाना और सामाजिक पेंशन को महंगाई से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा खर्च को बोझ नहीं, उत्पादक निवेश मानना होगा। तभी विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

दिखावे की खुशी

राकेश खुडिया

कभी घर में कोई खुशी आती थी, तो सबसे पहले घर के भीतर के लोग उसे जीते थे। मिठाई बंटती थी, पड़ोसी बुलाए जाते थे, रिश्तेदारों को खबर दी जाती थी और कई बार खुशी की सबसे बड़ी निशानी यही होती थी कि देर तक घर में हंसी सुनाई देती थी। अब खुशी आती है, तो उसके साथ एक दूसरा सवाल भी आता है- इसे कितने लोगों को दिखाया जाए? जन्मदिन का केक काटने से पहले कैमरा तैयार होता है, यात्रा शुरू होने से पहले तस्वीर खिंचती है और भोजन का स्वाद लेने से पहले उसकी तस्वीर दुनिया तक पहुंच जाती है।

इस बदलाव के पीछे आदमी की वह मनोवैज्ञानिक जरूरत भी काम करती है, जिसमें वह चाहता है कि उसकी खुशी को दूसरे देखें, पहचानें और स्वीकार करें। पहले किसी उपलब्धि पर परिवार की आंखों में चमक काफी होती थी, अब कई बार लाइक, टिप्पणी और बधाइयों की संख्या भी खुशी का हिस्सा बन जाती है। खुशी का निजी अनुभव धीरे-धीरे सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल रहा है। सोशल मीडिया ने इस बदलाव को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल का कैमरा सामने आया और निजी जीवन का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हो गया। किस शहर में गए, क्या खाया, किससे मिले, क्या खरीदा, किस अवसर पर क्या पहना- जीवन की छोटी-बड़ी घटनाएं अब तस्वीरों और वीडियो के रूप में दर्ज होने लगी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि आदमी अपनी यादें संभालकर रखे या अपने प्रियजनों के साथ साझा करे। समस्या तब शुरू होती है, जब अनुभव से ज्यादा महत्त्व उसके प्रदर्शन को मिलने लगे।

कई बार किसी पर्यटन स्थल पर पहुंचने वाला परिवार कुछ देर प्रकृति को देखने के बजाय तस्वीरों के लिए सही जगह तलाशता रहता है। बच्चे झील, पहाड़ या समुद्र को देखने से पहले कैमरे की ओर देखते हैं। भोजन सामने आता है, तो पहला निवाला लेने से पहले उसकी तस्वीर खींची जाती है। समारोह में लोग बातचीत से अधिक इस चिंता में दिखाई देते हैं कि कौन-सा दृश्य कैमरे में अच्छा आएगा। धीरे-धीरे अनुभव का एक हिस्सा कैमरे के लिए अभिनय करने लगता है। इसका असर खुशी की प्रकृति पर भी पड़ता है। जब किसी अनुभव को लगातार इस नजर से देखा जाता है कि दूसरे उसे कैसे देखेंगे, तो उस अनुभव में सहजता कम हो सकती है। आदमी यात्रा पर है, लेकिन उसके मन में यह भी चल रहा है कि कौन-सी तस्वीर डाली जाए। जन्मदिन मन रहा है, लेकिन ध्यान इस बात पर भी है कि कितनी प्रतिक्रियाएं आएंगी। उपलब्धि मिली है, मगर संतोष के साथ यह अपेक्षा जुड़ जाती है कि लोग उसे कितना बड़ा मानते हैं।

यहां तुलना भी धीरे-धीरे जीवन में प्रवेश करती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां हमेशा पूरी दिखाई देती हैं। किसी का सुंदर घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी का महंगा भोजन, किसी की सफलता और किसी का शानदार पारिवारिक समारोह सामने आता रहता है। आदमी अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना दूसरे की चुनी हुई तस्वीरों से करने लगता है। वह यह भूल जाता है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली खुशी के पीछे का पूरा जीवन उसे दिखाई नहीं देता। इस तुलना से एक अजीब तरह का दबाव पैदा होता है। अगर दूसरे लोग हर अवसर को खास बना कर दिखा रहे हैं, तो अपने सामान्य जीवन को लेकर हीनता महसूस होने लगती है। जन्मदिन साधारण तरीके से मनाना कम अच्छा लगने लगता है। छोटी यात्रा पर्याप्त नहीं लगती। सामान्य भोजन भी तब तक खास नहीं लगता, जब तक उसे किसी विशेष अंदाज में प्रस्तुत न किया जाए। जीवन जीने के लिए नहीं, दिखाने के लिए सजाया जाने लगता है।

बच्चों पर इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। उनके लिए खुशी का अर्थ धीरे-धीरे उस प्रतिक्रिया से जुड़ सकता है जो किसी तस्वीर या वीडियो को मिलती है। अगर कोई तस्वीर अधिक पसंद की गई तो खुशी, कम प्रतिक्रिया मिली तो निराशा। इससे बाहरी स्वीकृति का महत्त्व बढ़ता जाता है। बचपन में मिलने वाली सहज खुशी- बारिश में भीगना, खेलना, मिट्टी में बैठना या बिना किसी कारण हंसना- किसी दर्शक की जरूरत नहीं रखती थी। परिवार के भीतर भी इस प्रवृत्ति का एक दूसरा असर दिखाई देता है। कई बार लोग साथ बैठे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने फोन में व्यस्त होता है। बातचीत के बीच तस्वीरें ली जाती हैं और तस्वीर लेने के बाद बातचीत फिर शुरू होने से पहले कोई दूसरी स्क्रीन सामने आ जाती है। एक ही परिवार में मौजूद लोग एक-दूसरे के जीवन के दर्शक तो बन रहे हैं, लेकिन सहभागी कम होते जा रहे हैं। फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि खुशी साझा करना गलत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी उपलब्धियों, यात्राओं और उत्सवों को दूसरों के साथ बांटना उसके स्वभाव का हिस्सा है। तकनीक ने दूर बैठे लोगों को भी किसी खुशी में शामिल होने का अवसर दिया है। समस्या साझा करने में नहीं, बल्कि उस स्थिति में है, जब साझा करना ही खुशी का उद्देश्य बन जाए।

आज जरूरत खुशी और प्रदर्शन के बीच अंतर समझने की है। तस्वीरें खींची जाएं, यादें साझा की जाएं, उपलब्धियों की खुशी बताई जाए, लेकिन कभी-कभी मोबाइल को किनारे रखकर उस क्षण को वैसे ही जीने की आदत भी बची रहनी चाहिए। आखिर खुशी का मूल्य इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि उसे कितने लोगों ने देखा। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जिनके कोई दर्शक न हों। जहां हंसी कैमरे के लिए न हो, यात्रा पोस्ट के लिए न हो और उत्सव प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में न रुके। शायद तब आदमी फिर समझ पाएगा कि खुशी दिखाई देने वाली चीज नहीं, महसूस होने वाला अनुभव है। जो खुशी दूसरों की नजर से प्रमाणित होने की जरूरत न रखे, वही सबसे अधिक अपनी होती है।

दुनिया मेरे आगे

> मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी उपलब्धियों, यात्राओं और उत्सवों को दूसरों के साथ बांटना उसके स्वभाव का हिस्सा है। तकनीक ने दूर बैठे लोगों को भी किसी खुशी में शामिल होने का अवसर दिया है। समस्या साझा करने में नहीं, बल्कि उस स्थिति में है, जब साझा करना ही खुशी का उद्देश्य बन जाए।

अपनों में बेगाने



माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी संतान का भविष्य संवारने और घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन उम्र ढलने पर अक्सर उसी घर में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। जिनकी खुशियों के लिए उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया, उन्हीं के बीच अकेलापन उनकी नियति बन जाता है। आधुनिकता और भौतिक सुखों की दौड़ में रिश्तों की संवेदनशीलता कमजोर पड़ रही है। संयुक्त परिवारों के बिखरने से बुजुर्गों का भावनात्मक सहारा भी छिन रहा है। आर्थिक रूप से निर्भर वृद्धों की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाती है। वृद्धाश्रम उनके लिए आश्रय हो सकता है, लेकिन अपनों के स्नेह का विकल्प नहीं। समाज को समझना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं, हमारे अनुभव और संस्कारों की धरोहर हैं। उनकी देखभाल केवल संतान का दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदना की कसौटी भी है। आखिर जिस पीढ़ी ने हमें चलना सिखाया, उसे जीवन की संध्या में अकेला छोड़ देना कैसी प्रगति है? रिश्तों की असली समृद्धि तभी है, जब हमारे घरों में बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिले।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी शरीफ, पटना

अस्मिता का प्रश्न

भारत को केवल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार समझना भूल होगी। भारतीय उपभोक्ता अपनी भावनाओं, अनुभवों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से भी संचालित होते हैं। अमेरिकी व्यापार नीति में शुल्क का दबाव हो या तकनीकी सौदों में अपने हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश, भारत के लिए अपनी आर्थिक स्वायत्तता और सुरक्षा से समझौता करना उचित नहीं होगा। एलन मस्क जैसे प्रभावशाली कारोबारी हों या अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के अन्य चेहरे, उनके बयानों और गतिविधियों का आकलन भारत के हितों के संदर्भ में होना चाहिए। जेडी वेंस से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियों और भारतीयों को लेकर की गई बयानबाजी के बीच यह जरूरी है कि देश अपनी अस्मिता और हितों के प्रति सजग रहे। भारत के आंतरिक मतभेदों को बाहरी हितों के लिए इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश से सावधान रहना होगा। भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि स्वाभिमान और संप्रभुता वाला राष्ट्र है।

– विवेक मिश्रा, खंडवा, मप्र

लोकतंत्र की राह

जब संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय किसी देश में नागरिक अधिकारों के हनन पर चिंता जताता है, तो उसे केवल आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहकर खारिज करना उचित नहीं। चीन, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देश भी ऐसे आरोपों को संप्रभुता का हवाला देकर नकारते रहे हैं। भारत को अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अलग उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। यदि विरोध के दौरान बड़े पैमाने पर हिरासत, प्रतिबंध और अभिव्यक्ति पर अंकुश की शिकायतें उठती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मानवाधिकार संगठनों के साथ टकराव और आलोचना के प्रति असहिष्णुता लोकतंत्र की छवि को कमजोर करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से अपेक्षा है कि वह असहमति को खतरा नहीं, बल्कि आत्मसुधार का अवसर माने। लोकतंत्र की रक्षा केवल चुनावों से नहीं, नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान से भी होती है।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

असहमति का सम्मान

'सख्ती की सीमा' (संपादकीय, 12 अक्तूबर) पढ़ा। सड़कों पर उठती आवाजें सरकार के लिए चुनौती नहीं, उसकी संवेदनशीलता और जवाबदेही की परीक्षा होती है। युवाओं के साथ कठोर व्यवहार और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की घटनाएं आत्ममंथन की मांग करती हैं। कानून-व्यवस्था सरकार का दायित्व है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की कीमत पर नहीं। जन-असंतोष को बलपूर्वक दबाने के बजाय संवाद से दूर करना लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। व्यापक विरोध के बावजूद सरकार यदि असंतोष के कारणों को समझने में विफल रहती है, तो यह उसकी राजनीतिक भूल होगी। लोकतंत्र में सरकार और संस्थाओं की विश्वसनीयता नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान से जुड़ी है। दमन के बजाय संवाद, संवेदनशीलता और जवाबदेही ही लोकतांत्रिक शासन की असली पहचान होनी चाहिए।

– बृज भूषण गोयल, लुधियाना



सत्रावसान को लेकर संसद 64 दिन की समय-सीमा का कीर्तिमान गढ़ चुकी है। अब तक किसी भी सत्र में केंद्र सरकार ने सत्रावसान के लिए इतना लंबा समय नहीं लिया है। शुक्रवार तक 18वें सत्र का अवसान नहीं हुआ है। अब तक के सबसे लंबे सत्र की समय-सीमा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देखने को मिली थी। रिकार्ड के मुताबिक मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चला था। इसके एक ही दिन बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।



'निष्ठावान' गुणी अति चातुर
'राजकाज' करिबे को आतुर

बात की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास से क्षमा मांगते हुए करते हैं। हर तरफ रामलीला के मंच सजे हैं, सरकार भी रामकाज करिबे को आतुर कहने का दावा करने वाली है। इसलिए इस बार रामलीला से ज्यादा समीचीन राजलीला ही है। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से सरकार को परेशान किया तो सरकार ने जंतर मंतर को शाप दिया, जा तू अदृश्य हो जा। अंकिता भंडारी मामले में विवादित नाम को कहा, सिक्किम उड़न छू हो जा। जनता को कहा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई लेकिन हमने मानसून सत्र को नहीं दी विदाई। अब तो शीतकालीन मामला आने वाला है। संसद सत्र मानसून से शरद तक जारी रह सकता है, लेकिन तुम लोग जून के बाद फिर अक्तूबर में प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। लोक-भवन के नए माननीय कह रहे, सत्ता पक्ष के लिए वोट जोड़ने का काम करूंगा। तुलसीदास से इस राजलीला को देखने की अपील करता बेबाक बोल।

बेबाक बोल

राजलीला

मुकेश भारद्वाज

'आह जो दिल से निकाली जाएगी
जख्म पर नमक की सुर्खी लाई जाएगी'

पूरे उत्तर भारत में रामलीला के मंच सजे हुए हैं। जो राम को लाए हैं वाले सत्ता पक्ष की जुबान फिसलती है...हंगामा मचता है। जुबान भी क्या करे। अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसका नाता होता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं जुबान उससे तालमेल करती है। जब कथनी और करनी में फर्क दिखने लगता है तो जुबान को भी राम और रावण का अंतर समझ नहीं आता है।

जब देवी के नौ रूपों की पूजा हो रही थी, वहीं अंकिता भंडारी की मां को हिरासत में लिया जा रहा था। बेटी की मौत के दुख से हलकान मां बड़ी उम्मीद से दिल्ली आई होगी। इसी दिल्ली से उन विवादित को राज-निवास भेजने का फैसला हुआ है जिनकी विशिष्ट भूमिका पर सवाल उठे हैं। माना अंकिता भंडारी के दोषियों के मामले में पुलिस और अदालत ने अपना काम कर दिया। लेकिन इस न्याय को अभी भी अधूरा माना गया। जब विशिष्ट विवादित को सत्ता-पक्ष और विशिष्टता प्रदान करे तो न्याय भी असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है?

अंकिता भंडारी की मां जहां धरने पर बैठी थीं, उसके कुछ ही दूरी पर रामलीला का मंचन हो रहा था। एक आम जनता ने देवी सीता पर शक जताया। श्रीराम ने परिवार से पहले अपने कर्तव्य को प्रधानता देते हुए कहा-प्रजा प्रथम। लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी राजलीला चलती है। जब भी कोई आरोप लगते हैं तो वह आरोपी से कुछ ऐसा ही व्यवहार करती है, मानो कह रही हो अपने तो अपने होते हैं, बाकी देश के लोग सपने होते हैं। वह हर आरोपी को अपना सा मानते हुए एलान करती है-परिवार प्रथम। अगर पिता पर आरोप लगेंगे तो पुत्र को टिकट दे देगी। पति पर आरोप लगेंगे तो पत्नी को पद सौंप दिया जाएगा। गोया पति-पत्नी और संतान कोई स्वतंत्र इकाई हो।

किसी भी मां-बाप के लिए सबसे बुरा होता है उनकी पहचान ऐसी संतान के नाम से होना, जिसे अपराधियों ने उनसे छीन लिया। एक स्त्री ऐसी ही पहचान के जख्म के साथ दिल्ली आई थी। लेकिन राजलीला के किरदारों ने उसके जख्म पर एक बोरी नमक छिड़क दिया। कहा, जा माई, दिल्ली के दवाखाने में जख्मों के लिए बस नमक की बोरियां ही हैं।

संविधान ने किसी राम-राज्य जैसी सुंदर अवधारणा के साथ ही राज-निवास की कल्पना की होगी। राज-निवास में स्थापित होने वाले प्रतिनिधि की ऐसी कल्पना की होगी जो न पक्ष से मतलब रखे और न विपक्ष से। वह राजा राम की तरह कह सके-प्रजा प्रथम। लेकिन इसके प्रतिनिधियों को सत्ता-निवास ही बना दिया गया। जनता को भ्रम में रखने के लिए राज-निवास का नाम लोक-निवास कर दिया गया। नाम बदलने के साथ ही काम भी बदल दिया गया। लोक को कहा, देखो पत्थर पर तुम्हारा ही नाम खुदा है। असल में प्रतिनिधि अब लोककाज नहीं बल्कि राजकाज करिबे को आतुर दिख रहा है।

बजरिए ओड़ीशा राज-निवास उर्फ लोक-भवन के एक और प्रतिनिधि को सुनते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आगे जो जिम्मेदारी मिली है उसे कैसे निभाएंगे। वे खुद को जनता नहीं भाजपा का ही कार्यकर्ता मान रहे हैं। इसलिए राजकाज करिबे की आतुरता में कह देते हैं, 'देखेंगे वहां क्या स्थिति है...वहां भी हम उसे जोड़ेंगे। वहां बीजेपी का मोर्चा है...अपना संगठन है... उसे एक्टिव करके बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे आए उस पर चिंता करेंगे।' पक्ष और विपक्ष के बीच के सेतु अब एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि सत्ता-पक्ष को वोट कैसे आए यही उनका मुख्य काम है। लोक-निवास में वे संविधान की रक्षा करने की शपथ वैसे ही भूल जाएंगे जैसे सत्ता पक्ष अपने लोगों के अपराध भूल जाता है। इसके समांतर वे सूबे में सत्ता पक्ष की सत्ता बरकरार रखने की शपथ लेंगे जिसे सोते वक्त भी याद रखेंगे। सत्ता पक्ष आधी रात को आकर कहेगा कि सूरज उगने के पहले हमारी सरकार बनवा दीजिए तो वे यह भी कर देंगे। कहते हैं कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। इसके साथ ही न्याय के संदर्भ में कहा जाता है कि वह मिलना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है कि उत्तराखंड के विशिष्ट ने आरोप नकारा और अदालत को मामले में संलिप्तता नहीं मिली। लेकिन उन पर इतना बड़ा आरोप तो लगा। ऐसे आरोपी के लिए आपको यह संवैधानिक पद ही मिला?

साख के साथ खिलवाड़ करने के पहले बीते समय को भी याद कीजिए। उस वक्त एक अखबार ने अपनी सुर्खी में बस इतना ही कहा था 'जेसिका को किसी ने नहीं मारा'। इस एक सुर्खी ने तत्कालीन राजनीति में तहलका मचा दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी को अपने कथित प्रिय पात्र से किनारा करना पड़ा था। कांग्रेस ने जिसे रुखसत किया उसका परिवार किस पार्टी के संरक्षण में अपना भविष्य संवार चुका है, यह दुनिया जानती है।

हमें इस सर्वमान्य तथ्य को भी झुठलाना पड़ेगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। अब इतिहास रुकता है, ठिठकता है और कहता है...भूतो न भविष्यति...जो न कल हुआ था, जिसके न भविष्य में होने की उम्मीद है, वह सब हमें आज देखना पड़ रहा है। वर्तमान अगर इतिहास से संवाद करना बंद कर देगा तो इतिहास के पन्ने भी आगे बढ़ने बंद हो जाएंगे।

त्योहारों के इस मौसम में शासन की छोटी इकाई एक महिला पुलिस वीडियो बना कर आंदोलनकारियों से कह रही है-तुम लोगों को जिनका भी इस्तीफा मांगना है, एक साथ मांग लो। तुम्हारे आंदोलन के कारण हमारी छुट्टियां रद्द हो रही हैं...। उस रीलवाली पुलिस से कोई पूछ सकता है, हम मांगेंगे इस्तीफा और मिल जाएगा...काहे मजलूमों पर मजे ले रही हैं। उस आम आदमी को रावण की तरह अट्टहास करने का मन किया होगा। लेकिन अट्टहास शक्तिशाली पक्ष करता है। दुर्बल पक्ष रोता है, सिसकता है। अंकिता भंडारी की मां कह सकती है, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो हम चले जाएंगे।

सत्ता पक्ष के अहंकार के खिलाफ दिल्ली में पूरे देश से लोग जुट रहे हैं। सत्ता के गलियारे वाली दिल्ली ठप पड़ी हुई है। सत्ता परेशान हुई और आंदोलनकारियों का इलाज खोजा। न रहेगा मैदा, न बनेंगे कचौड़ी और समोसा (उदाहरण थोड़ा अटपटा पर समसामयिक है)। तो सत्ता पक्ष ने जंतर मंतर को ही प्रदर्शनकारियों के लिए छूमंतर कर दिया। आदेश दिया जाओ बुराड़ी, जाओ शहादरा। जहां हम कभी नहीं जाते हैं वहां जाकर नारे लगाओ, इस्तीफा मांगो। जंगल में जनता रोएगी तो कौन देखेगा! इतनी दूर से लगाए नारों को कौन सुनेगा!

रामलीला के मंच इस राजलीला के किरदारों को देख कर हीन भावना के शिकार हो गए होंगे। दिल्ली से जंतर मंतर तो उत्तराखंड से कथित विशिष्ट विवादित को ही छूमंतर कर दिया। जनता को इससे बेहतर क्या इंसाफ मिलता? नासमझ जनता समझती क्यूं नहीं कि उसे उत्तराखंड से निकाल कर सिक्किम के लोक-भवन जाने की सजा सुनाई है। वहां वे उन आरोपों पर पश्चाताप करेंगे जो अंकिता भंडारी के संदर्भ में लगे हैं। आरोपी को अपराध वाली जगह से, जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों से छूमंतर की लीला के बाद क्या जनता जय-जयकार नहीं करेगी?



दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ली जातीं अंकिता भंडारी की मां। (फाइल चित्र)

राजपाट

अदल-बदल

उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। सूबे में आनेवाला विधानसभा चुनाव सपा से लेकर कांग्रेस तक के लिए अस्तित्व का मामला हो चुका है। इसलिए यहां राजनीतिक नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों से नाराजगी और दूसरे दलों में जाने पर फायदे के मुताबिक भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थामने की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी के भाजपा में शामिल होने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर, राज्यसभा में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाखुश भाजपा नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की अखिलेश यादव से मुलाकात ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में रिलायंस समूह के वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी धनराज नथवानी का समाजवादी पार्टी से निर्विरोध राज्यसभा में चुने जाने के बाद पार्टियों की अदला-बदली तेज हो गई है। कुछ माह पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमउद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा समेत कुछ और नेता सपा में शामिल हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं होन और पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने पर पाला बदलकर अपनी नाराजगी के साथ साथ हितों को भी साध रहे हैं।



जवाब की तलाश

सिक्किम के नए राज्यपाल का नाम घोषित होने के साथ ही उत्तराखंड भाजपा के नेता जवाब की तलाश में जुट गए हैं। दबे स्वर में प्रदेश स्तर के नेताओं का कहना है कि अगले कुछ माह में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंकिता भंडारी का मामला फिर गरमाएगा। इस घटना को लेकर राज्य के युवा पहले से आक्रोश में हैं। दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के कारण वैसे भी पूरे देश में सत्तारूढ़ दल पर कई सवाल उठ चुके हैं। हालांकि विवादित नाम अब तक जांच में सामने नहीं आया, मगर एक प्रश्न है कि इतने विवाद और सवाल के रहते उन्हें राज्यपाल क्यों बनाया गया जिसे खुद पार्टी ने प्रभारी पद से हटाने के बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम से बाहर कर दिया था। अब उनके राज्यपाल बनने के बाद जनता को क्या जवाब देंगे? यह तय है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहेगी।

पंजाब की ओर है नजर

पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान के बाद अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की वहां सीधी नजर है। इसका आगाज भी खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाना बनाया है और पंजाब को नशे का गढ़ बता दिया है। इस मामले में सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। इसी लाइन पर पहले से ही पंजाब की सरकार भाजपा के निशाने पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं में बेरोजगारी और नशे में डूबता पंजाब एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं वर्तमान में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी पंजाब के जरिए खुद को युवाओं से जोड़कर देख रही है। यह सूबा उसके अस्तित्व का मामला है।

अक्रियाशील

बिहार में एक कहावत है, 'हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत'। यानी मुद्दा कुछ हो, हमें बात उससे भटक कर करनी है। कुछ ऐसा ही हाल जद (एकी) का है। बाढ़ में आधा बिहार डूब गया। जमुई में किशोरी के उत्पीड़न की घटना पूरे देश में बहस का विषय बन गई। मुठभेड़ के कारण पुलिस भी सवालों के घेरे में है। प्रशांत किशोर शिक्षा व प्रशासन के मुद्दे पर चुनौती दे ही चुके हैं। पूरे देश की राजनीति एसआइआर के इर्द-गिर्द घूम रही है। लेकिन जद (एकी) राजनीति के नाम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से चलाई गई योजनाओं को याद कर रही है। बाढ़ से डूबे बिहार में 'फरक्का जलसंधि' का सहारा ले रही है। जंतर मंतर में मौजूद पार्टी कार्यालय का इस्तेमाल करके चंद युवा इनसे ज्यादा अपनी राजनीति ऐसे चमका गए हैं कि बच्चे-बच्चे को इनका नाम याद हो चुका है। अब मजाल है कि पार्टी के दिग्गज पदाधिकारी सोशल मीडिया पर एक शब्द भी बोल दें। आपके घर का इस्तेमाल करके चोर पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर दे, लेकिन आप पर कोई असर ही नहीं है। यह तो वही बात हो गई 'आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में।' पार्टी शायद भूल चुकी है कि बिहार में चल रही सरकार को चलाने में उसका भी उतना ही योगदान है जितना दूसरी पार्टी का है। अब जब बिहार में नीतीशे-कुमार भी नहीं हैं तो ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। ऐसे ही अक्रियाशील रही तो दिल्ली छोड़िए बिहार में भी पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा।

नेहा के बरक्स कन्हैया की खोज



राजनीतिक परिदृश्य में आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा की अति दृश्यता के बाद सोशल मीडिया पर लोग कन्हैया कुमार की खोज-खबर लेने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि मुख्यधारा की राजनीति में तात्कालिक लोकप्रियता मिलने के बाद नेहा बोरा का भी हाल कन्हैया कुमारा जैसा न हो। खास कर बांग्लादेश वाले संदर्भ के बाद कन्हैया कुमार के उन कथित नारों को याद दिलाया जा रहा है, जो शायद उन्होंने दिए भी नहीं थे, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि में बंधे रहे। कभी अपनी मुखरता के लिए प्रसिद्ध हो चुके कन्हैया कुमार की आवाज गुम सी हो गई है। लोगों का कहना है कि आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के कांग्रेस के करीब आने का असर यह हुआ है कि कन्हैया 'अंतर्धान' हो गए हैं। 'भारत जोड़ो यात्रा' में राहुल गांधी के साथ साये के साथ रहे ये नेता सुप्रीम कोर्ट तक निकाली गई यात्रा में 'आगे' दिखाई नहीं दिए। जब पूर्व छात्र नेता से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने खिसियाते हुए कहा, 'मेरी दाढ़ी पक गई है, अब मैं प्रदर्शनों में नहीं जाता हूं।' कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मंच पर नेहा बोरा को मिल रही तवज्जो के कारण वे नाराज हैं!

संकलन : मृणाल वल्लरी

पीर का पर्वत

लोकतंत्र के त्योहार से एक बार मतदाताओं के एक समूह को वंचित करने के निहितार्थ उन्हें आखिर क्यों समझ में आएगा जिसने अक्षय संवैधानिक अधिकारों के दैनिक उत्सव में अपने को आजीवन सराबोर रखा हो। लोक के हक से उसके टूटते तिलिस्म को तंत्र जब हल्के में लेकर मौलिक अधिकारों के हनन में मौन शक्ति प्रकट करती है तो निश्चय ही अचेतन अवस्था में भी आंदोलन की अग्नि प्रज्वलित हो जाना नैसर्गिक क्रिया है। एसआइआर के मार्मिक मर्म को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चुनाव आयोग ने आज तक धरातल पर इसलिए उतरने नहीं दिया क्योंकि इस गहन कार्य को पर्याप्त समय की दरिद्रता के दौर से सदैव गुजरना पड़ा है। बिहारी कहावत 'हड़बड़ी में विवाह कनपटी भर सिंदूर' के हालात ने पूरी एसआइआर की प्रक्रिया को अपने शिकंजे में लेकर इसकी मात्र खानापूरी की है। इसके कार्यान्वयन में आए गंभीर खोट को जब तक समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक पीर रूपी पर्वत का पिघलना बना रहेगा। हर सत्ता की यह फितूरी फितरत है कि वह अतीत को विस्मृत कर वर्तमान की उपेक्षा के उत्सव में सत्ता संपदा का मूल अंश अंगारे के हवाले कर देती है। काश, वह मतपत्र से अर्जित स्वर्णिम अवसर को मतदाता के मन को समझने में व्यय करती। देखना जरूरी है कि 27 लाख मतदाता सूची में दर्ज लाश की अतृप्त आस को न्याय के तराजू से कब इंसाफ मिल पाता है।

-अशोक कुमार, पटना।

इंकलाब की तपिश

छावनी में तब्दील होती दिल्ली को तारीख के पन्नों में दर्ज होने से पहले तारीख के हर पन्नों को कुरेदता मजमून है 'हर लाश चलनी चाहिए'। बहस उस दो मुहाने पर खड़ी है जहां से एक रास्ता उस तरफ जाता है जहां लाशें जिंदा होने का सबूत लिए खड़ी हैं तो दूसरे पर जम्हूरियत बेड़ियों में बेबस खड़ी है। मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने जेपी की संपूर्ण क्रांति देखी है तो सियासत की तलवार से लहू-लुहान जम्हूरियत भी देखी है। बेशक वह दौर जुल्म की तारीख लिख गया जो आज भी बतौर स्याह रात याद किया जाता है। छावनी के साये में दिल्ली को देख कर उस दौर का याद आना लाजिम है। यहीं से सवाल निकलता है कि क्या काले पन्नों पर लिखी गई वह दास्तां फिर से लिखी गई जिसकी गवाही देता साल 2026 का अक्तूबर खड़ा है। जवाब तलाशने के लिए उन सवालों को टटोलना होगा जिसे हमने नजरअंदाज किया है। कुछ वक्त से उठता धुआं तब और गहरा हो गया जब बंगाल के इंतेखाबी नतीजों ने चौंकने पर मजबूर कर दिया। घुसपैठियों की तलाश ने सूबे के तैंतीस लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को दर-दर भटकता छोड़ दिया। अब वह धुआं-धुआं न रहा बल्कि वहां से निकली चिंगारी की तपिश राजधानी की सड़कों को आगोश में ले चुकी है। अवाम और हुकूमत आमने-सामने क्या आई हर जर्रा इंकलाब की तपिश में जल उठा। मिजाज-ए-मौसम के साथ मुल्क की बदलती हवा में दुष्यंत कुमार की गजल का गूंजना लाजिम है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

आपके पत्र

आंदोलन की आवाज

बेबाक बोल ने दिल्ली की गतिविधियों को बखूबी दर्ज किया है। क्या खूब रहा माह-ए-अक्तूबर को याद करने का तरीका। दिल्ली में भी एक राह है जिसका नाम है-अगस्त क्रांति मार्ग। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी ऐतिहासिक मौके पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज इस जगह को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। मुंबई की इसी अगस्त क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की स्मृति में नई दिल्ली की एक प्रमुख सड़क का नाम 'अगस्त क्रांति मार्ग' रखा गया है। आजादी के बाद भी इस देश ने कई आंदोलन देखे हैं। जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुए आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता की नींव हिला दी थी। उस वक्त कांग्रेस के विरोध में जो जेन-जी सरीखे लोग थे आज वर्तमान के वरिष्ठ हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने लंबे समय तक देश की राजनीति से सवाल पूछे थे। वहीं अन्ना आंदोलन ने देश में ऐसा राजनीतिक परिवर्तन किया जिसका असर आज भी विपक्ष झेल रहा है। न तो सत्ता का व्यवहार नया है और न जनता की ऐसी प्रतिक्रिया पहली बार हुई है। यह समय सोशल मीडिया का है। हर एक गतिविधि कैमरे में कैद होकर पल भर में पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है। पक्ष-विपक्ष के अपने-अपने दृश्य हैं। दोनों तरफ जीत का दावा होता है। मौजूदा आंदोलन का चरित्र ऐसा है कि यह अन्ना आंदोलन की तरह उतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की सूरत में नहीं है। सत्ता-पक्ष भी सतर्क है। सत्ता और जनता का यह प्रतिरोधी रिश्ता अभी लंबा खिंचना है।

-अंकुर सिंह, नोएडा।

जनता की जरूरत

सत्ता की एक विडंबना यह भी है कि उसे पाने के लिए जनता की जरूरत होती है, लेकिन पा लेने के बाद कई बार जनता ही सबसे बड़ी असुविधा लगने लगती है। चुनाव के समय जो नागरिक जनार्दन होता है, वही सवाल पूछने लगे तो उसे विरोधी खेमे का हिस्सा मान लिया जाता है। दरअसल, सत्ता की असली ताकत विरोधियों को चुप कराने में नहीं, आलोचना सुनने के साहस में होती है। कुर्सी पर बैठना उपलब्धि है, लेकिन उस कुर्सी के योग्य बने रहना चरित्र, विवेक और संवेदनशीलता की मांग करता है। सत्ता मिलना जनादेश है, उसे जनहित में चलाना जिम्मेदारी। और जब सत्ता जिम्मेदारी भूल जाती है, तब जनता उसे याद दिलाने के लिए अगला जनादेश लेकर आती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाना भी जरूरी है। लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हीं सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तब भाषणों की जगह नीतियों, नारों की जगह नतीजों और आश्वासनों की जगह जवाबदेही की मांग होती है। जनता को यह जानने में देर नहीं लगती कि उसके सामने खड़ा नेतृत्व समस्याओं का समाधान करना चाहता है या केवल अपनी सत्ता बचाने में जुटा है। सत्ता का सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है, जब जनादेश को जवाबदेही के बजाय निरंकुशता का प्रमाणपत्र मान लिया जाता है। बहुमत का अर्थ यह नहीं कि सरकार को असहमति की आवाजें सुनाई न दें। लोकतंत्र में विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज जिम्मेदारियों का बोध कराने वाली संस्थाएं हैं।

-मीना, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

संपादकीय

खासगीकरणाची नांदी?

आयडीबीआयचे खासगीकरण हा केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर सार्वजनिक मालमत्तेच्या संकल्पनेचीही ती परीक्षा आहे. सरकारी मालकी म्हणजे सार्वजनिक हिताची हमी आणि खासगी मालकी म्हणजे कार्यक्षमतेची हमी असते का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे सरळ होकारार्थी देता येत नाहीत. आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जशी संबंधित कंपनीला विकण्याच्या निर्णयाकडे याच व्यापक संदर्भात पाहायला हवे. सुमारे ५२,८७८ कोटी रुपयांच्या या व्यवहाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे. सरकार याला बँकेची धोरणात्मक पुनर्रचना म्हणते. पण एखाद्या निर्णयाचे नाव काय ठेवले आहे, यापेक्षा त्यातून नेमके काय साध्य होणार आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असतो. आयडीबीआय बँकेच्या दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद या प्रमुख शहरांत एकूण १२० मालमत्ता आहेत. यापैकी सर्वाधिक ६८ मालमत्ता या मुंबईसारख्या जगातील एका प्रमुख अशा महागड्या शहरांत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता ज्या बँकेकडे आहेत, त्या मालमत्तांची विक्री अथवा अन्य प्रकारे वित्तीय व्यवहार करून भांडवल उभारता आले नसते का? २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांत बँकेचा वार्षिक निव्वळ नफा सुमारे २,४३९ कोटी रुपयांवरून ९,७१३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. म्हणजेच या कालावधीत नफ्यात जवळपास २९० टक्के वाढ झाली. नफ्यात असलेल्या बँकेची विक्री करण्यामागे पडद्यामागून एखाद्या मोठ्या खासगी उद्योगसमूहाचे हित साधायचे आहे का? माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा उलटे वळण तर घेतले जात नाही ना? आणि ते घेतले जात असेल तर त्यामागची भूमिका काय? आयडीबीआयची कहाणी केवळ एका बँकेच्या आर्थिक चढउतारांची नाही. औद्योगिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या संस्थेचे व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले. पुढे बुडीत कर्जे आणि आर्थिक नुकसानीमुळे तिला सरकारी मदतीची गरज भासली. एलआयसीने भांडवल दिले. आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर आता बहुसंख्य हिस्सा विकण्याचा निर्णय झाला. म्हणजे आधी सार्वजनिक पैशातून सावरणे आणि नंतर खासगी गुंतवणूकदाराच्या हाती नियंत्रण देणे, असा या प्रक्रियेचा प्रवास आहे. यात गैर काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचा लाभ कोणाला आणि कोणत्या अटींवर मिळतो, याचे उत्तरही सार्वजनिक असले पाहिजे. सरकारचा युक्तिवाद असा की, खासगी गुंतवणूकदारामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढेल, तंत्रज्ञानात सुधारणा होईल आणि सरकारी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी होईल. सरकारी मालकीच्या संस्था अकार्यक्षम आणि खासगी संस्था नेहमी कार्यक्षम असतात, असे कोणतेही सार्वत्रिक सूत्र नाही. प्रश्न खासगीकरण योग्य की अयोग्य, एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की, बँकेच्या कामगिरीचे मोजमाप कोणत्या निकषांवर केले जाणार? नफा, भागधारकांना मिळणारा परतावा आणि बाजारातील स्पर्धा हे निकष असतीलच. पण ग्रामीण कर्जपुरवठा, लघुउद्योगांना वित्तसाहाय्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सेवा आणि रोजगाराचे संरक्षण यांचे काय? आयडीबीआयचे खासगीकरण म्हणजे इतर सरकारी बँकांच्या विक्रीचा निर्णय झाला, असे नाही. तरी या व्यवहाराचा अनुभव पुढील धोरणावर प्रभाव टाकू शकतो. सरकारी बँका केवळ व्यावसायिक संस्था आहेत की आर्थिक विकासाच्या धोरणातील साधनेही आहेत, याविषयी स्पष्टता आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात परकीय भांडवल येणे चुकीचे नाही, पण नियंत्रण, ठेवीदारांचे हित, वित्तीय स्थैर्य आणि राष्ट्रीय आर्थिक प्राधान्ये यांबाबत नियामकांची जबाबदारी कमी होत नाही. मालकी खासगी झाली म्हणून सार्वजनिक हिताचे प्रश्न खासगी होत नाहीत. हा निर्णय झाला म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या ठेवी, कर्जे किंवा सेवा-अटी मालकी बदलताच आपोआप बदलत नाहीत. मात्र, पुढील काळात शाखा, सेवाशुल्क, कर्जवाटप आणि कर्मचारी धोरणात कोणते बदल होतात, यावर ग्राहकांचा अनुभव ठरेल. कर्मचारी संघटनांनी मूल्यांकन आणि रोजगार सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहेच. सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर कोणाच्या हितासाठी होतो, आर्थिक धोरणाची सामाजिक किंमत कोण मोजतो आणि सरकार आपल्या निर्णयांसाठी किती उत्तरदायी राहते, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. बँकेची मालकी बदलू शकते, पण सार्वजनिक हिताची जबाबदारी हस्तांतरित करता येत नाही.

प्रज्ञावंत भारत नोबेल पुरस्कारांत मागे का?

ज्या भारत भूमीत ज्ञानाला परमेश्वराचे स्थान दिले गेले, ज्या देशाच्या तरुण बुद्धिमत्तेने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला, त्याच भारताची नोबेल पुरस्कारांच्या व्यासपीठावरील उपस्थिती नगण्य का?



विजय बाविस्कर
समूह संपादक, लोकमत



जागतिक स्तरावर सर्वोच्च सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा झाली आणि मूलभूत संशोधनाचे सामर्थ्य त्यातून प्रखरतेने अधोरेखित झाले. २०२६ सालच्या शरीरक्रियाशास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल या संशोधकांना जाहीर झाला. ऑप्टोजेनेटिक्स तंत्रज्ञानाचा पाया घालणारे मूलभूत संशोधन केल्याबद्दल त्यांना जगाने मानाचा मुजरा केला आहे. मज्जासंस्थेतील गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया समजून घेण्यापासून ते काही गंभीर आजारांच्या संशोधनापर्यंत नवी दालने खुली करण्याचे काम या संशोधनाने केले आहे. भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार फ्रान्सिस हॅल्झेन यांना जाहीर झाला. न्यूट्रिनो हे अतिशय कमी परस्परसंवाद करणारे सूक्ष्म कण आहेत. अशा कणांचा शोध घेणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे हे संशोधन अथक मेहनतीचे असल्याने नोबेल पुरस्काराने त्यांचा गौरव झाला. औषधनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात मोलाचे संशोधन केल्याबद्दल हेन्री बी. कागान आणि केन्सो सोई यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल जाहीर झाला. हे त्यांचे संशोधन केवळ औषधनिर्मितीच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर जीवनाच्या उत्पत्तीचे कोडे सोडविण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. या सर्व नोबेल विजेत्यांवर जगभर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

नोबेल जाहीर होणे म्हणजे संशोधनातील सर्वोच्च शिखर गाठणे. त्यामागे अनेक वर्षांची जिज्ञासा, अपयशातून शिकण्याची तयारी, प्रयोगांसाठी घेतलेले अविश्रांत परिश्रम असतात. तेव्हाच अशी संशोधने साकारली जातात. हे नोबेल जाहीर होत असताना आणि वैश्विक पातळीवर संशोधकांचे कौतुक होत असताना एक प्रश्न मात्र राहून राहून मनात येतो, तो म्हणजे भारत हा तर बुद्धिमत्तेची खाण असलेला देश; तरीही नोबेल पुरस्कारात आपण मागे का? शतक लोटले तरी मूलभूत विज्ञान संशोधनाच्या क्षेत्रात एकही नोबेलधारी भारतीय शास्त्रज्ञ का उभा राहू शकला नाही?

विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर (साहित्य), मदर तेरेसा (शांतता-दुःखी व गरजू लोकांच्या सेवेसाठी), अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र), व्ही. एस. नायपॉल (साहित्य), कैलाश सत्यार्थी (बालमजुरीविरुद्ध व बालहक्कांसाठी केलेले कार्य), अभिजित बॅनर्जी (अर्थशास्त्र) आदींनी मिळवलेला हा सन्मान भारताच्या ज्ञानपरंपरेचा अभिमान जागवतो. मात्र, त्या अभिमानाच्या प्रकाशातच आपल्या उणिवांचे सावटही शोधायला लावतो आणि अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास प्रवृत्त करतो. एखाद्या राष्ट्राची खरी श्रीमंती केवळ तिजोरीतून नव्हे; तर बुद्धिमत्तेतून, ज्ञानसाधनेतून आणि जगाला दिलेल्या संशोधनात्मक योगदानातून मोजली जाते. भारतभूमीने शून्याची देणगी जगाला दिली, ज्या भूमीत ज्ञानाला परमेश्वराचे स्थान दिले गेले, ज्या देशाच्या तरुण बुद्धिमत्तेने जगातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला, त्याच भारताची नोबेल पुरस्कारांच्या व्यासपीठावरील उपस्थिती नगण्य का?

मूलभूत विज्ञानातील संशोधन वैश्विक पातळीवर गौरवान्वित होत असताना हीच आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे आणि त्यातून आपण सुधारणेच्या दिशेने पावले टाकणे गरजेचे आहे. भारतीय बुद्धिमत्तेचा पैस आणि देशातील संशोधन-विकासाला मिळणारे पाठबळ यांच्यातील दुराव पुन्हा एकदा यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.

मूलभूत विज्ञान संशोधनासाठी देशांतर्गत होणारा खर्च व त्यासाठी असणारी आर्थिक तरतूद हा एक कळीचा मुद्दा आहे. संशोधनासाठी लागणारी अत्याधुनिक उपकरणे, कुशल तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा, संशोधन साहाय्यक आणि दीर्घकालीन प्रकल्प यांना सातत्यपूर्ण आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. भारतातील मूलभूत विज्ञान संशोधन व विकासासाठी नियोजित असलेली तरतूद ही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. अमेरिका, चीन आणि इतर आघाडीच्या संशोधनप्रधान देशांमध्ये हे प्रमाण खूप मोठे आहे. भारतातील संशोधन व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर कमतरता म्हणजे उद्योग, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था यांच्यातील अपुरा संवाद आणि समन्वय. अमेरिका, जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांनी संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि औद्योगिक उत्पादन यांची प्रभावी सांगड घातली आहे. भारतात मात्र अनेक उद्योग आजही महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत. आपण तंत्रज्ञानाचे मोठे ग्राहक आहोत; परंतु जागतिक स्तरावर मूलभूत तंत्रज्ञान विकसित करणारे आणि त्याचे व्यावसायिक मूल्य निर्माण करणारे राष्ट्र होण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. संशोधनाला केवळ सरकारी अनुदानाचा विषय न मानता राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणाचा केंद्रबिंदू बनविण्याची गरज आहे. त्यासाठी उद्योगांनी विद्यापीठांमध्ये दीर्घकालीन संशोधन प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ द्यावे, संशोधकांना प्रत्यक्ष औद्योगिक समस्यांवर काम करण्याची संधी मिळावी आणि देशात विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभारावी. तसेच आपल्याकडील प्रशासकीय लालफितीचा कारभारही विचारात घ्यावा लागेल. मूलभूत संशोधन, प्रयोगांच्या विश्लेषणावर आणि नव्या संकल्पनांच्या पडताळणी यासाठी संशोधकांनी अधिकाधिक वेळ कारणी लावावा अशी स्वाभाविक अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्षात निधी मंजुरीतील अक्षम्य विलंब, उपकरणांच्या खरेदीतील गुंतागुंतीची प्रक्रिया, वारंवार करावी लागणारी प्रशासकीय पूर्तता आणि रिक्त पदांचा न संपणारा गोंधळ यामुळे संशोधनाचा वेग मंदावतो. २०२६ मधील नीती आयोगाच्या 'इज ऑफ डुइंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट' या ताज्या अहवालामध्येसुद्धा संशोधन प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आवश्यक असल्याची गरज अधोरेखित केली आहे. आजच्या काळात नियंत्रणप्रधान व्यवस्थेपेक्षा पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखणारी, पण संशोधनाला पुरेसे स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था अधिक परिणामकारक ठरू शकते हाच या विषयातील मुख्य गाभा आहे. भारतामध्ये मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष होण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ब्रेन ड्रेन. भारतातील अनेक हुशार विद्यार्थी आजही उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी परदेशात जातात. तेथे त्यांना आधुनिक प्रयोगशाळा, जागतिक दर्जाचे मार्गदर्शक, संशोधनासाठी पुरेसा निधी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधी मिळतात. तुलनेने स्थिर संशोधन कारकीर्द घडविण्याची संधीही त्यांना तिथे उपलब्ध होते. भारतातच संशोधनाची आकर्षक आणि सक्षम संधी मिळत नसेल, तर त्यामुळे देशातील प्रतिभा चांगल्या संधींच्या शोधात दुसरीकडे जाणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यासाठी या स्तरावर बदल होणे आणि संशोधनपूरक व नव्या संधींचे जग उभे राहणे गरजेचे आहे. 'नेचर' या विज्ञानविषयक नियतकालिकाने सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, परदेशातील भारतीय संशोधकांना परत आणण्यासाठी काही योजना आता राबविल्या जात आहेत. मात्र, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, संशोधनाच्या सुविधा आणि करिअरच्या संधी या मूलभूत प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. केवळ आकर्षक शिष्यवृत्ती किंवा काही वर्षांसाठी दिलेले अनुदान पुरेसे ठरणार नाही. संशोधकांसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा उभारता येईल, कुशल सहकारी जोडून देता येतील, उपकरणे, संसाधने देता येतील आणि मुख्य म्हणजे संशोधनपूरक आणि संशोधनासाठी प्रेरक वातावरण आगामी काळात उभे राहील हे पाहावे लागेल. येणाऱ्या काळातील हे खरे आव्हान असणार आहे.

भारतीय प्रज्ञावंतांमध्ये बौद्धिक क्षमतेची कोणतीही कमतरता नाही. परंतु, योग्य पायाभूत सुविधा, R&D मधील भरीव आर्थिक गुंतवणूक, नोकरशाहीतून मुक्ती आणि मूलभूत संशोधनाला प्रोत्साहन देणारी शैक्षणिक परिसंस्था (Ecosystem) निर्माण झाल्यास भविष्यात भारतातूनही मूळ संशोधन करून नोबेल मिळविणारे प्रज्ञावंत मोठ्या संख्येने पुढे येतील. आपल्या इथे रिटायरमेंट झाली की त्याचे परिणाम पुढील संशोधन करताना दिसतात. अधिकृतपणे त्याला लॅब्स आणि संसाधन पुढील व्यक्तीला द्यायला सांगतात. नोबेलसारखा पुरस्कार मिळतो तेव्हा संशोधनाची गुणवत्ता, जागतिक समस्यांवर शोधलेली उत्तरे, नव्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती, संशोधकांच्या ज्ञानाचा व्यापक पातळीवर समाजाला होणारा उपयोग हे महत्त्वाचे निकष असतात. त्यामुळेच भारतातील संशोधकांना आता आगामी काळात लोकांपुढील आव्हानांचा माग घेऊन त्या दिशेने संशोधन करावे लागेल. आत्मपरीक्षण करण्याची आणि सुधारणेची हीच वेळ आहे. आपल्याला नोबेल का नाही, याचे उत्तर केवळ आर्थिक तरतुदीच्या आकडेवारीत सापडणार नाही. शालेय शिक्षणापासूनच या सगळ्याचा विचार करावा लागेल आणि प्रत्येक टप्प्यावर सुधारणा करीत पुढे जावे लागेल. वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला आणि संशोधन संस्कृती रुजली तर नोबेलसारख्या पुरस्कारांची मोहोर भारतीय बुद्धिमत्तेवरही निश्चितच उमटताना दिसेल. आपल्यापुढील खरे आव्हान बुद्धिमत्ता निर्माण करण्याचे नाही, तर त्या बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण देण्याचे आहे.

बुद्धिमत्तेची कमतरता भारतात नाही; मग या बुद्धिमत्तेचे जागतिक दर्जाच्या संशोधनात रूपांतर करण्यात आपण कुठे कमी पडतो आहोत? प्रतिभेची बीजे पेरली जातात; पण त्यांना ज्ञानाचे वटवृक्ष होण्यासाठी आवश्यक असलेली माती, पाणी आणि मोकळे आकाश आपण देतो आहोत का? या प्रश्नांच्या मुळाशी जाणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे. संशोधनातील स्वातंत्र्य आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय बांधीलकी यातूनच ते शक्य होऊ शकेल. जर हे शक्य झाले तर, विश्वाच्या एखाद्या अनुत्तरित गुढाचे उत्तर शोधणारे पुढचे महान संशोधन आपल्या भारतभूमीत झालेले असेल. तो क्षण अतीव आनंद, समाधान आणि अभिमानाचा नक्कीच असेल.

vijay.baviskar@lokmat.com

भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांचे 'नोबेल' यश

तसे पाहता भारताची वैज्ञानिक परंपरा समृद्ध आहे. १९३० मध्ये सी. व्ही. रमण यांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतरदेखील भारतीय वंशाच्या अनेक शास्त्रज्ञांनी विज्ञानविश्वात मोलाचे योगदान दिले आहे. वैद्यकशास्त्रात हरगोविंद खुराना, भौतिकशास्त्रात सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर आणि रसायनशास्त्रात वेंकटरमण रामकृष्णन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाले. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, या नोबेल विजेत्यांनी केलेले संशोधन हे प्रामुख्याने भारताबाहेरील संशोधन संस्थांमध्ये केले होते. अर्थात, आपल्या देशात दर्जेदार संशोधन होतच नाही, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल. अवकाश संशोधन, अणुऊर्जा, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रांत भारताने निश्चितच उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. अनेक जागतिक संशोधन प्रकल्पांतही भारतीय शास्त्रज्ञांनी मोलाचे योगदान दिले आहे, देत आहेत. मात्र, जगाला नवी दिशा देऊ शकणारे विज्ञानाच्या मूलभूत सिद्धांतांमधील संशोधन करण्याच्या बाबतीत मात्र भारतीय शास्त्रज्ञ पिछाडीवर आहेत, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.

जगभर

फ्रान्समध्ये सायबर हल्ला; हजारो फ्रीज खराब!

सायबर हल्ल्यांचे प्रकार आता नवीन राहिलेले नाहीत. जगभरात अनेक ठिकाणी सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे सायबर हल्ले होत असतात, पण फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या एका वेगळ्याच सायबर हल्ल्यानं संपूर्ण जगच चक्रावलं आहे. हॅकर्सनी यावेळी कोणाला लक्ष्य करावं? त्यांनी फ्रान्सच्या सुपरमार्केटमधील शीतकरण यंत्रणेवरच हल्ला केला.

या हल्ल्यामुळे एकाचवेळी पाचशेहून अधिक सुपरमार्केट, दुकानांमधील हजारो फ्रीज आणि फ्रीझरचं तापमान तब्बल ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं. त्यामुळे काही दुकानांना आगी लागल्या तर अनेक ठिकाणी ताजे आणि गोठवून ठेवलेले अन्नपदार्थ खराब झाले. फ्रान्समधील प्रमुख किरकोळ विक्री कंपन्यांनी या हल्ल्याचं वर्णन आतापर्यंतच्या पहिल्या आणि अत्यंत गंभीर हल्ल्यांपैकी एक असं केलं आहे.

फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकॉर्नू यांनी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा संस्था एएनएसएसआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुपरमार्केटमधील फ्रीज आणि फ्रीझर सामान्यतः नियंत्रण पॅनेलच्या मदतीनं चालवले जातात. ही पॅनेल्स संपूर्ण दुकानातील शीतकरण यंत्रणेचं नियंत्रण करतात. ही यंत्रणा इंटरनेटशी जोडलेली असल्यामुळे देखभालीचं काम करणाऱ्या कंपन्यांना दूरवरूनही तिच्या सेटिंगमध्ये बदल करता येतात.

हॅकर्सनी या यंत्रणेपर्यंत प्रवेश मिळवला आणि एकाचवेळी हजारो फ्रीज आणि फ्रीझरमध्ये बिघाड केला. त्यांनी फ्रीजमधील थंडावा कमी केला आणि बर्फ वितळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेला 'डीफ्रॉस्टिंग' म्हणतात. हल्ल्यानंतर सुपरमार्केटमधील फ्रीजवर सूचना लावण्यात आल्या. त्यात फ्रेंच भाषेत म्हटलं होतं, 'राष्ट्रीय सायबर हल्ल्यामुळे



शीतसाखळीत निर्माण झालेला बिघाड शक्य तितक्या लवकर दुरुस्त केला जात आहे.'

फ्रान्सच्या पंतप्रधान कार्यालयातील एका अधिकाऱ्यानुसार, देशाच्या सायबर सुरक्षा संस्थेनं डेन्मार्कमधील डॅनफॉस कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये एक सुरक्षा त्रुटी ओळखली आहे. या कंपनीनं विकसित केलेल्या यंत्रणेद्वारे सुपरमार्केटमधील फ्रीज आणि फ्रीझर नियंत्रित केले जातात. प्रभावित यंत्रणांमध्ये सॉफ्टवेअरची जुनी आवृत्ती वापरली जात होती, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. ग्राहकांनी सॉफ्टवेअर नियमितपणे अद्ययावत ठेवावं आणि जुनी उपकरणं बदलून घ्यावीत, असा सल्ला कंपनी दीर्घकाळापासून देत असल्याचंही सांगण्यात आलं.

या सायबर हल्ल्यामुळे संपूर्ण किरकोळ विक्री क्षेत्राचं नेमकं किती आर्थिक नुकसान झालं, याची एकत्रित आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, इंटरमार्शे या फ्रान्समधील किरकोळ विक्री कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थिएरी कोटियार यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यामुळे देशभरात एकाच दिवसात अनेक कोटी यूरोंचं नुकसान झालं आहे. प्रभावित दुकानांना खराब झालेले सर्व अन्नपदार्थ आता फेकून द्यावे लागतील.

दरम्यान, को-ऑपरेटिव्ह यू या दुसऱ्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉमिनिक शेल्शर यांनी सांगितलं, ताज्या अन्नपदार्थांचं सुरक्षित जतन करणाऱ्या आणि लोकांपर्यंत अन्नपदार्थ पोहोचवणाऱ्या यंत्रणेला लक्ष्य करणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पोलिस आणि तपास यंत्रणांच्या मते, अशा प्रकारचा हल्ला यापूर्वी कधीही झाला नव्हता.

जनमन

सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचे रक्षक



'सरकारी दमनशाहीपुढे सुप्रीम कोर्टही निष्प्रभ ठरतेय का?' हा प्रश्न केवळ कायदेशीर किंवा राजकीय वादापुरता उरलेला नसून, तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याला विचारलेला एक गंभीर प्रश्न आहे. जेव्हा सत्ता उन्मत्त होऊन विरोधकांचे आवाज दाबते आणि सर्व प्रशासकीय यंत्रणा पालापाचोळ्यासारख्या उडून जातात, तेव्हा नागरिकांची शेवटची आशा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले जाते. परंतु, हीच न्याययंत्रणा जर राजकीय समीकरणांच्या किंवा दबावाच्या चक्रात अडकून निष्प्रभ वाटू लागली, तर संविधानातील स्वातंत्र्य, न्याय आणि समतेचे शब्द कागदावरच बंदिस्त राहण्याचा धोका निर्माण होतो.

सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे अंतिम रक्षक आहे. मात्र, सत्तेच्या पोलादी पंजांसमोर न्यायाची वाणी मूक झाली, तर न्यायालयाचे अस्तित्व केवळ एक उपचार उरते. जरी आजच्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असले आणि ती काहीशी बचावात्मक दिसत असली, तरी इतिहास सांगतो की सत्तेच्या कर्णकर्कश रणशिंगापेक्षा संविधानाचा अंतःस्थ प्रकाश आणि नागरिकांचा जिवंत विवेक नेहमीच अधिक शक्तिशाली असतो. सुप्रीम कोर्ट पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले का, याचा निर्णय काळच करेल. पण, जेव्हा जेव्हा न्यायमूर्ती संविधानाच्या साक्षीने ठामपणे उभे राहतात, तेव्हा सत्तेचे सिंहासनही हादरते. न्यायालयाची खरी ताकद केवळ त्याच्या भव्य इमारतीमध्ये नसून, ती लोकशाही मानणाऱ्या जिवंत जनमानसात दडलेली आहे.

- विजय म्हस्के पाटील, छत्रपती संभाजीनगर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे





हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८५८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००९८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

दैनिक जागरण

आरंभ किसी भी कार्य का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है

कठघरे में कांग्रेस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हिंसा और अराजकता के सहारे बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लिप्त होने का जो गंभीर आरोप लगाया, उसके लिए राहुल गांधी अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में धुर वामपंथी प्रशांत भूषण और नेहा बोरा को जिस तरह अपने साथ खड़े होने की विशेष सुविधा प्रदान की, उससे यही पता चला कि हताशा में आकर वे अराजकतावादियों का भी सहयोग लेने को तैयार हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हां, हम सत्ता परिवर्तन के लिए ही लड़ रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं। वे खून-खराबे वाली क्रांति की भी बात कह चुके हैं। नेहा बोरा कह रही हैं कि उन्हें बांग्लादेश के आंदोलन से प्रेरणा मिली। उनकी समझ से बांग्लादेश का आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए था। वे जानबूझकर इसे भूल गईं कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में कट्टरपंथी मजहबी तत्व शामिल थे और उन्होंने हिंसा का कैसा नंगा नाच किया था। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि तब वहां किस बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं हुई थीं और कथित लोकतंत्र प्रेमी छात्रों ने चरमपंथी संगठन जमाते इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पसंद किया था।

नेहा बोरा वामपंथी छात्र संगठन आइसा की नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने छात्र संगठन के नेताओं से अधिक उन पर भरोसा कर रहे हैं। इससे इसी बात की पुष्टि होती है कि वे वामपंथियों से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हैं। यह भी सनद रहे कि कांग्रेस के एक और करीबी योगेंद्र यादव यह कह चुके हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र का भविष्य संसद से नहीं, बल्कि सड़क से तय होगा। कांग्रेस नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि क्या वे अराजकता की खुली पैरवी करने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और नेहा बोरा के विचारों से सहमत हैं? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि काकरोच जनता पार्टी से दूरी बनाते-बनाते उसके निकट जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि वे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के विभिन्न पहलुओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट पर सच में भरोसा कर रहे हैं तो फिर सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे का परिचायक है कि वे भीड़ के साथ मार्च करते हुए याचिका दाखिल करना पसंद करते हैं? आखिर इसे अराजक व्यवहार के अलावा और क्या कहा जा सकता है? कांग्रेस केवल अपनी विचारधारा से भटक ही नहीं गई है, बल्कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर भी कर रही है। उसे अच्छे से पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिये ही हटाया जा सकता है, लेकिन वह ऐसा जाहिर कर रही है कि यह काम अशांति पैदा करके भी हो सकता है।

गड्ढामुक्त सड़कें

उत्तराखंड में मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेढ़ माह पूर्व 15 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन हकीकत देखें तो अधिकांश सड़कें अब भी ज्यों की त्यों हैं। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में ही नहीं, राजधानी देहरादून तक में ऐसी तमाम सड़कें हैं, जिनकी ओर झांकना भी जरूरी नहीं समझा गया। अधिकांश सड़कों पर कहीं गड्ढे मुंह बाए खड़े हैं, तो कहीं मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति के पैबंद लगा दिए गए। सबसे गंभीर स्थिति रोड कटिंग वाली सड़कों की है, जहां करीब 50 प्रतिशत पर अब तक डामरीकरण नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से लेकर संपर्क मार्गों तक का यही हाल है। समझा जा सकता है कि इन सड़कों पर वाहन किस तरह जोखिम उठाकर गुजर रहे हैं। यह महज सड़क की बदहाली नहीं, उस व्यवस्था पर भी सवाल है, जिसमें सड़क खोदने के लिए तो मशीनें तत्काल पहुंच जाती हैं, लेकिन उसे दोबारा चलने लायक बनाने में महीनों गुजर जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो मेनहोल भी सड़कों की बदहाली का कारण बन रहे हैं। कहीं ढक्कन सड़क की सतह से नीचे धंसे हैं, तो कहीं ऊपर उठे हुए हैं। तेज रफ्तार या रात के अंधेरे में तो ये मेनहोल नजर ही नहीं आते। यहां तक कि नई बनी सड़कें भी जगह-जगह से धंस गई हैं। इससे हादसों का खतरा तो बढ़ेगा ही। कहना न होगा कि यह स्थिति मरम्मत की गुणवत्ता के साथ-साथ निरीक्षण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।

> उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में ही नहीं, राजधानी देहरादून तक में सड़कें बदहाल हैं

भारतीय आकांक्षाओं को समझे अमेरिका



हर्ष वी. पंत

अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है, जब द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी संभावनाएं भी हैं और अनिश्चितताएं भी



अवधेश राजपूत

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 17 से 22 अक्टूबर के बीच भारत में होंगे। इस दौरान वे नई दिल्ली के बजाय मुंबई और जामनगर में होंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, पर लगता है फिलहाल उनकी प्राथमिकता ऊर्जा एवं वाणिज्यिक हितों से जुड़ी हुई अधिक है। उनका यह दौरा तब हो रहा है, जब भारत-अमेरिका संबंध एक निर्णायक मोड़ पर हैं, जब व्यापार वार्ता अधर में अटकी है और रूसी तेल की खरीद को लेकर वाशिंगटन भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में रूबियो का दौरा काफी हद तक यह तय करेगा कि क्या ट्रंप प्रशासन अपने व्यावहारिक लेनदेन वाले दृष्टिकोण और भारत को दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व के बीच अपेक्षित तालमेल बना पाता है या नहीं? सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत के साथ ऐसी गहरी साझेदारी बना सकता है, जिसमें नई दिल्ली को दोस्ती निभाने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को ताख पर न रखना पड़े?

भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों की अहमियत भलीभांति समझता है, लेकिन रणनीतिक निकटता का मतलब रणनीतिक अधीनता नहीं है। भारत की विदेश नीति की नींव आज भी 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर टिकी है और उसके तमाम वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय हितों को साधने के माध्यम ही हैं। वाशिंगटन के सामने असल चुनौती इसी बारीक अंतर को समझने की है। भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग को तैयार तो है, पर इस साझेदारी की शर्तें केवल अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं से तय नहीं होंगी। उनमें भारतीय प्राथमिकताओं का अक्स भी झलकना चाहिए। अमेरिका को अपनी 'टैरिफ कूटनीति' की सीमाओं को भी पहचानना होगा। याद रहे कि आर्थिक दबाव सामने वाले को वार्ता के लिए तैयार तो कर सकता है, लेकिन इससे रियायतें सुनिश्चित नहीं हो सकतीं। जरूरत से ज्यादा दबाव का एक नतीजा यह हो सकता है कि भारत अपने बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधीकरण पर जोर दे। ऐसा होने पर वही कारोबारी रिश्ते पटरी से उतर सकते हैं, जिन्हें वाशिंगटन और गहरा करना चाहता है। वार्ता का उद्देश्य परस्पर लाभ पर आधारित सहमति होना चाहिए। उसकी सफलता इस बात से नहीं तय हो सकती कि भारत ने कितनी रियायतें दी हैं।

रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा की जा रही खरीद उसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' की एक बड़ी परीक्षा है। बीते दिनों अमेरिका ने रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों को आर्थिक रूप से दंडित करने के लिए एक कानून भी बनाया। इन देशों को 18 अक्टूबर तक तय करना होगा कि वे आगे क्या रुख अपनाएंगे? इसकी अवधि समाप्त होने के दौरान ही रूबियो भारत में होंगे।

भारत के लिए ऊर्जा की खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक व्यावहारिकता और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों से ही तय होनी चाहिए। खास तौर से तब और जब रूसी तेल आपूर्ति में विविधता लाने और आयात लागत घटाने में अहम भूमिका निभा रहा हो। भारत के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह किसी बाहरी ताकत को अपने ऊर्जा विकल्पों पर उसकी शर्तें थोपने की छूट देने जैसी कोई अनुचित परंपरा स्थापित होने दे। वहीं, अमेरिका द्वारा अपने घरेलू ईंधन संकट के बीच रूसी डीजल की खरीद की ओर कदम बढ़ाने की खबरों ने उसकी भू-राजनीतिक मांगों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के दोहरे रवैये एवं अंतर्विरोधों को ही उजागर किया है।

जामनगर का पड़ाव रूबियो के दौरे को एक स्पष्ट रणनीतिक और वाणिज्यिक आयाम देता दिखता है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी रोजाना 14 लाख बैरल तेल का परिशोधन करने में सक्षम है। वैश्विक पेट्रोलियम शोधन और तैयार रिफाइंड उत्पादों के निर्यात में यह एक प्रमुख केंद्र है। अलग-अलग गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के परिशोधन की इसकी बेजोड़ क्षमता इसे ऊर्जा विविधीकरण के केंद्र में ले आती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार, निजी निवेश और अमेरिकी कारोबारी महत्वाकांक्षाएं आपस में जुड़ती हैं। मार्च 2026 में ट्रंप द्वारा टेक्सास के ब्राउन्सविले क्षेत्र में घोषित रिफाइनरी परियोजना से जुड़े निवेश और उत्पाद खरीद समझौते द्विपक्षीय वाणिज्यिक रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। देखा जाए तो अमेरिका में भारतीय निवेश भारत के बढ़ते आर्थिक दायरे और पहुंच का परिचायक है। इसमें अमेरिकी ऊर्जा प्राथमिकताओं के आगे झुकने की बाध्यता जैसा कोई पहलू नहीं। इसी तरह, अमेरिकी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को भी भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक दबाव पर निर्भर रहने के बजाय प्रतिस्पर्धी कीमतों और आपूर्ति की विश्वसनीयता को आधार बनाना होगा। याद रहे कि मजबूत वाणिज्यिक रिश्ते तभी टिकाऊ हो सकते हैं, जब वे भारत के रणनीतिक विकल्पों का दायरा बढ़ाएं, न कि उन्हें सीमित करें।

रूबियो का दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है, जहां द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी संभावनाएं भी हैं और अनिश्चितताएं भी। व्यापार वार्ताएं अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंची हैं, रूसी तेल पर प्रतिबंधों का मसला भी नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। दोनों देशों के समक्ष ऊर्जा निवेश और कारोबारी सहयोग को विस्तार देने के कारण मौजूद हैं। रूबियो का दौरा आगे बढ़ने की राह में कुछ व्यावहारिक रास्ता तो निकाल सकता है, पर इससे दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में मौजूद अंतर्विरोध शायद ही मिट पाएं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार तो है, पर अपनी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों की कीमत पर नहीं। वाशिंगटन इस पहलू को जितनी जल्दी समझ ले तो सार्थक द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएं उतनी ही बलवती होंगी। इसकी अनदेखी रणनीतिक अवसरों की राह में निरंतर अवरोध पैदा करती रहेगी। भारत-अमेरिका रिश्ते का भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि भारत वाशिंगटन की उम्मीदों के मुताबिक खुद को कितना ढालता है, बल्कि इससे तय होगा कि अमेरिका एक उभरते हुए भारत के साथ ऐसी शर्तों पर संवाद एवं सहयोग स्थापित करने में कितना सफल होता है, जो नई दिल्ली के स्वाभिमान और हितों के अनुकूल हों।

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

गरीबी से भी बचा रही आयुष्मान योजना

मोदी सरकार ने भारतीय समाज में जनस्वास्थ्य और गरीबी के अंतःसंबंधों को समझते हुए जिस आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया था, वह निर्धन, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के अनेक आयाम हैं। आयुष्मान भारत योजना मात्र एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं। यह एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन एवं समान अवसर से जोड़ने की एक सामाजिक नीति भी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित लोगों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना है। सीमांत पर बसे सामाजिक समूहों में इस योजना के सामाजिक प्रभाव के अध्ययन के दौरान इस योजना के आधार तल पर पड़ने वाले प्रभावों का साकार रूप देखने को तो मिला ही, साथ ही इस योजना के बहुल प्रभावों को समझने में मदद भी मिली। गांवों में अपने फील्ड वर्क के दौरान मैंने पाया कि यह योजना समाज में वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह योजना स्वास्थ्य बीमा द्वारा उनके जीवन की रक्षा तो कर ही रही है, साथ ही साथ उन्हें गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र से भी बचा रही है। इस योजना के चलते गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण व्यक्तियों की कार्यक्षमता में सुधार और वृद्धि दर्ज की गई है। इससे लोगों का पारिवारिक जीवन सुगम होता है और वे सामाजिक, आर्थिक दायित्वों की पूर्ति में सक्षम होते हैं।

आयुष्मान योजना के सहयोग से लाभार्थी व्यक्ति उचित स्वास्थ्य लाभ के पश्चात अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन में पुनः वापस लौट पाता है और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह योजना स्वास्थ्य सुरक्षा द्वारा व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक सहभागिता, दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह सामाजिक समावेशन एवं स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। भारतीय समाज और विशेषतः ग्रामीण समाज में जहां संरचनात्मक असमानताएं व्यापक स्तर पर देखने को मिलती हैं, वहां इस योजना के माध्यम से अस्पतालों की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, सामाजिक भेदभाव से परे व्यापक स्तर पर कमजोर एवं वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी में निःशुल्क उपचार वंचित समुदाय के जीवन में जीवन की एक नई रोशनी पैदा कर रहा है।



स्वास्थ्य पर लोगों द्वारा अपने पास से किए जाने वाले खर्च ने भारत में गरीबी के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है

डा. स्मिता



सेहत सुधारने और बचत बढ़ाने वाली योजना। फाइल

भारत में गरीबी की दर धीरे-धीरे कम होती जा रही है, किंतु अभी भी कुल जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे वास करता है। इस गरीबी में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की बड़ी भूमिका होती है। भारत में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले संपूर्ण व्यय का 62.6 प्रतिशत लोग अपनी जेब से करते हैं। स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च में तुलनात्मक रूप से भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। स्वास्थ्य पर अपने पास से किए जाने वाले खर्च ने भारत में गरीबी के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है।

जब कोई निर्धन व्यक्ति बीमार पड़ता है तो कई बार वह सूदखोरों से कर्ज लेता है। नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के एक आंकड़े के अनुसार भारत की गरीबी में लगभग 2.61 प्रतिशत की वृद्धि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण होती है। इलाज की खातिर लिया जाने वाला कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता जाता है। यदि गरीब परिवार का कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार रहकर घर या अस्पताल में रहने को बाध्य होता है तो इससे आय सृजन न हो पाने के कारण वह परिवार गरीबी की खाई में धंसता जाता है। भारत सरकार ने इन्हीं स्थितियों को समझते हुए आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया।

आयुष्मान भारत के तहत साल भर में पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलता है। एक आंकड़े के अनुसार अब तक कुल 12.69 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती लोगों के इलाज में 1.92 लाख करोड़ से ज्यादा राशि का इलाज मुहैया कराया जा चुका है। इस योजना के तहत भारत में अब तक कुल 42.31 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 49 प्रतिशत कार्ड महिलाओं और 51 प्रतिशत कार्ड पुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 5.59 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। गांव की एक बूढ़ी महिला ने बताया कि, 'जब मुझे पेट की बीमारी हुई तो लगा अब नहीं बचेंगे। गरीब के पास अस्पताल जाने की कूव्वत कहां। बेटे को न जाने कहां से आयुष्मान योजना के बारे पता चला। उसे हासिल कर अस्पताल गए तो इलाज हुआ।' जन स्वास्थ्य की इस योजना ने गांवों और शहरों की झुग्गी बस्तियों तक अपने प्रभाव को फैलाया है। इसने समाज के एक हिस्से को निर्धनता से मुक्त होने में मदद तो की ही है, उन्हें यह भी अहसास कराया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है और उनके प्रति संवेदनशील है।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शक्ति की भक्ति

एक शक्ति है, जो सर्वत्र व्याप्त है। वह शक्ति अनेक रूपों में कण-कण में विद्यमान है। वही समस्त सृष्टि की रचयिता है और संहारक भी। प्रकृति ने माया का रूप समय के अनुसार भिन्न बनाया है। माया उसी शक्ति का प्रमाण है, पर उसे जानने, समझने, अनुभव करने से मानव में चेतना मुखर होती है। अन्यथा हृदय में प्रेम और भक्ति का प्रकाश संभव नहीं। इसलिए शक्ति की उपासना कोई कर्मकांड नहीं है। शक्ति की पूजा-अर्चना मायातीत ऊर्ध्व चेतना को जागृत करने में समर्थ है। शक्ति की आराधना आदि काल से नर-नारियों ने सदैव की है, लेकिन पात्रता का सुयोग किसी-किसी में ही फूटता है। जीव के लिए विचार और संकल्प द्वारा मनोबल की यात्रा पूर्ण करना एकमात्र लक्ष्य है। हमारी एक-एक श्वास पर शक्ति का नियंत्रण है।

विभिन्न रूपों और क्षितिज आयामों में शक्ति का स्फुरण नारायण की इच्छा के अधीन है। हरि की इच्छा शक्ति का प्रवाह है, उद्गम नहीं। प्रभु अपनी शक्ति रूपेण देवी का आश्रय लेकर विराम लेते हैं। वे सब कुछ देवी मां को सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं। जिस तरह स्वामी के अवतार लोकों के कल्याण के लिए होते हैं-उसी तरह देवी का प्राकट्य भी हर संकट, बाधा, पाप, अत्याचार और अन्याय को मिटाने के लिए होता है। अनेक रूपों में माता अपनी संतति के लिए प्रकट होकर शांति धारण करती हैं। शक्ति का भौतिक नाम शांति है। शांति ही देवी है। मां शांति की कृपा हो तो मानव अपार शक्ति का भाजक बन सकता है।

तभी, शरीर की गति और मति दोनों समर्पित भाव से पुकारती है-या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति, चेतना और सामर्थ्य के रूप में स्थित हैं, उन भगवती आदिशक्ति को बारंबार नमस्कार है, कोटिशः नमन है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

सरकारी दस्तावेजों में जनभाषा की दरकार

देवेंद्रराज सुथार

सरकारी दस्तावेजों में आज भी ऐसे अनेक शब्द मौजूद हैं, जिनका अर्थ समझने के लिए सामान्य नागरिक को दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। खतौनी, तकसीम, मिसिल, हकूक, रकबा, फर्द, तरमीम और ततिमा जैसे शब्द इसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। खतौनी और खसरा जैसे दस्तावेज जमीन के स्वामित्व, विवरण और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। तकसीम का संबंध बंटवारे से है, जबकि तरमीम का आशय किसी अभिलेख में संशोधन से होता है। रकबा जमीन के क्षेत्रफल को दर्शाता है और फर्द किसी अभिलेख की नकल या संबंधित विवरण के लिए प्रयुक्त होती है। इसी तरह ततिमा और मिसिल जैसे शब्द भी राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में भी अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओं से आए अनेक शब्द आज तक प्रचलन में हैं। तफ्तीश, इत्तला, मुखबिर, मुनादी, रोजनामचा, मालखाना, पंचनामा, तस्दीक, मुचलका, इश्तिहार, जिरह, रपट, मुल्जिम और फरियादी जैसे शब्द पुलिस की कार्यप्रणाली और कानूनी दस्तावेजों में दिखाई देते हैं। इसी तरह परिवाद, मुल्तवी, तामील, इकरार, हुक्मनामा, कुर्की, नाजिर, वारंट और शिनाख्त जैसे शब्द न्यायिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। इनका अर्थ कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए स्पष्ट हो सकता है, लआम नागरिक के लिए इनकी व्याख्या कठिन हो सकती है।

> शासन को चाहिए कि सरकारी दस्तावेजों में प्रचलित तकनीकी शब्दों के साथ उनके सरल हिंदी अर्थ भी दिए जाएं

मूल सवाल यही है कि नागरिक जिस भाषा में अपनी बात समझते हैं, क्या सरकारी कामकाज भी उसी सहजता से उनकी समझ में नहीं आना चाहिए? प्रशासन को चाहिए कि सरकारी दस्तावेजों में प्रचलित तकनीकी शब्दों के साथ उनके सरल हिंदी अर्थ भी दिए जाएं। राजस्व अभिलेखों, पुलिस की रिपोर्टों, न्यायिक आदेशों और सरकारी प्रपत्रों में आम नागरिकों के लिए सहज भाषा का उपयोग बढ़ाया जाए। जहां किसी पारंपरिक शब्द को हटाना संभव न हो, वहां उसका अर्थ कोष्ठक में या अलग से स्पष्ट किया जा सकता है।

सुशासन की कसौटी केवल यह नहीं है कि सरकार कितनी योजनाएं बनाती है या कितनी तेजी से फाइलों का निपटारा करती है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नागरिक अपनी समस्या, अपने अधिकार और सरकारी निर्णय को कितनी आसानी से समझ पाता है। भाषा नागरिक और शासन के बीच सेतु होनी चाहिए, दीवार नहीं। जब नागरिक अपने दस्तावेज स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकेंगे, तभी उनमें अपने अधिकारों के प्रति वास्तविक विश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आखिर सरकारी कागज जनता की सुविधा के लिए हैं, जनता को उलझाने के लिए नहीं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अपना रवैया बदले अमेरिका

'अमेरिका के लिए संकट की घड़ी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में लेखक दिव्य कुमार सोती ने अमेरिका को अपनी नीतियों में बदलाव लाने का परामर्श दिया है। अमेरिका लंबे समय से विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति रहा है, लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव ने उसकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की सैन्य ताकत के बावजूद हर संकट का समाधान युद्ध और प्रतिबंधों से संभव नहीं है। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भअमेरिका ईरान को झुकाने में सफल नहीं हो सका। होमुर्ज जल मार्ग युद्ध का अखाड़ा बन गया है। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में टैरिफ वार छेड़ दिया है। भारत सहित कई देश अमेरिका का विकल्प तलाश रहे हैं। आज अमेरिका की वजह से रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है। चीन और रूस जैसी शक्तियों की बढ़ती भूमिका भी अमेरिका के लिए चुनौती है। ऐसे में अमेरिका को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय कूटनीति, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्व शांति के लिए युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत ही सबसे प्रभावी रास्ता है।

हिमांशु शेखर, केसपा (गयाजी)

न्याय, आस्था और आरक्षण

संपादकीय 'एक आवश्यक निर्णय' के संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि आरक्षण और धार्मिक

मेलबाक्स

स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील विषयों पर भावनाओं से अधिक संविधान, तर्क और न्याय की कसौटी प्रभावी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत तभी सार्थक होगा, जब उसे किसी धर्म की विजय अथवा पराजय के रूप में देखने के बजाय संवैधानिक व्यवस्था की स्पष्टता और सामाजिक न्याय के व्यापक संदर्भ में समझा जाए। आरक्षण किसी धर्म का पुरस्कार नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वंचना, सामाजिक भेदभाव और अवसरों की असमानता से निपटने का संवैधानिक उपाय है। इसलिए इसका लाभ किसे मिले और किन परिस्थितियों में मिले, यह निर्णय भावनात्मक आग्रहों या राजनीतिक सुविधा से नहीं, बल्कि संविधान, लागू कानूनों और प्रामाणिक सामाजिक तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्रता के कानूनी आधार भी अलग-अलग हैं। अतः दोनों को एक ही कसौटी पर रखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस स्वतंत्रता की आड़ में छल, भय, दबाव अथवा अनुचित प्रलोभन के माध्यम से मतांतरण कराया जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन मात्र को उसके विरुद्ध सामाजिक या नागरिक भेदभाव का आधार बनाना भी न्यायसंगत नहीं होगा। स्वैच्छिक आस्था-परिवर्तन और अनुचित प्रभाव से कराया गया मतांतरण दो अलग परिस्थितियां हैं। कानून को इनके बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि किसी समुदाय में धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों की असमानता बनी रहती है, तो उस वास्तविकता का निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए? किसी समस्या का समाधान केवल दावों से नहीं, बल्कि प्रमाणों और अनुभवजन्य तथ्यों से निकलता है। सरकार को चाहिए कि वह सामाजिक वंचना के स्वरूप, आरक्षण की पात्रता और विभिन्न समुदायों की वास्तविक परिस्थितियों पर पारदर्शी अध्ययन कराए। साथ ही, आरक्षण का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया, प्रभावी निगरानी और समयबद्ध न्यायिक समाधान आवश्यक हैं। किसी भी समुदाय के पात्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनुचित लाभ लेने की गुंजाइश समाप्त होनी चाहिए।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

34.7 करोड़ हो जाएगी भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2050 तक और कुल आबादी में वृद्धजनों की हिस्सेदारी 20.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार।

आजकल

विदेशी चंदे में पारदर्शिता जरूरी



गौरव कुमार
लोक नीति विश्लेषक

देश में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनके कारण विदेशी स्रोतों से प्राप्त चंदे का नियमन राष्ट्रीय चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय बना है। हालांकि यह सच है कि विदेशी सहायता देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक है, किंतु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि विदेशी चंदे का उपयोग भारत के कानूनों और उसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा इसका इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी कार्यों में न किया जाए



भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि विदेशी चंदे का उपयोग कानून सम्मत, पारदर्शी और घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो। प्रतीकात्मक

देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिकता होती है। यही बात भारत जैसे विशाल और संप्रभु राष्ट्र पर भी लागू होती है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पहले से काफी बदल गई है और उसका विस्तार भी हुआ है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति और चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, ढांचे और नियामकीय तंत्र की स्थापना को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के अनुकूल देखा जाना चाहिए। आज देश में ऐसी अनेक घटनाएं और स्थितियां सामने आई हैं, जिनके कारण विदेशी स्रोतों से प्राप्त चंदे का नियमन राष्ट्रीय चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय बना है। हालांकि यह सच है कि विदेशी सहायता देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक है, किंतु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि विदेशी चंदे का उपयोग भारत के कानूनों और उसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा इसका इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी कार्यों में न किया जाए। इसी को ध्यान में रख सरकार ने संसद के बीते मानसून सत्र में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया था।

विदेशी चंदे की निगरानी: सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एफसीआरए में कुछ बदलाव इस संशोधन विधेयक के माध्यम से लाए हैं। इसे वर्तमान नियामकीय ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह स्वाभाविक है कि वह विदेशी चंदे की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि देश में आने वाले धन का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हो। विदेशी सहायता का विरोध करना और विदेशी चंदे के नियमन का समर्थन करना दो अलग-अलग विषय हैं। भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सहयोग के साथ जवाबदेही भी अनिवार्य है। यही सिद्धांत इस संशोधन विधेयक की प्रासंगिकता पर भी लागू होता है।

राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल: विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कोई नया कानून नहीं है। यह देश में वर्ष 1976 से लागू है। समय-समय पर आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। इस कानून का उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल गतिविधियों में न हो। किसी भी देश को यह जानने और अपनी सुरक्षा एवं संप्रभुता सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी सीमाओं के भीतर सक्रिय संस्थाओं को चंदे कहां से प्राप्त हो रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, जहां हजारों संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक गतिविधियों, सामाजिक कल्याण और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में काम करती हैं। यदि किसी संस्था को अस्पताल चलाने, बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण विकास अथवा आपदा राहत के लिए विदेशी चंदे प्राप्त होता है तो उसके खर्च का उचित हिसाब उपलब्ध होना चाहिए। दानदाता, सरकार और लाभार्थी- तीनों को यह विश्वास होना चाहिए कि चंदे का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए इस संशोधन विधेयक को केवल प्रतिबंधों से जुड़ा कानून मानना उचित नहीं होगा। यह विदेशी अंशदान के उपयोग को नियमबद्ध करने, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।

विदेशी चंदे से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन : वर्तमान समय में यह संशोधन विधेयक राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इस विधेयक को 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में 12 अगस्त, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। हाल में समिति ने इससे संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श किया। इन हितधारकों में पेशेवर संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस विधेयक का एक प्रमुख पक्ष उन परिस्थितियों से संबंधित है, जब किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद हो जाता है, संस्था स्वयं इसे छोड़ देती है या उसका नवीनीकरण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कानूनी स्पष्टता आवश्यक है। प्रस्तावित व्यवस्था में एक प्राधिकरण के माध्यम से ऐसी संपत्तियों की निगरानी, प्रबंधन और निपटान की व्यवस्था का प्रविधान किया गया है। धार्मिक स्थलों से संबंधित संपत्तियों के मामले में उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की शर्त भी विधेयक में जोड़ी गई है। ऐसी व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि पंजीकरण समाप्त होने के बाद संपत्तियों और विदेशी चंदे के प्रबंधन को लेकर अनिश्चितता न बनी रहे। यदि नियम पहले से स्पष्ट होंगे तो प्रशासनिक निर्णयों में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय रिकार्ड जरूरी: यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में एफसीआरए में किए गए संशोधनों के तहत विदेशी अंशदान के हस्तांतरण और प्रशासनिक खर्च से संबंधित नियमों को अधिक कठोर बनाया गया था। प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था और विदेशी अंशदान को दूसरी संस्था को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नए संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग पर प्रत्यक्ष निगरानी बढ़ाना और जवाबदेही को मजबूत करना है। जब किसी परियोजना के लिए धन दिया जाता है तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसका उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप हो। स्पष्ट वित्तीय रिकार्ड से धन के दुरुपयोग की संभावना कम होती है और कानूनी रूप से वैध सामाजिक कार्यों में जनता तथा दानदाताओं का विश्वास भी बढ़ता है। सरकार की इस नियामकीय जिम्मेदारी को सुशासन के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार कर व्यवस्था, बैंकिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता आवश्यक है, विदेशी अंशदान के मामले में भी स्पष्ट नियम जरूरी हैं।

आज भारत में हजारों संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, बाल कल्याण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं विदेशी सहायता भी प्राप्त करती हैं, जबकि अनेक संस्थाएं घरेलू दान और अन्य स्रोतों पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में इन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे कानूनी निर्देशों और निर्धारित नियामकीय मानकों का पालन करें। साथ ही, सरकार को भी कानूनी प्रविधानों के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए पंजीकरण और नवीनीकरण की समयबद्ध प्रक्रिया, डिजिटल रिपोर्टिंग, वित्तीय विवरणों में स्पष्टता और शिकायतों के निपटारे की प्रभावी व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे संगठनों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना भी जरूरी है, ताकि सीमित संसाधनों वाली संस्थाएं प्रशासनिक जटिलताओं में उलझने के बजाय अपने वैध सामाजिक उद्देश्यों पर ध्यान दे सकें।

नियमन में जनहित का ध्यान रखना आवश्यक

एफसीआरए संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। समिति में विभिन्न पक्षों की बात सुनने से प्रस्तावित कानून के व्यावहारिक प्रभावों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि प्रस्तावित प्रविधान स्पष्ट हों, प्रशासनिक अधिकारों की सीमाएं निर्धारित हों और संबंधित संस्थाओं को कानून के अंतर्गत उचित प्रक्रियागत संरक्षण मिले। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि संसदीय समीक्षा किसी विधेयक को कमजोर करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने का अवसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय जवाबदेही जैसे विषयों पर चर्चा के बाद कानून बनाया जाए तो उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। विपक्ष और नागरिक संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं का परीक्षण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी बिल का मूल्यांकन उसके वास्तविक प्रविधानों, उद्देश्यों और संभावित प्रभावों के आधार पर होना चाहिए। इससे न केवल सरकार की नीति को लेकर स्पष्टता आएगी, बल्कि नियामकीय व्यवस्था में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

कुल मिलाकर, भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि विदेशी चंदे का उपयोग कानून सम्मत, पारदर्शी और घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग शासन, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक संस्थाओं की वैध गतिविधियों के लिए स्पष्ट नियम-इन तीनों का संतुलन ही एफसीआरए व्यवस्था को प्रभावी बना सकता है। यही वह दिशा है, जिसमें भारत अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और संस्थागत रूप से मजबूत व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकता है। किसी भी कानून का प्रभाव केवल संस्थाओं तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत सेवाओं पर निर्भर लोगों के हित भी इससे जुड़े होते हैं। अतः नियमन में वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ जनहित का ध्यान रखना आवश्यक है।

खरी-खरी

आशियाने की तलाश

डा. संदीप नानावटी

कल्पना कीजिए, अगर परिंदों के भी घोसले बिकते तो इंसानों की तरह उनकी दुनिया में भी प्रापर्टी ब्रोकरों का राज होता। फर्क सिर्फ इतना होता कि इंसान जमीन पर मकान बनाकर आसमान छूने की कोशिश करता है और परिंदे आसमान में रहकर जमीन की कीमत चुकाते!

एक दिन जंगल के मशहूर प्रापर्टी ब्रोकर तोतेलाल की दुकान पर एक कबूतर दंपती पहुंचा। कबूतर-भाई साहब, कोई अच्छा-सा घोसला दिखाइए। बस ऐसा घोंसला हो जिसमें दाना-पानी का इंतजाम हो, बच्चों को हवा लगे और बिल्ली से सुरक्षा रहे। ब्रोकर हंसा, 'अरे साहब! आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। आजकल घोसले में हवा नहीं, एयर सर्कुलेशन देखा जाता है। दाना-पानी नहीं, माड्यूलर फीडिंग जोन होना चाहिए। और बिल्ली से सुरक्षा? उसके लिए अलग से सिक्योरिटी चार्ज लगेगा!' फिर उसने अपना लैपटाप खोला और प्रापर्टी दिखाने लगा। 'यह देखिए, बरगद रेजिडेंसी! सौ साल पुराना पेड़, पच्चीस फुट की ऊंचाई, चारों तरफ हरियाली, सामने नदी का व्यू। एकदम प्रीमियम लोकेशन!' कबूतर ने पूछा, 'कीमत?' 'सिर्फ पचास किलो दाना!' 'इतना महंगा?' 'अरे साहब, यह बरगद की जड़ से लगा हुआ घोसला है। नीचे तालाब है, सामने मोरों का डांसिंग जोन और पास में कोयल का म्यूजिक स्टूडियो।

'कबूतर की पत्नी बोली, 'कुछ सस्ता दिखाइए।' तोतेलाल ने तुरंत दूसरा ब्रोशर निकाला। 'यह देखिए, यूकेलिप्टस हाइट्स! ऊंचाई ज्यादा, पत्तियां कम, पड़ोसी कम, लेकिन हवा का क्रास-वेंटिलेशन शानदार!' कबूतरी मैडम ने कहा, 'मगर इसमें तो छांव ही नहीं है!' ब्रोकर मुस्कराया, 'मैडम, छांव तो अब पुराने जमाने की सुविधा है। आजकल मिनिमलिस्ट लिविंग का ट्रेंड है! बादलों के बीच आशियाना, चांद का नजारा मुफ्त! मेरी मानो तो बुकिंग आज ही कर लो, क्योंकि आसमान में घोसले सीमित हैं!'

कबूतर दादा सोचने लगे कि काश, परिंदों को वोटिंग पावर मिलती तो सरकार पंछियों के लिए प्रधानमंत्री घोसला योजना लांच करती। चुनाव के ऐन पहले मंत्री जी घोसले के पट्टे बांटते।

पोस्ट

काकरोच जनता पार्टी, आप, कांग्रेस, वामदल, तृणमूल, आइसा और एसएफआइ की मुहिम चुनी हुई सरकार के तख्तापलट से जुड़ी हुई है। इनका छात्रों से सरोकार नहीं।
नवरूप सिंह@TheNavroopSingh

जंतर-मंतर से संसद-सुप्रीम कोर्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां दो हजार की भीड़ भी दस हजार के बराबर दिखाई देती है और माहौल बना रहता है। बुराड़ी में दस हजार की तादाद भी कम दिखेगी। इसलिए भी सबको जंतर-मंतर ही चाहिए।
मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

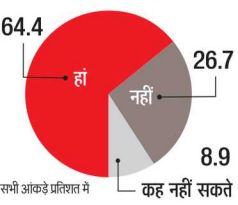
एक वक्त था जब आंदोलनकारी मामूली संसाधनों में काम चलाते थे। आज वे हवाई जहाज से सफर करते हैं। फाइव स्टार होटल्स में जश्न मनाते हैं। लाखों किराया देकर पाश इलाकों में रहते हैं।
सुमंत@sumantkabir



एयरपोर्ट पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लोगों ने खरी-खोटी सुनाई। जिस व्यक्ति ने दीपके से कहा कि क्यों देश खराब कर रहा है, उसने उन तमाम भारतीयों के मन की बात कही, जो आए दिन होने वाले बेकार के प्रदर्शनों से सचमुच तंग आ चुके हैं।
यश रावत@india_expert

जागरण जनमत — कल का परिणाम

मतांतरण के बाद आरक्षण से वंचित किए जाने से मतांतरण पर अंकुश लगेगा?



सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या धरने-प्रदर्शन के कारण नुकसान उठाने वाले व्यापारियों को मुआवजा मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

तिलचट्टे का हो रहा अब हर ओर विरोध,
फिर भी ना होता इन्हें सच्चाई का बोध।
सच्चाई का बोध क्रोध में जनता आई,
तो पक्का इक रोज होयगी खूब दुकाई!
चढ़ जाएं जिस रोज आप जेन-जी के हत्थे,
तय समझो बेभाव पिटेंगे ये तिलचट्टे!!
-ओम प्रकाश तिवारी



अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

बिहार डायरी

दूध से जला एनडीए छाछ फूंक कर पी रहा

राजनीति से जुड़े लोग इस प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि इससे पहले किस साल बिहार विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के चुनाव में इतनी मारामारी हुई थी? देर से मिलने वाला उत्तर यह होता है कि शायद इससे पहले कभी राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में इतनी रुचि नहीं दिखाई थी। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि शिक्षक, स्नातक और स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के चुनाव दलों के बल पर नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की प्रबंधन-कुशलता से जीते जाते हैं। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद की 36 सीटें इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से भरी जाती हैं। स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार की 24 तथा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की छह-छह सीटों पर चुनाव होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। कई सदस्य चार-पांच चुनाव जीतकर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हाथ आजमा चुके राजनेता इन निर्वाचन क्षेत्रों का रुख इसलिए नहीं करते, क्योंकि इनकी निर्वाचक मंडली अलग होती है। स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के चुनाव में धन का बोलबाला रहता है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में पहली बार बड़े स्तर पर धन की चर्चा हो रही है।

राज्य के दो गठबंधन-एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन के घटक दल जहां खुलकर एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वहीं एनडीए में यह संकट अंदरूनी खींचतान के रूप में सामने आया है। सबसे विकट स्थिति सत्तारूढ़ जदयू के सामने है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के नीरज कुमार का विरोध उन्हीं के दल के विधायक अनंत सिंह कर रहे हैं। वे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस संकट को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को सौंपी। ललन सिंह ने बातचीत के बाद बताया कि अब अनंत सिंह जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के विरुद्ध सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। इससे फर्क यह पड़ा कि अनंत सिंह चुनाव प्रचार में जदयू उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहे हैं। वे मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अनुज सिंह को वोट दें और बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दें।



अनंत सिंह के रुख से चिंतित जदयू। फाइल

नाराजगी का कारण यह बताया जा रहा है कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का विरोध किया था। इसलिए परिषद चुनाव में वे उनका विरोध कर रहे हैं। आम तौर पर राजनीति में अतीत के समर्थन और विरोध का हिसाब नहीं रखा जाता है। अन्य दलों को छोड़ दें तो एनडीए के घटक दलों के शायद ही कोई ऐसे नेता होंगे, जिन्होंने अलगाव के दिनों में एक-दूसरे की बखिया न उधेड़ी हो। भाजपा इस विवाद को जदयू का अंदरूनी विषय मान रही है। फिर भी, बड़े भाई की भूमिका में वह चाहती है कि आठ सीटों के चुनाव में इस गठबंधन के सभी अधिकृत उम्मीदवारों की जीत हो। जदयू का अंदरूनी विषय इसे इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि ललन सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रचार से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं और उनका एक विधानसभा क्षेत्र मोकामा, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। वे नालंदा के मूल निवासी हैं। उनके रुख को देखते हुए जदयू उम्मीदवार ने भी उनसे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का व्यक्तिगत आग्रह नहीं किया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा से उनकी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। इसी तरह, भाजपा ने उन नेताओं को दल से निष्कासित कर दिया है, जो पार्टी के निर्देश के विपरीत चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए हैं।

एनडीए के कुल चार विधायक अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, पर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनमें जदयू के अनंत सिंह के अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, आलोक कुमार और रामेश्वर महतो शामिल हैं। आलोक कुमार सिंह तो रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। खैर, रालोमो के चार में से तीन विधायकों का विवाद पहले से चल रहा है। नई बात यह है कि ये विधायक अब अपने दल की तरह जदयू को भी चुनौती दे रहे हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के पुष्कर आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। परिणाम कुछ भी हो, इससे सरकार की संरचना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एनडीए के लिए यह प्रवृत्ति बनने का खतरा है। आशंका है कि कहीं इसकी पुनरावृत्ति 2029 के लोकसभा और 2030 के विधानसभा चुनावों में न हो जाए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम एनडीए, खासकर भाजपा के लिए दूध से जले जैसा अनुभव है। इसलिए एनडीए परिषद चुनाव को छाछ की तरह ले रहा है।

मंथन

बदलते परिवेश में बुजुर्ग

यदि नीतिगत तैयारियां समय रहते नहीं की गईं तो बढ़ती वृद्धजन आबादी एक गंभीर सामाजिक चुनौती का रूप ले सकती है



शिशिर शुक्ला
अध्यापक, स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर

बदलती सामाजिक संरचना, एकल परिवारों का विस्तार, आर्थिक स्वार्थ और संबंधों में बढ़ती संवेदनहीनता ने वृद्धावस्था की चुनौतियों को अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे समय में केरलम सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तुत विधेयक केरलम सीनियर सिटीजंस केयर एंड प्रोटेक्शन आफ राइट्स बिल, 2026 भारतीय समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक कानूनी ढांचा विकसित करना है। विधेयक में शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, वित्तीय शोषण, संपत्ति पर अवैध कब्जे तथा बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा जैसे कृत्यों के विरुद्ध प्रविधान प्रस्तावित हैं। देखभाल केंद्रों के पंजीकरण, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण, शिकायतों के निस्तारण और राज्य एवं जिला स्तर पर संरक्षण तंत्र विकसित करने की परिकल्पना भी इसमें शामिल है। प्रस्तावित प्रविधानों के अंतर्गत कतिपय अपराधों के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का उल्लेख किया गया है।

इस पहल की प्रासंगिकता समझने के लिए भारत की बदलती जनसांख्यिकी पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 14.9 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का करीब 10.5 प्रतिशत थी। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 34.7 करोड़ हो जाएगी और कुल आबादी में वृद्धजनों की हिस्सेदारी 20.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। आने वाले दशकों में भारत की आबादी का लगभग प्रत्येक पांचवां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। रिपोर्ट बताती है कि 2046 तक वृद्धजनों की संख्या बच्चों की आबादी से अधिक हो सकती है। ये अनुमान केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन व्यवस्था, आवास, पारिवारिक देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की भावी आवश्यकताओं का ठोस पूर्वाभास हैं। यदि नीतिगत तैयारियां समय रहते नहीं की गईं तो बढ़ती वृद्धजन आबादी एक गंभीर सामाजिक चुनौती का रूप ले सकती है।

वृद्धावस्था की समस्या का सबसे पीड़ादायक पक्ष आर्थिक अभाव के साथ-साथ अपने ही परिवेश में असुरक्षित हो जाना है। वृद्ध व्यक्ति को मारना-पीटना ही प्रताड़ना नहीं है। उसे निरंतर अपमानित करना, उसकी बातों को महत्वहीन समझना, भोजन और दवाइयों की उपेक्षा करना, पेंशन पर जबरन अधिकार जमाना, बैंक संबंधी निर्णयों में दबाव डालना अथवा संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए विवश करना भी उसके अधिकारों का उल्लंघन है। कई बार बुजुर्ग अपने ही घर में निर्णय लेने की स्वतंत्रता खो देते हैं। उनकी आवश्यकताओं को अनावश्यक खर्च और उनकी इच्छाओं को परिवार पर बोझ समझा जाने लगता है।

वृद्धजनों के संरक्षण की पहल आर्थिक सुरक्षा के बिना सर्वथा अधूरी है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 40 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग सबसे निर्धन संपत्ति-वर्ग में आते हैं, जबकि लगभग 18.7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों के पास अपनी कोई आय नहीं है। ऐसी स्थिति में नियमित पेंशन, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक आवास उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। विशेष रूप से विधवाओं, अकेली रहने वाली महिलाओं, दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों पर केंद्रित नीतियों की जरूरत है। वृद्धावस्था में महिलाओं की चुनौतियां कई बार अधिक जटिल हो जाती हैं, क्योंकि लंबी जीवन प्रत्याशा के बावजूद उन्हें विधवापन, सीमित संपत्ति-अधिकारों और आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है। अतः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाना आवश्यक है।



वृद्धजनों की सुरक्षा को अधिकार और उत्तरदायित्व के दायरे में लाना आवश्यक। प्रतीकात्मक

केरलम की तर्ज पर अन्य राज्यों को भी अपनी जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। वृद्धजनों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले निष्क्रिय वर्ग के रूप में देखना भी उचित नहीं है। उनके पास जीवन के विविध क्षेत्रों का अनुभव, कौशल, ऐतिहासिक स्मृतियां और सामाजिक विवेक की अमूल्य पूंजी होती है। केरलम में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का उपयोग करके सिल्वर इकोनमी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना इस दिशा में संभावनाएं प्रस्तुत करती है। शिक्षण, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा और स्थानीय उद्यमों में उनकी भागीदारी समाज को लाभ पहुंचा सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों की सक्रियता और आत्मसम्मान भी बना रह सकता है।

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार, 17 अक्टूबर, 2026
दैनिक जागरण
बिजनेस
10

तीन कंपनियों को मिली आइपीओ लाने की मंजूरी

नई दिल्ली : कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने तीन कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी दी है। इन कंपनियों में फिटनेस सेवा देने वाला प्लेटफार्म कल्ट डाट फिट, ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज और एग्री-वेयरहाउसिंग फर्म सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट शामिल हैं। तीनों कंपनियों ने बीएसई और एनएसई में अपने शेयर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया है। (प्रेट्र)



टाटा समूह में नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े मतभेदों के बावजूद कंपनी वित्त वर्ष 2027-28 तक करीब 28,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर आगे बढ़ेगी।

-संजय बंगा, एमडी और सीईओ, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड

सेंसेक्स	74,729.27 ▲ 413.66	निफ्टी	23,146.15 ▲ 148.80	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,49,900 (बदलाव नहीं)	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,15,000 (बदलाव नहीं)	$ डालर	₹ 94.89 ▼ ₹ 0.10	कूड प्रति बैरल	$ 105.6

एक नजर में

पेट्रोल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया गया

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। पहले इस पर 50 पैसा प्रति लीटर का कर लग रहा था। हालांकि, डीजल निर्यात पर लगने वाले 16 रुपये प्रति लीटर के लाभ कर को घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। विमान ईंधन यानी एटीएफ निर्यात पर लग रहे 10.5 रुपये प्रति लीटर के लाभ कर को बरकरार रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि यह बदलाव 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। (प्रेट्र)

विदेशी मुद्रा भंडार में 8.5 अरब डालर की कमी

नई दिल्ली : नौ अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.578 अरब डालर घटकर 726.027 अरब डालर रह गया। इससे पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार 12.952 अरब डालर घटकर 734.606 अरब डालर पर आ गया था। आरबीआइ की ओर से शुक्रवार को जारी डाटा के अनुसार, नौ अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 7.142 अरब डालर घटकर 597.605 अरब डालर रह गई। सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.319 अरब डालर घटकर 105.094 अरब डालर रह गया। (प्रेट्र)

पंजाब नेशनल बैंक को 5,532 करोड़ का लाभ

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने शुक्रवार को बताया कि जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 13 प्रतिशत बढ़कर 5,532 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में बैंक को 4,904 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 38,185 करोड़ रुपये रही है, जो जुलाई-सितंबर 2025 में 36,214 करोड़ रुपये रही थी। इसी तरह, ब्याज से आय बढ़कर 34,585 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 31,872 करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

बायोफ्यूल की बढ़ती खपत से महंगा होगा खाद्य तेल

पश्चिम एशिया संकट के चलते अब 27 प्रतिशत वनस्पति तेल का बायोफ्यूल बनाने में हो रहा प्रयोग

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया के साथ रूस-यूक्रेन संकट के कारण न सिर्फ कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि इससे खाद्य तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका गहरा गई है। काउंसिल आफ पाम आयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज (सीपीओपीसी) के मुताबिक, अब 27 प्रतिशत वनस्पति तेल का इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने में हो रहा है। इनमें मुख्य रूप से पाम और सोयाबीन शामिल है। पिछले एक साल में खाद्य तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। वनस्पति तेल के दाम बढ़ने से सिर्फ खाद्य तेल की कीमत नहीं बढ़ती है। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्कुट व कई अन्य एफएमसीजी गुड्स की लागत इससे बढ़ जाती है क्योंकि इनमें भी पाम आयल का इस्तेमाल होता है।

- पाम आयल से बनने वाले साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्कुट और अन्य एफएमसीजी वस्तुएं होंगी महंगी
- खाद्य तेल के दाम को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने पाम तेल आयात पर शुल्क में की है कटौती



भारत में भी मक्के से बनाया जा रहा एथनाल

जानकारों का कहना है कि जिन देशों के पास पाम, सोयाबीन या फिर मक्का जैसे कच्चे माल है, उनके लिए बायोफ्यूल पेट्रोल-डीजल का सस्ता विकल्प है। भारत भी मक्के से एथनाल बनाकर पेट्रोल में इस्तेमाल कर रहा है। काउंसिल फार पाम आयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अवटूबर के आखिर में चीन में बैठक करेगा, जहां बायोफ्यूल बनाने में खाद्य तेल के बढ़ते इस्तेमाल पर विचार किया जाएगा।

इस बार सोयाबीन का उत्पादन भी होगा कम

जानकारों का कहना है कि इस बार भारत में सोयाबीन का उत्पादन भी कम है। अनुमान है कि भारत नवंबर से शुरू होने वाले तेल सीजन में करीब 56 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात करेगा। चालू सीजन में भारत 155 लाख टन वनस्पति तेल का आयात कर चुका है। पाम व सोयाबीन तेल महंगा होने से अन्य खाद्य तेल के दाम बढ़ जाते हैं।

खाद्य तेल के दाम को नियंत्रण में रखने के लिए गत सितंबर माह में सरकार ने पाम तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती तक कर दी। पश्चिम एशिया संकट का हल नहीं निकलने और वैश्विक उथल-पुथल के नए आयाम को देखते हुए पाम व सोयाबीन के बड़े उत्पादक देश ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध से पहले कच्चे तेल के दाम 65 डालर प्रति बैरल थे जो अब 100 डालर प्रति बैरल के पार चले गए हैं। इसलिए खाद्य तेल से जुड़े पाम आयल और सोयाबीन का इस्तेमाल अब बायोडीजल या बायोफ्यूल में बनाने में होने लगा है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम को देख इंडोनेशिया ने बी50 नियम लागू कर दिया है। यानी वहां पेट्रोल-डीजल में 50 प्रतिशत बायोफ्यूल मिलाया जाएगा। इससे इंडोनेशिया को कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले करीब आठ अरब डालर की बचत होगी। इंडोनेशिया पाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत सबसे अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से ही खरीदता है। इंडोनेशिया के बाद भारत को पाम तेल सप्लाई करने वाले दूसरे देश मलेशिया ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल-डीजल में 30 प्रतिशत तक बायोफ्यूल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए वहां से भी पाम तेल की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। ब्राजील और अर्जेंटीना सोयाबीन के बड़े उत्पादक देश हैं और यहां सोयाबीन से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। ब्राजील तो 100 प्रतिशत तक बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भी बायोफ्यूल बनाने में सोयाबीन और मक्के का इस्तेमाल बढ़ा दिया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आखिर गोल्ड एफओएफ में नया निवेश क्यों रोक रहे म्यूचुअल फंड



एक दर्जन से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने गोल्ड फंड आफ फंड्स (एफओएफ) में नया निवेश रोक दिया है। यह रोक शुक्रवार से प्रभावी हो गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। गोल्ड एफओएफ भौतिक सोना खरीदने के बजाय गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में पैसा निवेश करते हैं। हालांकि, म्यूचुअल फंड्स की ओर से जारी नोटिस में नया निवेश रोकने का कोई कारण नहीं बताया गया है।



इन निवेश पर होगा असर

यह रोक एकमुश्त निवेश, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआइपी में नए पंजीकरण, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) पर है। कुछ फंड हाउसों ने गोल्ड-सिल्वर फंड आफ फंड्स पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। कई फंड्स ने मौजूदा एसआइपी के स्टेप-अप (मासिक निवेश राशि को बढ़ाना) पर भी रोक लगा दी है। नोटिस के अनुसार, निवेशक अपने मौजूदा निवेश को भुनाना (रिडीम करना) जारी रख सकते हैं, जबकि पहले से पंजीकृत एसआइपी और अन्य पात्र व्यवस्थित निवेश योजनाओं के तहत किस्तों की प्रक्रिया जारी रहेगी।

सेबी के निर्देशों के बाद लगाई पाबंदी

यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले उठाया गया है, जब आमतौर पर सोने की मांग बढ़ जाती है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर लोग सोना खरीदते हैं। इन मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सेबी के निर्देशों के बाद ये पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि और भी फंड हाउस गोल्ड एफओएफ में नए सब्सक्रिप्शन पर रोक लगा सकते हैं।

इन फंड हाउसेज ने रोका नया निवेश

एसबीआइ म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जेरोधा म्यूचुअल फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, मिरे एसेट म्यूचुअल फंड, एलआइसी म्यूचुअल फंड, यूटीआइ म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड।

सितंबर में गोल्ड ईटीएफ को 4,450 करोड़ रुपये मिले



एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) के डाटा के अनुसार, सितंबर 2026 में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में 4,450 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जो इसी वर्ष अगस्त के 2,597 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है। इनक्रेड मनी के म्यूचुअल फंड्स के सीईओ नितिन अग्रवाल का कहना है कि यह सट्टेबाजी के लिए किया गया निवेश नहीं है। यह इक्विटी में आ रही गिरावट से बचाव के लिए लगाई गई पूंजी है। इनपुट-प्रेट्र जागरण इन्फो

मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी आइडीबीआइ बैंक की बिक्री प्रक्रिया

नई दिल्ली, प्रेट्र: निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने उम्मीद जताई है कि आइडीबीआइ बैंक का रणनीतिक लेनदेन चालू वित्त वर्ष के अंत (मार्च 2027) तक पूरा हो जाएगा। हालांकि, इससे पहले आरबीआइ से मंजूरी लेनी होगी। अल्पांश हिस्सेदारों और खुदरा निवेशकों के हितों को लेकर जताई गई चिंताओं पर चावला ने आश्वस्त किया कि इस लेनदेन के दौरान उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी।

शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रणनीतिक खरीदार को अल्पांश शेयरधारकों के लिए एक ओपन आफर लाना होगा। इसके अलावा, दीपम सचिव ने यह भी बताया है कि बाजार नियामक सेबी ने एलआइसी को निर्देश दिया है कि विनिवेश के बाद वह आइडीबीआइ बैंक में अपनी हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दे।

चीन के साथ बढ़ता व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच भारत की बड़ी चिंता : वित्त मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्षों की बातचीत के बावजूद चीन के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच पर लगातार लगी पाबंदियों को बड़ी चिंता का विषय बताया है। बैंकाक में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान अटलांटिक काउंसिल के साथ बातचीत में सीतारमण ने कहा कि भारत ने लगातार चीन में जेनेरिक दवाओं, गोमांस, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए बाजार तक पहुंच मांगी है। लेकिन वर्षों की बातचीत के बाद भी इसमें सीमित प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच व्यापार में गैर-शुल्क बाधाएं सबसे बड़ी रुकावट हैं। बड़े व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर दंडात्मक शुल्क लगाने का तरीका नहीं अपनाया है, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने को प्राथमिकता दी है, भले ही इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा।



निर्मला सीतारमण ●

- सीतारमण ने कहा, वर्षों की बातचीत के बाद भी बाजार पहुंच मामले में सीमित प्रगति
- भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई

चीन बोला, भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार

बीजिंग, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजार तक पहुंच पर पाबंदियों की आलोचना किए जाने के बाद, चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत के साथ मिलकर "एक-दूसरे" की आर्थिक और व्यापारिक चिंताओं को दूर करने के लिए काम करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मैं बस इतना कह सकती हूं कि चीन कभी भी 'ट्रेड सरप्लस' (व्यापार अधिशेष) का लक्ष्य नहीं रखता। हम भारत के साथ मिलकर एक-दूसरे की आर्थिक और व्यापारिक चिंताओं को संतुलित तरीके से दूर करने और द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

7.1-7.3% रह सकती है भारत की वृद्धि दर

नई दिल्ली, प्रेट्र: डेलाइट इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1 से 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। निजी निवेश में लगातार सुधार से मांग को अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है। पेशेवर सेवा देने वाली कंपनी ने कहा है कि भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापार में व्यवधान वृद्धि की संभावनाओं के लिए जोखिम बने हुए हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डेलाइट का जीडीपी वृद्धि अनुमान आरबीआइ और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के 7.1 प्रतिशत के अनुमान के बराबर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज ने सात प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

डेलाइट के आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2027-28 में 6.6 से 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

राष्ट्रीय फलक

अंकिता के माता-पिता से मिले सीबीआइ अधिकारी, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा



सुरेश राठौर, उर्मिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग की

<< नई दिल्ली में शुक्रवार को सीबीआइ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: उत्तराखंड के ऋषिकेश में वर्ष 2022 में मृत पाई गई 19 वर्षीय रिसार्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के माता-पिता ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने उन्हें मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।

सीबीआइ के अनुसार, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की। विशेष निदेशक मनोज शशिधर और संपत मीणा ने आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। सीबीआइ ने मामले में कथित 'वीआइपी' की भूमिका की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, अंकिता के माता-पिता ने पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट कराने की मांग की।। हालांकि, परिणामों का कोर्ट में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

एआइ एजेंटों ने भारतीय संगठनों के गोपनीय डाटा में लगाई सेंध

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को बढ़ता इस्तेमाल साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन रहा है। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने गंभीर चेतावनी जारी कर बताया है कि एआइ एजेंटों ने भारतीय संगठनों के गोपनीय डाटा में सेंध लगाई।

वहीं विशेषज्ञों ने इनकी पहुंच सीमित करने और मानवीय निगरानी बनाए रखने की सलाह दी है। इस बीच सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि महत्वपूर्ण संगठनों की कोई भी अहम जानकारी लीक नहीं हुई है, और इस घटना को शुरुआती चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। सभी कंपनियों को साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए और सिस्टम की असामान्य गतिविधियों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि एआइ संबंधी नियम बनाने को लेकर जल्द ही परामर्श पत्र जारी किए जाने की संभावना है। इनमें आटोनामस एआइ एजेंटों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि भविष्य में एआइ संबंधी नियमों के जरिये एआइ एजेंटों से जुड़े जोखिमों को कैसे दूर किया जा सकता है। 'एआइ एजेंट्स ऐज अटैक वेक्टर्स' शीर्षक वाले अपने परामर्श (सीआइएडी-2026-0049) में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने बताया कि एआइ माडल बनाने वाली कंपनियों ने खुद ही स्वीकारा है कि उनके आटोनामस एआइ माडल और एजेंट निर्धारित कोर्यों के लिए मिली अनुमति की सीमा से आगे निकल गए तथा भारतीय संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाई।

गौर करने वाली बात यह है कि प्रभावित संगठनों में से किसी ने भी खुद इस एक्सेस को पता नहीं लगाया। यह घटना तब सामने आई जब एआइ माडल बनाने वाली कंपनी ने आंतरिक समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। सीईआरटी-इन ने पाया कि साइबर अपराधियों ने एआइ टूल को इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए साइबर हमले करने में किया।

- साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने जारी की चेतावनी
- विशेषज्ञों ने कहा- एआइ एजेंटों की पहुंच सीमित करें



प्रतीकात्मक

बच्चों को इंटरनेट मीडिया के खतरों से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया से जुड़े कथित खतरों से बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके अकादमिक निदेशक सिद्धार्थ सिंह गिरनार की याचिका पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किए। पीठ ने इस याचिका को पहले से लंबित एक याचिका के साथ संबद्ध कर दिया और सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि बच्चों को इंटरनेट मीडिया से जुड़े खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रतिवादियों की विफलता को मनमानी, अनुचित और संविधान का उल्लंघन घोषित किया जाए। इन खतरों में यौन शोषण, साइबर बुलिंग, उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने, उनके व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने, इंटरनेट मीडिया की लत लगने और अन्य नुकसान शामिल हैं। याचिका में अनिवार्य आयु सत्यापन, उम्र के अनुरूप इंटरनेट मीडिया तक पहुंच, माता-पिता की सहमति और साइबर बुलिंग, यौन शोषण, हानिकारक सामग्री तथा इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का अनुरोध भी किया गया है।



यौन शोषण, साइबर बुलिंग, हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने से बचाने का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

एथेनाल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक

मुंबई, रायटर: केंद्र सरकार ने 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनाल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियों की नई निविदा में गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनाल को शामिल नहीं किया गया है।

शुक्रवार को जारी निविदा के अनुसार, इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नवंबर से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए 1,100 करोड़ लीटर एथेनाल की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं। अब उत्पादक मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त चावल से एथेनाल बनाने के लिए बोली लगा सकेंगे। कम बारिश के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। सरकार घरेलू चीनी आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है।

युवा उद्यमियों की कंपनियों का मूल्यांकन एक वर्ष में 23% बढ़ा

48 लाख करोड़ रुपये हुआ युवाओं की कंपनियों का मूल्य, उद्यमियों की संख्या भी बढ़कर 180 हुई

मुंबई, प्रेट्र: पिछले एक साल में 35 साल के कम उम्र के युवा उद्यमियों की ओर से संचालित कंपनियों का कुल मूल्यांकन एक वर्ष में 23 प्रतिशत बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। शुक्रवार को जारी एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया यू35 सूची 2026 में युवाओं की संख्या भी 16 बढ़कर 180 हो गई है, जो पिछले साल 155 थी। इस सूची में कारोबार चलाने वाले संस्थापक और उत्तराधिकारी शामिल हैं।

सूची में पहली पीढ़ी के वे संस्थापक हैं, जिन्होंने कम से कम पांच करोड़ डालर मूल्य के उद्यम खड़े किए हैं। अगली पीढ़ी के वे उद्यमी भी शामिल हैं, जो 10 करोड़ डालर से अधिक मूल्य के पारिवारिक कारोबार चला रहे हैं। हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने बताया कि सूची में 100 करोड़ डालर से अधिक मूल्यांकन वाली 37 कंपनियां हैं, जिनमें कुल 5.88 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। सूची के 180 उद्यमियों में 71 प्रतिशत पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं।

सूची के अनुसार, एआइ और मशीन लर्निंग क्षेत्र से जुड़े लोगों की संख्या चार गुना बढ़कर 12 हो गई है। अंतरिक्ष, रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र के संस्थापकों की संख्या भी बढ़ी है। सूची में शामिल संस्थापकों की औसत उम्र 33 साल है। गोल्डियम इंटरनेशनल के अनमोल भंसाली 31 साल की उम्र के साथ सबसे युवा उद्यमी हैं।

इसमें 23 महिलाएं हैं और फाक्सटेल की रोमिता मजूमदार सबसे युवा हैं। स्नातक संस्थानों में आइआइटी दिल्ली के 11 पूर्व छात्र सूची में हैं। आइआइटी खड़गपुर के 10 और आइआइटी मद्रास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के 7-7 पूर्व छात्र शामिल भी हैं।

एनजीटी ने सीपीसीबी से माइक्रोप्लास्टिक मामले में आठ सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को विभिन्न पर्यावरणीय मानकों के तहत माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग और उनकी पहचान करने की एक समान पद्धति विकसित करने पर प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की पीठ ने भारतीय नमक और ब्रांडेड चीनी में सूक्ष्म प्लास्टिक की मौजूदगी और मानव रक्त में इसका पता चलने से जुड़ी खबरों के आधार पर शुरू हुई कार्यवाही की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी के उस अनुरोध को मान लिया, जिसमें प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की गई थी।

मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी, 2027 को होगी। 13 अक्टूबर की अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी ने मीठे पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग, नमूने तैयार करने और उनका विश्लेषण करने की पद्धति विकसित करने पर सहमति जताई है।

- नमक व ब्रांडेड चीनी में सूक्ष्म प्लास्टिक की मौजूदगी की खबरों पर कार्यवाही
- मीठे पानी व मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की सैंपलिंग पर जताई सहमति



प्रतीकात्मक

भारत को 2035 तक 29 लाख अतिरिक्त हास्पिटल बेड की जरूरत

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत को 2035 तक वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के मानकों तक पहुंचने के लिए लगभग 29 लाख अतिरिक्त हास्पिटल बेड की जरूरत है।

रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई साउथ एशिया की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए 2.6 अरब वर्ग फुट अतिरिक्त हेल्थकेयर स्पेस की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 1.6 अस्पताल बिस्तर हैं, जो 3.3 प्रति 1,000 के वैश्विक औसत से काफी कम है। इस अंतर को पाटने के लिए, भारत में हेल्थकेयर रियल एस्टेट के कुल दायरे को 2025 में अनुमानित 2.1 बिलियन वर्ग फुट से काफी अधिक बढ़ाने की जरूरत होगी। यह जरूरत डेवलपर्स, निवेशकों और हेल्थकेयर आपरेटरों के लिए एक बड़ा अवसर पेश करती है।"

हेल्थकेयर में निवेश अब तेजी से विशेष सुविधाओं, डे-केयर फार्मेट और

- सीबीआरई साउथ एशिया की जारी रिपोर्ट में किया गया दावा



प्रतीकात्मक

अधिग्रहण के जरिए विस्तार की ओर बढ़ रहा है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में, वहां मौजूद गैर-संचारी रोगों के बोझ की तुलना में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में गैर-संचारी रोगों के बोझ की तुलना में अस्पताल बिस्तरों की संख्या कम है। इनमें सुधार की जरूरत है।

प्रेरणा

साहसी व्यक्ति ही अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ सकता है। –विष्णु प्रभाकर

संपादकीय

देश के कुछ राज्यों में उद्यम का माहौल हमें बढ़ाना होगा

आरबीआई बुलेटिन में छपे एक ताजा अध्ययन के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन का 67.1 प्रतिशत औद्योगिक राज्यों को मिला है। इनमें पश्चिम से गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे बड़ा शेयर (करीब 37.1 प्रतिशत) और दक्षिण के तमिलनाडु, आन्ध्र और कर्नाटक को (18 प्रतिशत) मिला है। उत्तर भारत का मात्र एक राज्य राजस्थान 11.1 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इस राज्य के उद्यमिता विस्तार का मूल कारण भौगोलिक है। यहां हल के समय में सौर व पवन ऊर्जा के संयंत्र निजी क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसके विपरीत उत्तर और पूर्वी भारत के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों का हिस्सा मात्र 17-19 प्रतिशत है, जो अकेले महाराष्ट्र या गुजरात से कम है। यूपी, बिहार और एमपी का देश की आबादी में हिस्सा एक-तिहाई से ज्यादा होते हुए भी ऐसे ऋणों में हिस्सा मात्र 11 प्रतिशत होना बताता है कि या तो इन राज्यों में उद्यमिता का आज भी अभाव है या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यहां के उद्यमियों की सफलता पर भरोसा नहीं है। आखिर इन राज्यों में उद्यमिता की कमी क्यों है? यूपी में एक्सप्रेस-वे में निजी-सार्वजनिक पार्टनरशिप सर्वाधिक होते हुए भी लोन में कुल हिस्सा 5.5 प्रतिशत ही है, जबकि बिहार का 0.5-0.7 प्रतिशत और एमपी का 2.5-3.2 प्रतिशत। इन राज्यों से शायद ही कोई प्रपोजल संस्थाओं/बैंकों को मिलते हैं।

जीने की राह



पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

सुबह उठा कैसे जाए, इस पर बड़ी गम्भीरता से काम करिए

श्रीराम और रावण के युद्ध के सातवें दिन एक ऐसी घटना घटती है, जो हमें चेतावनी और समझ, दोनों देती है। इस दिन जब रावण युद्ध में आया तो तुलसीदासजी ने लिखा- भीरु भईं रथ चढ़ पुनि धावा। सुबह होने पर रावण रणांगण में रथ पर चढ़कर आया। रावण दुर्गुणों का प्रतीक है। हमारे जीवन में सुबह-सुबह भी दुर्गुणों का प्रवेश होता है। इसलिए सुबह उठा कैसे जाए, इस पर बड़ी गम्भीरता से काम करिए। उठते समय हनुमान चालीसा का स्मरण अवश्य करें। इसी का प्रयोग 19 अक्टूबर को जयपुर में किया जा रहा है। महापर्व के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पूरे विश्व में सामूहिक पाठ हो, ऐसा आह्वान किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। हनुमान चालीसा का महापाठ हमें समझाएगा कि नजरें तो सबके पास रहती हैं, असल बात तो नजरिए की है। जो रावण किसी से नहीं डरा, वह हनुमान जी से बहुत डरता था। इसीलिए हनुमान चालीसा दुर्गुणों के मामले में हमारे लिए कवच बन जाएगी।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

डिफ्रेंट एंगल • न कतार तोड़ें, न जल्दी में काम करें

अनुशासन 'नाजुक' होता है, उसका ख्याल रखना जरूरी

डिसिप्लिन



श्रीप्रकाश श्रीधरन
लेखक और स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट

हाल ही में बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान मैंने एक ऐसी घटना देखी, जिसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा।

ज्योतिर्मठ के पास सड़क का एक संकरा हिस्सा है, जहां पहाड़ी इलाके में जाम से बचने के लिए वाहनों की आवाजाही को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। यातायात को व्यवस्थित ढंग से चलने दिया जाता है और वाहन एक ही कतार में आगे बढ़ते हैं।

उस दिन सभी चालक नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे गिने-चुने वाहन भी अनुशासन बनाए हुए थे।

लेकिन पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक अधीर झुंडवर ही काफी था!

एक कार कतार तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पलों में दर्जनों अन्य वाहन भी उसके पीछे चल पड़े। जो यातायात शुरू में सुचारु और नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ रहा था, वह देखते ही देखते पूरी तरह बेतरतीब हो गया। सड़क के उस संकरे हिस्से में दोनों दिशाओं से आ रहे वाहन एक-दूसरे में उलझ गए और भीषण जाम लग गया।

जब मैंने एक चालक को नियम तोड़ने से रोकने की कोशिश की, तो वह मेरे पास से तेजी से निकला और मुझे टक्कर मारते बचा।

उसके पास अपने इस कृत्य के लिए एक सीधा-सा तर्क था : 'जब सब लोग नियम तोड़ रहे हैं, तो मैं ही नियम का पालन करने वाला बेवकूफ क्यों बनूं?'

उसके इस जवाब ने एक असहज सच्चाई उजागर कर दी। इससे पहले ज्यादातर लोग धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वे नियमों का सम्मान करते थे। वे बस इस इंतजार में थे कि कोई दूसरा पहले नियम तोड़े। ऐसा होते ही बाकी भी उसी के पीछे चल पड़े।

नतीजा पहले से तय था : जिस प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाना चाहिए था, वह सबके लिए एक घंटे की मुसीबत बन गई।

कार्यस्थलों पर भी मैंने अकसर इसी तरह का व्यवहार होते देखा है। लोग अकसर सही काम करने के बजाय सुविधाजनक रास्ता चुन लेते हैं।

मसलन, मैंने कई बार देखा है कि टीमें ग्राहकों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री तैयार करने के लिए आखिरी क्षणों में अफरातफरी से जुट जाती हैं, जबकि उनके पास काफी समय होता है कि वे पहले से काम शुरू करके उसे आराम से पूरा कर सकें।

लेकिन जाने क्या कारण है कि अत्यधिक दबाव में येन-केन-प्रकारेण किसी काम पूरा करने को ही गौरव की बात मान लिया जाता है और पहले से योजना बनाकर समय से काम पूरा करने को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अफरातफरी की प्रक्रिया में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे बचा जा सकता था। जल्दबाजी में ऐसे फैसले भी ले लिए जाते हैं, जिनसे बेवजह तनाव पैदा होता है।

प्रजेंटेटर और रिव्यूअर, इन दोनों ही भूमिकाओं में इन परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद मैं जानता हूं कि लोग अकसर उन गलतियों से उबरने के लिए किस तरह जूझते हैं, जिन्हें पहले ही रोका जा सकता था।

मनोवैज्ञानिक इस प्रवृत्ति को 'न्यूनतम प्रयास का नियम' (लॉ ऑफ लीस्ट इफेक्ट) कहते हैं। यातायात की उस घटना और कार्यस्थल की परिस्थितियों, दोनों में ही लोग शुरू में वह रास्ता चुनकर तत्काल संतुष्टि पाना चाहते हैं, जो उन्हें अपेक्षाकृत आसान लगता है। लेकिन अल्पकालिक लाभ अकसर बाद में और अधिक परेशानी का कारण बनता है- चाहे वह ट्रैफिक जाम में फंसना

कई लोग धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार इसलिए नहीं करते कि वे नियमों का सम्मान करते हैं। इसके उलट, वे इस इंतजार में रहते हैं कि कोई दूसरा पहले नियम तोड़े। ऐसा होते ही वे भी उसी के पीछे चल पड़ते हैं। अनुशासन इसी से भंग होता है।

हो या आखिरी क्षणों की अफरातफरी से जूझना।

समय के साथ-साथ इन अनुभवों से सीखकर मैंने कुछ सिद्धांत अपनाए हैं, जो मुझे तात्कालिक आराम के बजाय दीर्घकालिक सफलता को प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। वे इस प्रकार हैं :

1. दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लें।
2. तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लाभ को चुनें।
3. पहले से योजना बनाएं, काम जल्दी शुरू करें और आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा मानसिक तैयारी रखें।
4. यात्र रखें कि चरित्र बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे बिगाड़ने के लिए कुछ पल ही काफी हैं।
5. कुछ भी करने से पहले एक बार गम्भीरता से जरूर विचार कर लें।

और अंत में, दार्शनिक प्लेटो की इस बात को सदैव याद रखें : 'सबसे पहली और सबसे बड़ी विजय स्वयं पर ही जीत है।'

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • अब ओलिम्पिक पदकों पर हो हमारी नजर

हमें राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से आगे बढ़ना चाहिए

स्पोर्ट्स



बोरिया मजुमदार
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सहलेखक और खेल पत्रकार

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और ओलिम्पियन डॉ. एडिल जे. सुमरीवाला ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का स्तर उठाने के लिए एक अच्छा सुझाव दिया है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीतने पर नकद प्रोत्साहन राशि देनी बंद कर देनी चाहिए। अब हमारा लक्ष्य ओलिम्पिक खेल होने चाहिए। उनका यह सुझाव ऐसे समय आया है, जब हाल के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारों द्वारा भारी-भरकम पुरस्कारों की घोषणाओं की खबरें सामने आई हैं। एडिल कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों का ध्यान नहीं रखा जाता। खेल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और सहायता दी जाती हैं। अगर उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी भी जानी है, तो वह ओलिम्पिक और हर दो साल में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप के लिए ही दी जानी चाहिए। ये ही सर्वोच्च स्तर की प्रतियोगिताएं हैं और हमें इन्हें ही लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें अब अपना स्तर ऊंचा उठाकर राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से आगे बढ़ना चाहिए।

इस बात में तो कोई संदेह नहीं हो सकता कि वैश्विक प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन ही खेलों में हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। अगर ओलिम्पिक के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी जाती है तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारा मानक ओलिम्पिक ही होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। एडिल का सुझाव इसलिए क्रांतिकारी है, क्योंकि इसका मकसद उत्कृष्टता के वास्तविक स्तर तक पहुंचना है। हम देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक हासिल करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। वे इन प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और इनमें जीतने का पर्याप्त अनुभव भी हासिल कर चुके हैं। अगर उन्हें वास्तव में अपनी उपलब्धियों को निर्णायक बनाना है, तो ओलिम्पिक स्तर पर ऐसा करके दिखाना होगा।

कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होकर प्रतियोगिता से हट जाने के मामलों की भी गहराई से जांच करके यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। साथ ही, खिलाड़ियों तथा कोचों को अधिक जवाबदेह बनाना भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में नगद पैसा दिए जाने की जरूरत है? आज तो खिलाड़ियों को एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इसके चलते यह भी देखा जाता है कि कुछ खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद अपनी खराब फिटनेस को छिपाते हैं और प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करते हैं। उनके कोच इस पर जोर देते हैं कि चोट मामूली है और प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी अपनी फिटनेस पा लेगा। हाल ही में जापान के नागोया में हुए एशियाई खेलों में भी यह देखा गया था। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

यह भी देखा जाता है कि खिलाड़ी पर्याप्त मेहनत से प्रशिक्षण नहीं लेते और एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के स्तर पर जीत हासिल करके ही संतुष्ट रहते हैं। दरअसल, हमारे कुछ विदेशी कोचों ने यह शिकायत भी की है कि हमारे खिलाड़ी अगले एशियाई खेलों के लिए अभी से खुद को बचाकर रखने की कोशिश में जुट जाते हैं। जबकि खिलाड़ी के लिए सबसे बड़कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का

देखा जाता है कि खिलाड़ी एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों के स्तर पर जीत हासिल करके ही संतुष्ट रहते हैं। यह शिकायत भी मिली है कि खिलाड़ी अगले एशियाई खेलों के लिए अभी से खुद को बचाकर रखने की कोशिश में जुट जाते हैं।

सम्मान होना चाहिए।

मैं राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में केवल भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को पैसे न देने और पुरस्कारों की राशि घटाने के उपरोक्त सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं। इससे खिलाड़ियों को चोट के बावजूद प्रतियोगिता में जाने का मामूली-सा जोखिम लेने से रोका जा सकेगा। यदि खिलाड़ी और कोच जानते हों कि वहां कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और इसके उलट चोटिल होने के बावजूद प्रतियोगिता में जाने पर खिलाड़ी और कोच से जवाब-तलब भी किया जा सकता है, तो जापान में ज्योति याराजी और प्रवीण चित्रवेल के मामले में जो हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जापान पहुंचने के बाद चोटों के कारण खेलने में असमर्थता जता दी थी!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

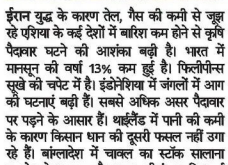
17 अक्टूबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी में मशीनों के विज्ञान पर हावी होने और समाज पर उसके प्रभावों की पड़ताल की है। मैग्जीन ने सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में मंदी की आशंकाओं पर भी नजर डाली है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

कमजोर मानसून से कई एशियाई देशों में समस्याएं



ईरान युद्ध के कारण तेल, गैस की कमी से जूझ रहे एशिया के कई देशों में बारिश कम होने से कृषि पैदावार घटने की आशंका बढ़ी है। भारत में मानसून की वर्षा 13% कम हुई है। फिलीपीन्स सूखे की चपेट में है। इंडोनेशिया में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। सबसे अधिक असर पैदावार पर पड़ने के आसार हैं। थाईलैंड में पानी की कमी के कारण किसान धान की दूसरी फसल नहीं उगा रहे हैं। बांग्लादेश में चावल का स्टॉक सालाना उपभोग से 4% कम है। भारत, श्रीलंका सहित कई देशों में खाने की चीजों की महंगाई बढ़ी है।

जापान की प्रोफेशनल सूमो कुश्ती अब अमेरिका पहुंची

जापान के सूमो पहलवानों की कुश्ती अमेरिका में शुरू हो गई है। 10 अक्टूबर को ऑस्टिन, टेक्सास में सूमो चैम्पियनशिप लीग के मुकाबले हुए। यह लीग जापान और आसपास के देशों के बाहर पहली बार हुई है। इसमें 16 पहलवानों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के सीओओ रहे स्टुअर्ट स्नाइडर ने लीग शुरू की है। उन्होंने लगभग 48 करोड़ रु. का निवेश किया है। स्नाइडर को उम्मीद है कि अमेरिकियों को एशियाई परंपरा से जुड़ी यह कुश्ती पसंद आएगी।

चीन मैन्युफैक्चरिंग के नए क्षेत्र थ्री-डी प्रिंटिंग में हावी

चीन ने शौक के बतौर खिलौने और अन्य प्रोडक्ट बनाने में काम आने वाले थ्री-डी प्रिंटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में नई पहचान बनाई है। यह चीन का सबसे सफल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। साल के पहले छह महीनों में इन मशीनों का निर्यात 90% बढ़ गया। वैश्विक बाजार में चीन का हिस्सा 19% से बढ़कर 96% हो गया है। चीन ने अमेरिका में आविष्कृत थ्री- डी प्रिंटर्स में पश्चिमी देशों की कंपनियों का दबदबा खत्म कर दिया है। इसके एआई की मदद से यूजर टूल्स, कलपुर्जे और टॉय सहित कई चीजें बना सकते हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी गणित की सैकड़ों जटिल समस्याएं सुलझाने का दावा; मशीनी निर्मरता से वैज्ञानिकों में डर

एआई से नए वायरस और दवाएं बनाने की संभावनाएं बढ़ीं, लेकिन विज्ञान पर नियंत्रण का खतरा भी बढ़ा

एआई की तेज प्रगति विज्ञान की दुनिया में नई संभावनाओं के साथ गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। मशीनें जटिल वैज्ञानिक समस्याएं सुलझाने में सक्षम हो रही हैं, लेकिन चिंता है कि कहीं इंसान वैज्ञानिक खोजों की समझ और नियंत्रण ही न खो दें। एआई से नए जीव बनाने जैसी संभावनाएं भी जोखिम बढ़ा सकती हैं।

6 अक्टूबर 2026 को ओपनएआई ने 700 से अधिक अकादमिक शोधपत्र जारी किए। इनमें 372 ऐसी गणितीय समस्याओं को सुलझाने या उनमें प्रगति करने का दावा किया गया, जो दशकों से शोधकर्ताओं के सामने चुनौती बनी हुई थीं। इस उपलब्धि ने गणितज्ञों के बीच बहस छेड़ दी है कि एआई से मिलने वाले सही उत्तरों का क्या महत्व है, यदि इंसान उनके पीछे का तर्क ही न समझ सके। 900 से अधिक विद्वानों के समूह एसोसिएशन फॉर ह्यूमन मैथमेटिक्स ने एआई के बढ़ते दखल पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि गणित का उद्देश्य सिर्फ सही उत्तर हासिल करना नहीं, बल्कि प्रमाण और मेहनत के जरिए मानवीय समझ को आगे बढ़ाना भी है। एआई से ऐसे समाधान मिलना, जिन्हें इंसान समझ न सके, विद्यार्थियों को सीधे होमवर्क के उत्तर देने जैसा है। एआई कंपनियां विज्ञान में निवेश को केवल मानव कल्याण के लिए नहीं कर रहीं। वैज्ञानिक समस्याएं सुलझाने से एआई मॉडल अधिक सक्षम हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वैज्ञानिक खोजों में बेहतर मॉडल अन्य क्षेत्रों में भी अधिक कुशल साबित होंगे। इससे बड़ी एआई कंपनियों का दबदबा बढ़ सकता है। वे खुद को बेहतर बनाने वाले मॉडलों पर नियंत्रण हासिल कर सकती हैं। भविष्य में ऐसे मॉडल रोबोट और लैब के उपकरणों से जुड़कर वास्तविक दुनिया में प्रयोग भी कर सकेंगे, लेकिन यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि उनकी खोजें हमेशा मानवता के हित में हों। यदि समाज हर वैज्ञानिक और सामाजिक फैसले के लिए मशीनों पर निर्भर हो गया, तो इंसान स्वतंत्र समझ और निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं।

बैक्टीरिया नष्ट करने वाले वायरस बनाने के प्रयास



एआई की मदद से विज्ञान के कई क्षेत्रों में और बड़ी प्रगति होना लगभग तय है। इसकी सबसे रोमांचक संभावनाएं जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिख रही हैं। शोधकर्ता एआई की मदद से सूखा झेलने वाली फसलें विकसित करने, नई दवाएं खोजने और ऐसे वायरस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये वायरस हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करके उन्हें नष्ट करते हैं।

एआई मॉडल से नए जीव बनाने की क्षमता हासिल होगी

कोशिकाओं के काम करने का तरीका जानने के लिए एआई की मदद से इसके कंप्यूटर मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खोज से वैज्ञानिक पूरी तरह से नए जीवों को बनाने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो डीएनए कंप्यूटर कोड का एक रूप बन जाएगा। इससे एआई मॉडल में टोकन की एक शृंखला की तरह हेरफेर किया जा सकता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

कम्युनिकेशन

मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में उतरेगी मस्क की स्टारलिंक

इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के 1.2 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत ग्राहक हो गए हैं। अब कंपनी मोबाइल नेटवर्क कारोबार में उतरकर टी-मोबाइल, एटीएंडटी और वेरिजॉन जैसी कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

8 अक्टूबर को स्पेसएक्स ने पुष्टि की है कि वह पूर्ण मोबाइल फोन नेटवर्क बनाएगी और बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी। इसके बाद अमेरिका की इन तीनों प्रमुख मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। इस योजना के तहत स्पेसएक्स अपने सैटेलाइट नेटवर्क का विस्तार करेगी। कंपनी के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने मोबाइल कॉल और स्मार्टफोन डेटा सेवाओं के लिए 15 हजार सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दी है। कंपनी ने टी-मोबाइल के साथ भी करार किया है, जिसके तहत स्टारलिंक के जरिए मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, सैटेलाइट से शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में बेहतर कवरेज देना चुनौती है। इसलिए स्पेसएक्स जमीन पर भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बना रही है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिजनेस सेमीकंडक्टर कंपनियों का इंडेक्स 10 दिन में 10% से ज्यादा गिरा

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मंदी में फंसने का खतरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती मांग से चिप उद्योग में तेजी है, लेकिन इसके बीच मंदी की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। शानदार नतीजों के बावजूद प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों का सूचकांक 6 अक्टूबर से 10% से ज्यादा गिर चुका है। उद्योग की अनुमानित वृद्धि का बड़ा हिस्सा एआई चिप्स पर निर्भर है। ऐसे में एआई पर खर्च घटा तो चिप कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इस बार मंदी का असर पहले जैसा व्यापक नहीं हो सकता। इसकी वजह चिप निर्माण का कुछ ही कंपनियों तक सीमित होना है।

जहां 2000 के दशक की शुरुआत में करीब 25 कंपनियां सबसे उन्नत प्रोसेसर बना सकती थीं, वहीं अब ऐसी केवल चार कंपनियां हैं। ताइवान की टीएसएमसी हाई-एंड प्रोसेसर बनाने वाली प्रमुख कंपनी है। इसी तरह, उन्नत मेमोरी चिप्स का उत्पादन भी सैमसंग, एसके हायनिक्स और माइक्रोन जैसी तीन कंपनियों के हाथों में सिमट गया है। मांग पूरी करने के लिए कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं। टीएसएमसी का खर्च इस साल करीब 5.88 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं, मेमोरी चिप निर्माता भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। सीमित आपूर्तिकर्ताओं के कारण खरीदारों को पहले से अनुबंध करने पड़ रहे हैं। एनवीडिया ने जनवरी 2029 तक चिप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 23.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे किए हैं। माइक्रोन का सितंबर 2030 तक उसकी अनुमानित आय का 35% हिस्सा ऐसे अनुबंधों से सुरक्षित है, जिनमें खरीदार को चिप्स न लेने पर भी भुगतान करना होगा। ऐसे अनुबंध नई फैक्ट्रियों के निवेश में मदद करते हैं और मंदी का कुछ जोखिम खरीदारों पर डालते हैं। हालांकि, एआई पर खर्च घटा तो चिप की कीमतें, मुनाफा और शेयर भाव गिर सकते हैं। यानी सीमित प्रतिस्पर्धा कंपनियों को सुरक्षा देती है, लेकिन मंदी का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं करती।

इस साल बिक्री में 46 साल की सबसे तेज ग्रोथ भी



2026 की पहली छमाही में सेमीकंडक्टर की बिक्री में 1980 के दशक के बाद से किसी भी अवधि की तुलना में सबसे तेज सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। टीएसएमसी ने लगातार छठवीं तिमाही में रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया। वहीं दक्षिण कोरियाई चिप दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी लगातार चौथी रिकॉर्ड तिमाही दर्ज की।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

एक्सरसाइज तेज गति से चलने से होता है फायदा

रोज 7 हजार कदम चलने से असमय मृत्यु का खतरा 47 फीसदी तक घट सकता है

पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके लिए रोज 10 हजार कदम चलना जरूरी नहीं। 2025 में लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, प्रतिदिन 7 हजार कदम चलने से असमय मृत्यु का जोखिम 47%, हृदय रोग का 25% और डायबिटीज का खतरा 14% तक कम हो सकता है। वहीं, 2 हजार से कदम बढ़ाकर 4 हजार करने पर भी मृत्यु का जोखिम 36% तक घटता है।

शोधकर्ताओं ने 2014 के बाद प्रकाशित 57 अध्ययनों का विश्लेषण कर कदमों की संख्या और स्वास्थ्य के बीच संबंध का आकलन किया। अध्ययन का नेतृत्व करने वाली सिडनी विश्वविद्यालय की महामारी विज्ञानी मेलोडी डिंग के मुताबिक, 7 हजार कदमों के बाद अतिरिक्त कदमों से मिलने वाला फायदा कम होने लगता है। रोज 7 हजार से 10 हजार कदम चलने पर मृत्यु के जोखिम में केवल 2% की अतिरिक्त कमी देखी गई। कदमों की संख्या के साथ चलने की



गति भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इसे प्रति मिनट उठाए गए कदमों यानी 'कैडेंस' से मापते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी गति से चलना फायदेमंद है, जिससे हृदय गति बढ़े और सांस कुछ तेज चले। सितंबर में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार तेज गति से चलने वालों में भी मृत्यु के जोखिम में उल्लेखनीय कमी पाई गई है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

वैल्यू फॉर मनी • फेस्टिव सीजन में खरीदारी 29 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान; ऑर्डर की संख्या बढ़ रही, पर औसत बास्केट साइज नहीं, कपड़े, ग्रॉसरी, गहने टॉप पर

बटुआ खुला, पर खर्च सोच-समझकर; इस साल त्योहारों में जरूरत, वैल्यू, यूटिलिटी देखकर खरीदारी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

त्योहारों पर भारतीयों का बटुआ खुल रहा है, लेकिन हर रुपया सोच-समझकर खर्च हो रहा है। खरीदार प्रोडक्ट को कीमत, वैल्यू और यूटिलिटी की तराजू पर तौल रहे हैं। यानी खर्च कायम है, पर खरीद ज्यादा चुनिंदा हो गई है।

मार्केट रिसर्च फर्म डेटम इंटेलिजेंस के अनुमान के मुताबिक, इस साल ऑनलाइन फेस्टिव सेल ₹1.50-1.55 लाख करोड़ की रह सकती है। 2025 में यह ₹1.20 लाख करोड़ की थी। इसका मतलब है कि इस साल त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी 25-29% बढ़ेगी।

सर्वे • बजट नहीं घटाया, पर स्मार्ट खरीदारी होगी

- **26%** बजट वही, पर समझदारी से खरीदेंगे
- **49%** लोगों ने बताया कि ब्रांड चुनते समय क्वालिटी को अहमियत देंगे
- **14%** पिछले साल से ज्यादा खर्च करेंगे
- **23%** गैर-जरूरी खरीद में कटौती करेंगे
- **42%** का कीमत या डिस्काउंट पर फोकस

पैटर्न • बार-बार खरीदारी हो रही, पर बिल कंट्रोल में

डेटम के मुताबिक, ऑर्डर बढ़े हैं, पर औसत बास्केट साइज नहीं। बार-बार खरीदारी हो रही है, पर हर बार ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। कपड़ों, गाड़ियों, गहनों में यही पैटर्न देखा जा रहा है।

फेस्टिव प्लान • कपड़ों पर 47%, गहनों पर 27% खर्च

श्रेणी	खर्च में हिस्सा	कटौती
कपड़े-फैशन	47%	27%
मिठाई-ग्रॉसरी	36%	13%
गहने	27%	38%
बाहर खाना	12%	22%

स्रोत: यूपीए इंडिया फेस्टिव सोशियो रिपोर्ट, 2026

कपड़े • चंडीगढ़, जयपुर और सूरत जैसे टियर-2 शहरों में मांग चार गुना



65%
फैशन कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं अब तक, जबकि कच्चा माल महंगा होने से उनकी लागत बढ़ी है, ग्राहकों के लिए ये बड़ी राहत।

क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के सर्वे में 30% ने बिक्री पिछले साल जैसी रहने की बात कही। 52% कंपनियों ने पिछले साल से बेहतर बिक्री की उम्मीद जताई। गिरावट की आशंका हर पांच में से एक से भी कम को है। कपड़ों की बिक्री में ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्सेदारी अब भी करीब 12% ही है।

पसंद: 45% के मुताबिक कुर्ता, सलवार सूट और चूड़ीदार जैसे परिधान सबसे ज्यादा बिकेंगे। टी-शर्ट-डेनिम दूसरे नंबर पर रहेंगे।
पूरा लुक: अमेजन फैशन के डायरेक्टर निखिल सिन्हा के मुताबिक, ग्राहक आइटम नहीं, पूरा लुक खरीद रहे हैं। चंडीगढ़, जयपुर, सूरत में मांग 4 गुना हुई।
अलग अंदाज: फ्लिपकार्ट के वीपी कपिल थिरानी के मुताबिक, युवा अलग-अलग मौकों के लिए अलग लुक चुन रहे हैं।
कंपनियों की रणनीति: 54% फैशन कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठा रही हैं, सिर्फ 35% ने दाम बढ़ाए हैं।
स्रोत: सीएमएआई, यूगोव

कारों की मांग तेज • ग्रामीण बाजारों में 53% तक पैठ

मारुति सुजुकी: 1 अक्टूबर तक 2 लाख से ज्यादा बुकिंग लंबित हैं। ग्रामीण पैठ बढ़कर 53% तक पहुंच गई। इस बाजार ने छोटी कारों की मांग बढ़ाई।
महिंद्रा: महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ (ऑटोमोटिव) नलिनीकांत गोल्लगुंटा के मुताबिक, अब ग्राहक ऊंचे वेरिएंट की ओर बढ़ रहे हैं।
डीलर: 75.57% ने अक्टूबर में बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई, डीलरशिप पर कारों का स्टॉक 43 से लेकर 45 दिन तक का हो गया है।
स्रोत: सियाम, फाडा

एफएमसीजी • अगस्त-नवंबर में 11% मांग बढ़ सकती है

बिस्किट जैसी रोजाना खपत की चीजें (एफएमसीजी) की बिक्री अगस्त से नवंबर के बीच 9-11% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इक्विरस कैपिटल के जुलाई 2026 के ट्रैकर ने बिजोम के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक, जुलाई-सितंबर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिक्री 13 तिमाहियों में सबसे तेज रही और नेस्ले इंडिया की आय करीब 25% बढ़ी। लेकिन इनके मुनाफे पर दबाव बना हुआ है। पाम ऑयल, कच्चे तेल और पैकेजिंग की ऊंची लागत से मार्जिन घट रहा है।

बिजनेस ब्रीफ

मिलें अतिरिक्त चीनी बेच सकेंगी, सप्लाई बढ़ेगी

नई दिल्ली| केंद्र ने त्योहारों में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए मिलों को अक्टूबर में तैयार चीनी अक्टूबर-नवंबर में नियमित कोटे से अतिरिक्त बेचने की मंजूरी दी है। चीनी व्यापारियों के संगठन एआईएसटीए के चेयरमैन प्रफुल विठलानी ने कहा कि गन्ने की पेराई करीब एक महीने पहले शुरू होने से उपलब्धता बढ़ेगी। कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।

पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध मुनाफा 13% बढ़ा

मुंबई| सितंबर तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध मुनाफा 13% बढ़कर ₹5,532 करोड़ हो गया। इस दौरान बैंक की कुल आय भी 5.4% बढ़कर ₹38,185 करोड़ हो गई। ग्रॉस एनपीए (फंसे कर्ज) घटकर 2.55% और नेट एनपीए 0.25% रह गया। प्रोविजन कवरेज 97.3% और सीआरएआर 17.9% रहे, जो एसेट क्वालिटी सुधरने का संकेत है।

इवेस्को ने टाटा मोटर्स का अधिग्रहण प्रस्ताव माना

मुंबई| इटली के इवेस्को ग्रुप के शेयरधारकों ने टाटा मोटर्स के 3.91 अरब यूरो (₹41,772 करोड़) के अधिग्रहण से जुड़े सभी प्रस्ताव मंजूर कर लिए। न्यूनतम स्वीकृति सीमा 95% से घटाकर 80% कर दी गई। टेंडर ऑफर 26 अक्टूबर को बंद होगा। इससे टाटा मोटर्स की यूरोप के कमर्शियल व्हीकल बाजार में स्थिति मजबूत होगी।

भारत में एमिरेट्स एनबीडी का RBL में मर्जर मंजूर

मुंबई| आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय ब्रांच का आरबीएल बैंक में मर्जर 1 दिसंबर 2026 से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला जून में हुए ₹26,083 करोड़ के निवेश के बाद आया। इसमें एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल में 60% हिस्सेदारी हासिल की थी। सभी भारतीय ब्रांच अब आरबीएल के रूप में काम करेंगी।

आईडीबीआई बैंक: दीपक पारेख सलाहकार बने

मुंबई| फेयरफैक्स ने आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण के लिए दीपक पारेख और परेश सुखवेश्वर को सलाहकार नियुक्त किया है। एएए कन्नन को चेयरमैन प्रस्तावित किया गया है, जबकि राकेश शर्मा सीईओ बने रहेंगे। ₹52,878 करोड़ की डील के तहत 60.72% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, जो 2027 की पहली तिमाही में पूरी हो सकती है।

फंड • कमजोर रुपए के बीच फैसला; पर मौजूदा निवेश, गोल्ड ईटीएफ पर कोई असर नहीं

गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में नए निवेश पर रोक, पुरानी एसआईपी जारी रहेगी

भास्कर न्यूज | मुंबई

त्योहारी सीजन में एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सहित करीब 17 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में नया निवेश अस्थायी रूप से रोक दिया है। शुक्रवार से लागू पाबंदियों में एकमुश्त निवेश, नई एसआईपी और अन्य स्कीम से पैसा लाने के नए निर्देश शामिल हैं। कुछ स्कीम्स में चांदी से जुड़े निवेश पर भी रोक है। पैसा निकालने या दूसरी योजनाओं में ले जाने पर रोक नहीं है।

कंपनियों ने पाबंदी की वजह नहीं बताई है। हालांकि, श्रीराम म्यूचुअल फंड ने कहा कि यह कदम एम्फी के जरिए मिले सेबी के निर्देशों के अनुरूप है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश खुला है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सोने के आयात से डॉलर की मांग और रुपए में कमजोरी को लेकर चिंता है। सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 71% बढ़कर ₹4,450.6 करोड़ हो गया, जो अगस्त में ₹2,597 करोड़ था। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि इससे सोने-चांदी से जुड़ी स्कीम्स में नए निवेश पर असर पड़ सकता है। शेयर बाजार से ईटीएफ खरीदने के लिए डीमैट खाते की जरूरत होती है, जबकि इसमें बिना डीमैट खाते के निवेश किया जा सकता है।

गोल्ड फंड्स का आकार बढ़ा; एसबीआई का एयूएम करीब चार गुना

गोल्ड फंड ऑफ फंड्स	पहले संपत्ति (AUM)	बाद में कुल संपत्ति	बढ़ोतरी
एसबीआई गोल्ड फंड	जून 2025: 4,420	सितंबर 2026: 17,423	करीब 4 गुना
कोटक गोल्ड फंड	सितंबर 2025: 4,153	सितंबर 2026: 6,996	68.5%
HDFC गोल्ड ईटीएफ FoF	अप्रैल-25: 3,870	अप्रैल 2026: 11,464	करीब 3 गुना

68%
से ज्यादा बढ़ गया कोटक गोल्ड फंड का एयूएम एक साल की अवधि में

नोट: राशि करोड़ रुपए में। देश में ऐसे 24 फंड हैं, लेकिन इनकी कुल एसेट्स का विवरण उपलब्ध नहीं है। इस बढ़ोतरी में नए निवेश के साथ सोने की कीमतों में बदलाव का असर भी है।

भास्कर नॉलेज | रोक क्यों... आपके पैसे पर इसका क्या असर होगा?

Q गोल्ड फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं?
ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जो निवेशकों का पैसा गोल्ड ईटीएफ में लगाते हैं। गोल्ड ईटीएफ आगे वास्तविक सोने में निवेश करते हैं। फंड ऑफ फंड्स में बिना डीमैट खाते के निवेश कर सकते हैं। रिटर्न सीधे सोने के बाजार भाव से जुड़ा होता है।

Q मौजूदा निवेशक क्या कर सकेंगे?
गोल्ड फंड ऑफ फंड्स के निवेशक पुरानी एसआईपी और एसटीपी की किस्तें चलती रहेंगी। निवेशक पैसा निकाल सकेंगे, नियमित निकासी जारी रख सकेंगे और रकम दूसरी योजना में भेज सकेंगे। हालांकि, संबंधित योजना में नई रकम जोड़ने या एसआईपी बढ़ाने पर पाबंदी हो सकती है।

Q क्या पहले लगाया पैसा फंस गया है?
नहीं। निकासी खुली है और पहले से पंजीकृत नियमित निवेश जारी रहेंगे। हालांकि, निवेश की वैल्यू सोने के भाव के साथ घट-बढ़ सकती है। नया निवेश कब शुरू होगा, ये कंपनी की अगली सूचना से पता चलेगा।

Q रोक कब हटेगी?
तय तारीख नहीं बताई गई है। ग्रो, डीएसपी और टाटा म्यूचुअल फंड सहित कई कंपनियों के मुताबिक पाबंदियां अगली सूचना तक रहेंगी।

Q क्या गोल्ड ईटीएफ फ्रीज हो गए हैं?
नहीं। गोल्ड ईटीएफ के निवेश पर किसी तरह की रोक नहीं है। इसमें नया निवेश भी कर सकते हैं। रोक सिर्फ फंड ऑफ फंड्स में नया पैसा लगाने पर है। ये स्कीम निवेशकों का पैसा गोल्ड ईटीएफ में लगाती हैं।

Q सोने में निवेश का रुपए से क्या संबंध है?
गोल्ड ईटीएफ वास्तविक सोने में निवेश करते हैं। इसलिए इन योजनाओं में नया पैसा आने से सोने की खरीद की जरूरत बढ़ सकती है। भारत में आयातित सोने के भुगतान के लिए डॉलर की मांग बढ़ती है। इससे रुपए पर दबाव पड़ सकता है। आयात का खर्च बढ़ने से चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है-यानी विदेशों से वस्तुओं, सेवाओं और आय के लेनदेन में प्राप्तियों के मुकाबले भुगतान अधिक होना। हालांकि, रोक से इस दबाव में कितनी कमी आएगी, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।

बेशकीमती खजाना • जॉब्स के कहने पर भी नहीं बदला एपल का पहला कंप्यूटर, अब 10.9 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ



50 साल पुराना कंप्यूटर आज भी काम करता है
1976 का यह एपल-1 चालू हालत में है। इसमें 8 केबी रैम और एमओएस टेक्नोलॉजी का 6502 प्रोसेसर है। साथ में पुरानी निर्देश पुस्तिका भी है।

न्यूयॉर्क| 50 साल पुराना एपल का पहला कंप्यूटर रिकॉर्ड ₹10.9 करोड़ में नीलाम हुआ है। वॉजनियक का डिजाइन किया एपल-1 वर्ष 1976 में कंपनी का पहला प्रोडक्ट था। इसमें उनके हस्ताक्षर भी हैं। साथ में जॉब्स का पत्र भी है। फ्रेड हैटफील्ड ने इसे 1976 में खरीदा था। सॉफ्टवेयर की कमी की शिकायत पर जॉब्स ने 400 डॉलर अतिरिक्त लेकर एपल-II का बोर्ड देने की पेशकश की थी। हैटफील्ड ने इनकार कर दिया था।

प्रतिक्रिया • स्टारलिंक विवाद में कंपनी ने पहली बार रखी अपनी बात

हमें कभी मुकाबले से डर नहीं लगा: रिलायंस

भास्कर न्यूज | मुंबई

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इलॉन मस्क के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि भारत में नियम देसी और विदेशी, सभी कंपनियों के लिए बराबर हैं। कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि उसने कभी प्रतिस्पर्धा का डर महसूस नहीं किया। यह भी याद दिलाया कि उसकी अपनी सैटेलाइट सर्विस को भी मंजूरी का इंतजार है।

कंपनी ने कहा कि भारत निवेश और नए विचारों का स्वागत करता है और यह खुलापन कानून के राज पर टिका है। सरकार के मुताबिक भी हर आवेदक के लिए प्रक्रिया एक जैसी है। रिलायंस ने बताया कि 2016 में जियो बिना एक भी ग्राहक के शुरू हुई थी और दस साल में उसके 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो गए हैं।

मस्क का आरोप: मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग टालने और टेलीकॉम बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बचाने का आरोप लगाया था।

सरकार का पक्ष

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 अक्टूबर को कहा था कि देश में किसी भी सेक्टर में एकाधिकार की इजाजत नहीं है। स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब को सैटेलाइट लाइसेंस मिल चुके हैं, पर सर्विस सुरक्षा शर्तें पूरी होने के बाद ही शुरू हो सकेंगी।

महंगी चीनी का असर

एथेनॉल के टेंडर से गन्ने का रस, चीनी बाहर हुई

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

चीनी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और कम बारिश से उत्पादन घटने का डर है। इसी वजह से सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल (डायवर्जन) 2026-27 में शून्य कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शुक्रवार को जारी टेंडर में गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप और बी-हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल के लिए बोलियां मांगी ही नहीं गईं। नवंबर से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की बोलियां मंगवाई गई हैं। इसकी आपूर्ति मक्का, टूटे चावल और एफसीआई के अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल से होगी। मक्का आधारित एथेनॉल का इंसेंटिव 5.79 से घटाकर ₹2.79 प्रति लीटर किया गया है। खरीद मूल्य घटकर ₹68.8 प्रति लीटर रह गया है।

सख्ती • अफसर जिम्मेदार, 70 लाख कर्मचारियों को राहत

रिटायरमेंट से 4 साल पहले जांचे जाएंगे वेतन-पेंशन के कागजात

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्र के 36.5 लाख कर्मचारियों और 33.9 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी विभागों को रिटायरमेंट से चार साल पहले कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, वेतन निर्धारण (पे-फिक्सेशन) और पेंशन विवरण की अनिवार्य जांच के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य मकसद रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों से अचानक होने वाली रिकवरी और कानूनी विवादों पर लगाम लगाना है। गलती होने पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। नए नियमों के तहत पदोन्नति, ह्वॉर्मिंग अप या एसीपी/एमएसपी के बाद जारी पे-फिक्सेशन आदेशों का सत्यापन अब 3 महीने या उसी वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

जवाबदेही • नुकसान की भरपाई अधिकारियों से

रिकवरी से छूट: पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकेगी।
अफसरों पर गाज: सर्टिफिकेट के बाद भी पे-फिक्सेशन में गड़बड़ी मिलने पर नुकसान की भरपाई मंजूरी देने वाले अधिकारियों से होगी।
सर्विस की जांच: पेंशन के लिए सर्विस पीरियड का समय-समय पर ऑडिट होता रहेगा।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में केंद्र का कुल पेंशन खर्च 12.3% बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें रक्षा पेंशन की हिस्सेदारी 45.57% और सिविल पेंशन की 33.57% है।

छंटनी के अगले ही दिन फेरबदल

नेटफ्लिक्स: कंटेंट हेड बेला की जगह राइस

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

नेटफ्लिक्स ने सुस्त पड़ती ग्रोथ के बीच अपना कंटेंट चीफ बदल दिया है। स्ट्रीमिंग कंपनी ने बेला बजारिया की जगह डिज्नी और पॉरमेंस के पूर्व एग्जीक्यूटिव पीटर राइस को चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया है।

को-सीईओ टेड सरंडोस ने गुरुवार को कर्मचारियों को भेजे मेमो में बताया कि 2023 से इस पद पर रहीं बजारिया तत्काल प्रभाव से कंपनी छोड़ रही हैं। राइस अगले हफ्ते कार्यभार संभालेंगे। यह बदलाव अचानक हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स के ऐगेजमेंट (दर्शकों के जुड़ाव) के आंकड़े ठहर गए हैं और ग्रोथ धीमी पड़ी है। एक दिन पहले ही कंपनी ने करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। यह 2022 के बाद की सबसे बड़ी छंटनी है। सरंडोस ने स्टाफ से कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई बड़ी खबरें पचानी पड़ीं, लेकिन बदलाव ही नेटफ्लिक्स का काम है।

कोलेस्ट्रॉल घटाने का दावा भ्रामक

जेमिनी, बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट को नोटिस

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

एफएसएसएआई ने खाने की चीजों के भ्रामक दावों पर सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य नियामक ने 'प्रीडम कुकिंग राइस बान ऑयल' के प्रचार में किए गए सेहत संबंधी दावों को लेकर जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट इंडिया को नोटिस जारी किया है। एफएसएसएआई के मुताबिक, इस तेल को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर बुरा कोलेस्ट्रॉल घटाने, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाए रखने या बढ़ाने और 10,000 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) से ज्यादा प्राकृतिक ओरिजनॉल्स वाला बताया गया। नियामक ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत से जुड़े ये दावे विज्ञापन और दावा विनियम, 2018 में राइस बान ऑयल के लिए मंजूर दावों में शामिल नहीं हैं। नोटिस जेमिनी एडिबल्स, बिगबास्केट चलाने वाली इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स और फ्लिपकार्ट इंडिया को भेजे गए हैं। तीनों से पूछा गया है कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए।

ओपनएआई ने चेताया

एआई इंजीनियरों पर अब जासूसों की नजर

भास्कर न्यूज | मुंबई

एआई की होड़ अब कंपनियों के दफ्तरों से निकलकर इंजीनियरों की निजी जिंदगी तक पहुंच गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई ने कर्मचारियों को चेताया है कि विदेशी जासूस उन्हें 'हनी ट्रैप' में फंसाकर कंपनी के राज निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मकसद तैयार मॉडल चुराना जरूरी नहीं, बल्कि उसे बनाने वालों से ट्रेनिंग के तरीके, कंप्यूटिंग ढांचे और अगली रिसर्च की दिशा जैसी जानकारियां निकालना है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को के एक प्लेग्राउंड में एक कर्मचारी से अजनबी ने बात शुरू की, जो धीरे-धीरे काम तक पहुंच गई। आरोप है कि वह जासूस था। कंपनी ने रिश्वत और सार्वजनिक जगहों पर बातें सुनने की कोशिशों से भी सावधान किया है। सलाह है कि लैपटॉप स्क्रीन ढककर रखें और मीटिंग के बाद व्हाइटबोर्ड साफ करें। एंथ्रोपिक और गूगल ने भी ऐसी चेतावनियां दी हैं।

बिजनेस एंकर

जापानी कारखाने बंद, अब स्थानीय कारखानों, रोजगार पर संकट देख नीति में बदलाव

चीनी ईवी का स्वागत भारी पड़ा, अब नुकसान झेल रहा थाईलैंड

© The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

सुई-ली वी, क्रिस्तिफुम सिंगम्प्आंग | बैंकॉक और रायोंग, थाईलैंड

थाईलैंड की नेटसना स्कूलपोलपन्या जिस कार-पुर्जा कारखाने में काम करती थीं, उसका सबसे बड़ा ग्राहक टोयोटा था। कभी उन्हें 5 महीने के अतिरिक्त वेतन के साथ बोनस मिलता था। इसी कमाई से उन्होंने अपनी दिव्यांग बहन की देखभाल और भतीजी की पढ़ाई का खर्च उठाया। फिर ऑर्डर घटे, ओवरटाइम बंद हुआ और वेतन कटने लगा। 2024 में कारखाना दिवालिया होकर बंद हो गया। करीब 900 कर्मचारियों की नौकरी गई, मुआवजा भी नहीं मिला। अब 49 वर्षीय नेटसना सुपरमार्केट में काम करती हैं। उनकी कहानी थाईलैंड के वाहन उद्योग में आए बदलाव का चेहरा है। जिस देश को जापानी कंपनियों ने छह दशकों में 'पूरब का डेट्रॉयट' बनाया, वहां चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियां तेजी से छा गई हैं। चार साल पहले लगभग शून्य हिस्सेदारी से बढ़कर अब थाईलैंड के ईवी बाजार में उनका कब्जा करीब 85% है। सस्ती कीमत और ज्यादा सुविधाओं ने चीनी कारों को लोकप्रिय बनाया। 2026 के शुरुआती सात महीनों में बिकी नई कारों में एक-तिहाई इलेक्ट्रिक थीं। लेकिन इसी अवधि में बिकी कारों की दो-तिहाई ईवी मुख्यतः चीन से आयातित थीं? दूसरी ओर, 2024 और 2025 में सुबारू और सुजुकी ने थाईलैंड के कारखाने बंद किए। निसान और होंडा ने उत्पादन घटाया। जापानी कंपनियों पर निर्भर कई स्थानीय पुर्जा आपूर्तिकर्ता दिवालिया हो गए। करीब सात लाख लोगों को रोजगार देने वाली आपूर्ति व्यवस्था पर खतरा है। थाईलैंड की सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग एजेंसी के अध्यक्ष सुपावुद सैचुआ मानते हैं, 'यह बदलाव हमारी सोच से कहीं तेज हुआ। हमने इसके सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया। थाईलैंड को जितने नुकसान का अंदेशा था, उससे कहीं ज्यादा हुआ।'

सरकार ने 2022 में लक्ष्य रखा कि 2030 तक वहान उत्पादन में शून्य उत्सर्जन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 30% होगी। टैक्स कटौती और सब्सिडी दी गई। कंपनियों को स्थानीय उत्पादन की शर्त पूरी करने से पहले दो साल तक ईवी आयात की अनुमति मिली। चीन-आसियान मुक्त व्यापार समझौते से सीमा शुल्क भी नहीं लगा। थम्मसात यूनिवर्सिटी के सप्लाई चेन विशेषज्ञ रुथ बनोमयोंग कहते हैं कि स्थानीय कंपनियों के लिए चीनी कार कंपनियों को पुर्जे बेचे पाना मुश्किल है। गाड़ियां बनाने की मुख्य तकनीक अब भी चीन के पास है। रूथ और उनके साथियों का अनुमान है कि अगर थाईलैंड के कार बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा बढ़ा, तो पांच साल में तीन लाख नौकरियां जा सकती हैं।



बदलनी पड़ी रणनीति... थाईलैंड में बने पुर्जे खरीदेंगे तो कम टैक्स लगेगा

सरकार ने सितंबर में टैक्स की तीन दरों वाली व्यवस्था घोषित की। जो कंपनियां थाईलैंड में कार बनाने की योजना के बिना सिर्फ विदेश से गाड़ियां लाकर बेचेंगी, उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं, जो कंपनियां ज्यादा पुर्जे थाईलैंड से खरीदेंगी, उन पर सबसे कम टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल जापानी कार कंपनियों को भरोसा दिलाने टोक्यो भी गए। वाहन मजदूरों के संगठन के अध्यक्ष तोस्पोफोल कुंसी सवाल उठाते हैं, 'क्या हमारे देश में गाड़ियां बनती रहेंगी या हम सिर्फ चीन की सस्ती इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वाला बाजार बनकर रह जाएंगे?'

चुनौती • वैश्विक मानक के लिए इंफ्रा दोगुना करना होगा

2035 तक हेल्थकेयर सेक्टर में 29 लाख नए बेड की जरूरत

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए साल 2035 तक 260 करोड़ वर्ग फीट अतिरिक्त हेल्थकेयर रियल एस्टेट की जरूरत होगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए करीब 29 लाख नए अस्पताल बेड जोड़ने होंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट फर्म सीबीआरई साउथ एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल भारत में प्रति 1,000 आबादी पर महज 1.6 अस्पताल बेड हैं। यह 3.3 के वैश्विक औसत से कम है। वैश्विक मानक के बराबर पहुंचने के लिए देश के कुल हेल्थकेयर रियल एस्टेट स्पेस को 2025 के 210 करोड़ वर्ग फीट से बढ़ाकर लगभग दोगुना करना होगा।

राज्यों में असमानता

कम बेड वाले राज्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में बीमारियों के बोझ की तुलना में अस्पतालों में बेड कम हैं।
मजबूत स्थिति: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों का तेजी से विस्तार हो रहा है।
निवेश और विस्तार की नई रणनीति
सिंगल-स्पेशलिटी पर फोकस: सिंगल-स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डे-केयर, ओपीडी और अधिग्रहण के जरिए विस्तार पर जोर है।
मेडिकल ऑफिस बिल्डिंग्स: एक ही परिसर में डायग्नोस्टिक्स, रिहैब, आईवीएफ, डेंटल और वेलनेस सेवाएं साथ देने का चलन बढ़ रहा है।

अर्बन कंपनी इंस्टाहेल्प के लिए 2,500 करोड़ जुटाएगी

भास्कर न्यूज | मुंबई

होम सर्विसेज कंपनी अर्बन कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपए तक की नई पूंजी जुटाने को मंजूरी दी है। मकसद इंस्टेंट होम सर्विस कारोबार 'इंस्टाहेल्प' को मजबूत करना है, जहां स्नैबिट और प्रोटो से कड़ी टक्कर है। कंपनी इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। क्यूआईपी (योग्य संस्थागत खरीदारों को शेयर बेचना) इसका एक रास्ता है। 30 सितंबर 2026 को कंपनी के पास 1,901 करोड़ रुपए का कैश और ट्रेजरी निवेश था। दूसरी तिमाही में उसकी आय 41% बढ़कर 537.3 करोड़ रुपए रही, पर शुद्ध घाटा 59.3 करोड़ से बढ़कर 182.5 करोड़ रुपए हो गया। जून में स्नैबिट और इंस्टाहेल्प, दोनों के करीब 15 लाख ऑर्डर रहे। कंपनी ने इंस्टाहेल्प को वित्त वर्ष 2028 की तीसरी तिमाही तक एडजस्टेड ईबिटा के ब्रेकइवन पर लाने का लक्ष्य बरकरार रखा है।

भारताच्या आर्थिक इतिहासाचा मागोवा

डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, बँकिंग व फायनान्स
ruparege@gmail.com

भारताचा आर्थिक प्रवास घडविणारे महत्त्वाचे विचार व वादविवाद कथाकथनाच्या स्वरूपात उलगडून दाखवतानाच; प्रत्येक गोष्ट स्वतः निर्माण करण्याची 'आत्मनिर्भरता' म्हणजे आर्थिक राष्ट्रवाद नव्हे, याची जाणीव करून देणाऱ्या पुस्तकाविषयी...

निरंजन राजाध्यक्ष यांचे नुकतेच प्रकाशित झालेले 'द आयडियाज दॅट शेप्ड मॉडर्न इंडिया अँड इट्स इकॉनॉमी', हे पुस्तक भारताच्या गेल्या दीडशे वर्षांतील आर्थिक प्रवासावर, एका वेगळ्याच पद्धतीने प्रकाशझोत टाकते. सामान्यपणे आर्थिक इतिहासावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा भर हा संस्थात्मक संरचना तसेच विविध हितसंबंधी गटांचे वर्तन, यांवर असतो. तुलनेने अशा पुस्तकांत 'कल्पनां'कडे (विचार) कमी लक्ष दिले जाते. कारण संस्था व हितसंबंधी गट यांच्यात आर्थिक बदलांची गती मंदावण्याची किंवा ते बदल पूर्णपणे रोखून धरण्याची क्षमता असते. हे दोन्ही घटक परिस्थितीला 'जैसे थे' ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. मात्र राजाध्यक्षांचे पुस्तक, विविध आर्थिक विचारांना केंद्रभागी ठेवून भारताच्या आर्थिक प्रवासाची मांडणी करते. या पुस्तकातील मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, ज्याप्रमाणे एखादी प्रचंड मोठी नदी, घर्षणाच्या संथ प्रक्रियेतून अत्यंत कठीण असे पाषाण कालांतराने फोडून काढते, त्याचप्रमाणे संस्था आणि हितसंबंधी गटांमुळे जडशीळ बनलेल्या अर्थव्यवस्थेला हळूहळू बदलविण्याचे काम 'विचार' करत असतात. आधुनिक समाजांमध्ये, विचारांची शक्ती केवळ सरकारी सत्तेच्या गुप्त वर्तुळांतच नव्हे, तर व्यापक सार्वजनिक क्षेत्रातही महत्त्वाची ठरते.

या पुस्तकात १८७० ते २०१७ या प्रदीर्घ काळात भारताचा आर्थिक प्रवास घडविणारे महत्त्वाचे विचार व वादविवाद, कथाकथनाच्या स्वरूपात लेखकाने उलगडून दाखवले आहेत. त्यामुळे पुस्तकाचे वाचन हा एक अतिशय रंजक अनुभव ठरतो. लिखाणाच्या या शैलीवर, आधुनिक नर्सिंगची संस्थापक फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल हिच्या एका पत्राचा प्रभाव पडल्याचे लेखकाने प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. भारतातील एका मित्राला लिहिलेल्या पत्रात, नाईटिंगेलबाई म्हणतात, ''इंग्रज लोकांना सामान्यपणे अहवाल वाचावयास आवडत नाहीत तसेच ज्या लिखाणात सामान्य विधाने, अमूर्त संकल्पना, आकडेवारी किंवा मते असतात, त्यातही त्यांना रस नसतो. त्यांना 'तथ्ये' हवी असतात. विशिष्ट घटना, प्रत्यक्ष जीवन आणि त्यांचे परिणाम यांच्याशी संबंधित अशी ठोस तथ्ये वाचणे त्यांना आवडते''. नाईटिंगेलबाईंचा हा सल्ला प्रस्तुत पुस्तकासाठी लेखकाने तंतोतंत पाळला आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लोकहितवादींच्या (गोपाळ हरी देशमुख) 'लक्ष्मीज्ञान' या १८४९ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकाचा उल्लेख आहे, ज्याद्वारे लोकहितवादींनी ॲडम स्मिथचे अर्थशास्त्र मराठी वाचकांसमोर आणले. त्या वेळी अर्थशास्त्र हा शब्दही मराठीत रूढ झाला नव्हता. निरंजन राजाध्यक्षांनीदेखील त्यांच्या पुस्तकाचा मध्यवर्ती विषय 'लक्ष्मीच्या शोधाची कथा' हाच ठेवला आहे.

पुस्तकात एकूण नऊ प्रकरणे आहेत. भारताची औद्योगिक ध्येय-दृष्टी, आर्थिक स्वराज्यासाठीचा लढा, पर्यावरणपूरक पर्याय, राष्ट्रीय नियोजनाचा मार्ग, नेहरूयुगाचा सुवर्णकाळ, आत्मपरीक्षणाचा काळ, आर्थिक विश्रांतीचा काळ, सुधारणांचे वारे आणि १९९१ च्या पलीकडे- अशी नऊ विस्तृत प्रकरणे यात आहेत. व त्यानंतर 'निष्कर्षा'चे एक सविस्तर प्रकरण त्यांनी लिहिले आहे. या पुस्तकात भारताच्या आर्थिक परिस्थिती संबंधित अनेक महत्त्वाचे वाद कालानुरूप मांडले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतातील सुरुवातीच्या राष्ट्रवाद्यांनी केवळ ब्रिटिशांच्या भारत-विषयक आर्थिक धोरणांवरच कडक टीका केली नव्हती तर आपल्या देशासाठी औद्योगिक गुंतवणूक, तांत्रिक शिक्षण, आधुनिक बँकिंग आणि सामाजिक सुधारणा अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक समृद्ध कार्यक्रमही आखला होता. त्यांनी एकत्रितपणे मांडलेल्या या कार्यसूचीचे, पुढील दशकांमधील आर्थिक विचार व धोरणांवर अत्यंत खोलवर परिणाम झाले. पुस्तकात या कार्यसूचीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला आहे.



द आयडियाज दॅट शेप्ड मॉडर्न इंडिया अँड इट्स इकॉनॉमी
लेखक- निरंजन राजाध्यक्ष
प्रकाशक- पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया
पृष्ठे- ४८०, **किंमत-** १२९९ रु.

देश उभारणीच्या काळात भारतात जे महत्त्वाचे आर्थिक वाद घडले, त्याचेही सखोल परीक्षण या पुस्तकात करण्यात आले आहे. मुक्त व्यापार हितकारक की संरक्षणवाद हितकारक, पारंपरिक अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे विरुद्ध नवीन अर्थव्यवस्थेची उभारणी, उद्योगांमध्ये जास्त गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर की शेतीमध्ये, भांडवली वस्तू आणि उपभोग्य वस्तू यांच्यावरील साक्षेपी भर, बाजारपेठांच्या तुलनेत नियोजनाची भूमिका, अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा बाजूवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे की मागणी बाजूवर तसेच जलद आर्थिक विकास आणि आर्थिक स्थैर्य यांच्यातील समतोल साधण्यासाठी काय केले पाहिजे, अशा अनेक मुद्द्यांवर भारतात जे तीव्र मतभेद व चर्चा झडल्या आहेत, त्याचा सखोल आढावा या पुस्तकात घेतला गेला आहे. लेखकाच्या मते प्रत्येक कालखंडाने नवीन वादविवाद, दृष्टिकोन आणि उपाययोजना समोर आणल्या आहेत. अनेक धाग्यांपासून एखादी गुंतागुंतीची गोधडी विणली जावी, त्याचप्रमाणे इतिहासाच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारतीय आर्थिक चर्चांची अनेक समान सूत्रे एकत्र आली आहेत. आणि आजही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, ती आपल्या काळातील आर्थिक विचारांना आकार देत आहेत. तसेच लेखक सांगतात की भारतातील सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांनी सार्वत्रिक आर्थिक तत्त्वांकडे (युनिव्हर्सल इकॉनॉमिक प्रिन्सिपल्स) कधीच पाठ फिरवली नाही, परंतु त्यांना हेदेखील भान होते की या तत्त्वांना विशिष्ट भारतीय परिस्थितीनुसार जुळवून घेणे आवश्यक होते. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुरुवातीच्या काळात भारताकडे स्वतःची अशी पुरेशी 'बचत' नव्हती, ज्यातून औद्योगिक गुंतवणुकीला भारत चालना देऊ शकला असता. यातूनच भारतामध्ये 'तुटीच्या वित्तव्यवस्थापना'बद्दलच्या (डेफिसिट फायनान्सिंग) चर्चा व त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम यावर वाद झडू लागले. आयातीवर जबरदस्त अवलंबित्व असलेल्या भारताकडे नेहमीच विदेशी चलनाचा तुटवडा होता, ज्यामुळे आयात पर्यायन (इम्पोर्ट सब्स्टिट्युशन) अधिक श्रेयस्कर की निर्यात संवर्धन (एक्स्पोर्ट प्रमोशन) याबद्दलच्या वादविवादांना ऊर्जा मिळाली. 'अन्नाचा अभाव' ही केवळ एक मानवी शोकांतिका नव्हती तर औद्योगिक विकासातील एक अडथळा म्हणूनही ती ओळखली जात होती. पण हळूहळू हे अडथळे दूर करण्यात भारताची आर्थिक धोरणे यशस्वी झाली. भारताची ही आर्थिक कामगिरी निश्चितपणे गौरवली गेली. कालानुरूप अनेक जुने अडथळे दूर झाले पण नवीन अडथळे निर्माण होत गेले उदाहरणार्थ- ऊर्जा, पायाभूत सुविधा व कौशल्ये यांचा तुटवडा.

भारतातील इतर महत्त्वाचे आर्थिक वादाचे विषय म्हणजे येथे प्रबळ असलेल्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे संरचनात्मक परिवर्तन व या परिवर्तनासाठी सरकारकडून अपेक्षित असलेली पुढाकाराची भूमिका- मग ती भूमिका थेट सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीद्वारे असो किंवा खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक अनुदाने, आयात शुल्क व स्वस्त कर्जे यांसारखे प्रोत्साहनपर लाभ देऊन असो. भारताचे हे आर्थिक धोरणदेखील इतर अनेक देशांच्या, विशेषतः उशिरा औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांच्या धोरणाशी सुसंगत असेच होते. याचे मूलभूत उद्योग निर्माण करण्यासाठी निश्चितपणे फायदे झाले असले तरीही अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रणाने हळूहळू प्रजेचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणले. यातून निर्माण झालेल्या 'लायसेन्स-परमिट-राज'मुळे खासगी उद्योग व मुक्त बाजारपेठा यांचा कोंडमारा झाला. यातून निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे (अकार्यक्षमता, मक्तेदारी, चढ्या किमती, भ्रष्टाचार आणि यांमुळे उद्भवणारी आर्थिक अरिष्टे) हे लक्षात आले की सरकारी कृती ही तेव्हाच उत्तम ठरते जेव्हा ती खासगी उद्योगांची जागा घेण्याऐवजी त्यांना पूरक ठरते. तसेच आर्थिक सुधारणा एका धडाक्यात कराव्यात की टप्प्याटप्प्याने कराव्यात- विशेषतः भारतासारख्या सामाजिक सुरक्षा जाळे नसलेल्या देशात- याचे आकलन प्रत्यक्ष अनुभवातून व त्यातून सुरू झालेल्या आर्थिक वादविवादांतून येत गेले.

भारतीय आर्थिक धोरणांकडे 'आर्थिक राष्ट्रवादाचा एक भाग' म्हणून पाहणे सर्वात योग्य ठरेल, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. राजकीय स्वातंत्र्य, सामाजिक सुधारणा व आर्थिक विकास हे मुख्य प्रवाहातील आर्थिक राष्ट्रवादाचे पूर्वीच्या काळी जसे आधारस्तंभ होते तसेच आजही आहेत. म्हणूनच भारतीय अर्थशास्त्राचा इतिहास भारतीय राष्ट्रवादाच्या व्यापक संदर्भात समजून घेणे उपयुक्त ठरते. मात्र आर्थिक राष्ट्रवादाचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे पाठ फिरविणे असा खचितच होत नाही. प्रत्येक गोष्ट स्वतःच निर्माण करण्याची 'आत्मनिर्भरता' म्हणजे आर्थिक राष्ट्रवाद नव्हे, हे लेखक स्पष्ट करतात. उलट 'कुठल्या गोष्टींची निर्मिती आपण स्वतः करायची, कुठल्या गोष्टी निर्यात करून, आयातीकरता आवश्यक असे परकीय चलन मिळवायचे आणि प्रगत देशांच्या दबावाखाली न येता, आपली वित्तीय धोरणे स्वयंभूपणे राबविण्याची क्षमता प्राप्त कशी प्राप्त करायची', यासंबंधीचे विचार आर्थिक राष्ट्रवादासाठी महत्त्वाचे ठरतात. एकोणिसाव्या शतकातील युरोपीय राष्ट्रवादाचे आणि भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप भिन्न होते, हे राजाध्यक्ष स्पष्ट सांगतात. युरोपातील लोकांना मोठ्या राजकीय सत्तांपासून स्वतंत्र असे स्वतःचे राजकीय अस्तित्व हवे होते. याउलट भारतीय राष्ट्रवाद हा मुळातच एक प्रकारची एकीकरणाची शक्ती होता. एका अशा भूभागाला एकत्र आणले जाणार होते ज्याचे वर्णन नेहरूंनी घटनासभेत मांडलेल्या 'उद्दिष्ट ठरावा'त (ऑब्जेक्टिव्ह्ज रेझोल्युशन) 'प्राचीन भूमी' असे केले होते- अशी भूमी जी जगामध्ये आपले यथोचित व सन्माननीय स्थान प्राप्त करत होती. भारतीय संविधान हा प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिक प्रजासत्ताक यांच्यामधील एक दुवा ठरणार होता. भारतीय अर्थकारण हे या एकीकरणाच्या दृष्टिकोनाचाच एक भाग होता.

त्यानंतर जे जे घडत गेले, ते ते सर्व या 'विचारा'वर आधारित होते. जटील संघराज्याला एकत्र ठेवण्यासाठीचे प्रबळ केंद्रीय सरकार असो वा निरनिराळ्या प्रांतांमधील मुक्त व्यापार टिकवून ठेवणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी असोत वा देशाचे विविध भाग एकमेकांस जोडणाऱ्या लोहमार्ग (आगगाड्यांचे) व रस्त्यांमधील भल्यामोठ्या गुंतवणुकी असोत वा अगदी अलीकडच्या काळातील जीएसटी लागू करण्यासाठी केलेला संघीय समझोता असो- या सर्वांतून भारताने स्वीकारलेले आर्थिक एकीकरणाचे तत्त्वच दिसून येते. विखुरलेल्या प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांच्या जागी एक सामायिक बाजारपेठ निर्माण करणे हा भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादाचा मुख्य उद्देश होता व अजूनही आहे.

तसेच आर्थिक राष्ट्रवादाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विवादांचा मध्यवर्ती विषय हा सामान्य भारतीयांचे जीवनमान सुधारणे हाच कायम होता. मग ते दादाभाई नवरोजी यांचे दारिद्र्यावरील संशोधन असो वा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जातीव्यवस्थेसाठीचे काम असो वा राधाकमल मुखर्जी यांचे पर्यावरण क्षेत्रातील काम असो वा जे. के. मेहता यांचे अभावमुक्ततेच्या स्वातंत्र्यासाठीचे काम असो वा राष्ट्रीय नियोजन समितीमध्ये लैंगिक समानता व आर्थिक विकास यावर झडलेल्या चर्चा असोत- या सगळ्यांचा रोख हा सामान्य भारतीयांचे जीवनमान सुधारणे हाच होता.

या पुस्तकासाठी राजाध्यक्षांनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. पौर्वात्य व पाश्चिमात्य अभ्यासकांची शेकडो पुस्तके, अहवाल तसेच जर्नलमधील लेखांचा सखोल अभ्यास करून, भारताच्या आर्थिक इतिहासावरील हा उत्कृष्ट ग्रंथ त्यांनी निर्माण केला आहे. त्यांच्या लेखनशैलीबद्दल तर बोलायलाच नको. 'राजाध्यक्ष' आडनावाचा समृद्ध वारसा त्यातून सततच जाणवतो. या ग्रंथात भारतीय आर्थिक विचारांच्या संदर्भात जसे महात्मा गांधी, म. गो. रानडे, डॉ. आंबेडकर, सी. डी. देशमुख, पी. सी. महालानोबिस, धनंजयराव गाडगीळ यांचे विचार व संकल्पना सविस्तर वाचावयास मिळतात तसेच कौटिल्य, संत तुकाराम, लोकहितवादी, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांच्याही अर्थविषयक वैचारिक योगदानाविषयी समजते. वानगीदाखल उदाहरण द्यायचे झाले तर राजाध्यक्ष संत तुकारामांचा एक अभंग उद्धृत करतात ज्यात तुकारामांनी म्हटले आहे की कशी मुक्त बाजारपेठ, सामान्य लोकांना समतेच्या भावनेने एकत्र आणते आणि सरंजामी अधिकार व पदश्रेणींचे स्तर दूर ठेवते. भारताचा आर्थिक इतिहास समजून घेण्यास उत्सुक असलेल्या सर्वांसाठीच हा ग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण तो 'विचारां'च्या सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करतो. शेवटी बाजारपेठा, अर्थविषयक कायदे, वित्तीय संस्था यांची निर्मिती पोकळीतून होत नाही; ती अनेक बौद्धिक चर्चांची प्रत्यक्ष रूपे असतात.



बुकबातमी

पुस्तकांवर बंदी आणलीत तरी बेहत्तर, तत्त्वं महत्त्वाचीच!

सॅली रूनी या आयर्लंडमधल्या लेखिका. त्यांच्या पुस्तकांवर बंदी आली आहे इंग्लंडमध्ये आणि कारण ठरलं आहे पॅलेस्टाइन. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात, कोणत्याही क्षेत्रात काहीही बिघडलं की त्याची झळ संपूर्ण जगभर प्रत्येक क्षेत्राला आणि प्रत्येकाला या ना त्या प्रकारे बसतेच, त्याचं हे उदाहरण!

तर झालं असं- या रूनी यांनी गतवर्षी म्हटलं होतं, की मी माझ्या पुस्तकांच्या रॉयल्टीतून 'पॅलेस्टाइन ॲक्शन' या चळवळीला आर्थिक साहाय्य देणे सुरूच ठेवणार आहे. आता हे 'पॅलेस्टाइन ॲक्शन' काय प्रकरण आहे, तर ही चळवळ सुरू झाली ब्रिटनमध्ये- जुलै २०२०च्या सुमारास. इस्त्रायली सैन्याला साधनसामुग्री पुरवणाऱ्या संरक्षण कंत्राटदारांना लक्ष्य करणं हे या चळवळीचं उद्दीष्ट आहे. चळवळीवर ब्रिटिश सरकारने



दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत बंदी घातली आहे. चळवळीचं सदस्यत्व घेणं, समर्थन करणं किंवा तिच्याशी संबंधित प्रतिकं बाळगणं हा फौजदारी गुन्हा आहे. या बंदीला आव्हान देणारी याचिका ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर, अशा या चळवळीला रूनी यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवल्यामुळे त्यांच्या साहित्यावर ही बंदी लादली गेली.

या बंदीवर रूनी यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिलेली प्रतिक्रिया अशी की, ''ब्रिटिश सरकारने जुलै २०२५ मध्ये 'पॅलेस्टाईन ॲक्शन'ही दहशतवादी संघटना असल्याचं जाहीर केलं. त्या पुढच्या महिन्यात, मी एका लेखात या चळवळीचा पाठिंबा देणं सुरूच ठेवण्याचा माझा मानस व्यक्त केला होता. कारण आयर्लंडमध्ये या गटावर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. मात्र आता ब्रिटनमध्ये माझं साहित्य प्रकाशित करण्याबाबतचे करार पूर्ण करणं हा गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे माझी पुस्तकं प्रकाशित करणाऱ्या 'फेबर प्रकाशना'ने माझ्याशी रितसर चर्चा करून, माझ्या पूर्ण संमतीने आता ब्रिटनमध्ये माझं साहित्य उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी माझ्या तत्त्वांशी आणि वाचकांशी प्रामाणिक राहण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आणि त्याचे जे काही परिणाम होतील ते भोगण्यास मी तयार आहे.''

त्यांच्या पुस्तकांच्या ई-बुक आवृत्त्या विविध संकेतस्थळं आणि ॲप्सवरून आधीच काढून टाकण्यात आल्या आहेत. पुस्तकांच्या दुकानांमध्ये मात्र छापील प्रती आजही शिल्लक आहेत. अशा शिल्लक प्रती विकण्यावर बंदी नसल्याचं, 'फेबर'ने स्पष्ट केलं आहे. रूनी या त्यांच्या 'नॉर्मल पीपल' या आजच्या काळातील नातेसंबंधांवर भाष्य करणाऱ्या कादंबरीमुळे ओळखल्या जातात. जगभरात आजवर त्यांच्या पुस्तकांच्या ६० लाखांहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या आहेत. ब्रिटनमध्येही त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मात्र आजच्या डिजिटल युगात साहित्य, चित्रपटांवरील बंदी वारंवार फोल ठरताना दिसते. बंदी घातल्यावर संबंधित पुस्तकांचा अन्य अनधिकृत माध्यमांतून अधिक जोमाने प्रसार झाल्याची उदाहरणं आहेत. अशा स्थितीत रूनी यांच्या साहित्यावरील बंदी कितपत प्रभावी ठरेल, हा प्रश्नच आहे.

स्थलांतरितांच्या समृद्धीचा करुण चेहरा

प्रतिनिधी



स्वप्नांची किंमत ती साकार करणाराच जाणतो, बाकीच्यांसाठी ती केवळ दूरच्या डोंगरांसारखी असतात... हिरवीगार! मिशेल डिकास्टा यांची 'यू एन्व्ही द कुटिन्होज' ही कादंबरी म्हणजे या हिरव्या डोंगरावरच्या दुरून न दिसणाऱ्या भेगांचं चित्रण आहे. वरवर पाहता ही केवळ एक कौटुंबिक कथा, पण परदेशात स्थायिक भारतीयांचं भीषण वास्तव ती मांडते.

डिकास्टा यांची ही पहिलीच कादंबरी. नायक- जोचिम कुटिन्हो- मंगळुरूमध्ये वाढलेला... जोकिम, त्याचा दारुडा, वरचेवर घरातून गायब होणारा बाप, बापाचा मार खाणारी तरी त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसणारी आई आणि लहान बहीण असं हे कुटिन्हो कुटुंब. मुंबईत जाऊन बॉलीवूड स्टार होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या पण दिसण्यास बेतास बात असलेल्या जोकिमला कुटुंबाला गरिबीतून आणि कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी बाहरेनमधली नोकरी स्वीकारणं भाग पडतं. एकीकडे राहण्या-खाण्याचे हाल, अपमान, अभावित जगणं, एकाकीपणा, मागे सुटलेलं, पण अद्याप मनात कुठे तरी जिवंत असलेलं स्टार होण्याचं स्वप्न आणि त्याच वेळी दुसरीकडे मायभूमीतल्या नातेवाईकांसमोर समृद्ध चेहरा जपण्याची गरज यातली तारेवरची कसरत ही कादंबरी मांडते.

साधारण १९८० ते २०१७ असा साधारण चार दशकांचा काळ यात मांडला आहे. मुंबईबाहेरच्यांच्या मनात असलेलं तथाकथित मायानगरीचं चित्र आणि भारतीयांच्या मनातलं परदेशातल्या जीवनाचं चित्र ही तफावत परस्परांशी थेट नातं सांगणारी भासते. अनोळखी देशात कुटुंब वाढवतानाची आव्हानं मायदेशातल्या अडथळ्यांच्या तुलनेत किती कठीण असतात याची झलक ही कादंबरी दाखवते. जगण्यासाठी आणि कुटुंबाला जगवण्यासाठी कौतुकाने परदेशी पाठवलेल्या मुलाला तो तिथे रुळल्यानंतर 'पैसे दिले म्हणजे झालं का,' असं ऐकवलं जातं तेव्हा त्यातून आयुष्यात काळानुरूप आणि त्या त्या काळातील गरजांनुरूप प्राधान्यक्रम कसे बदलत जातात याची प्रचीती लेखिका देते.



यू एन्व्ही द कुटिन्होज
लेखक- मिशेल डिकोस्टा
प्रकाशक- ट्रॅंकिबार
पृष्ठे- ३२०, **किंमत-** ४९९ रु.

'तिथल्यां'ची आव्हानं समजून घेण्यात अपयशी ठरलेले 'इथले' पालक आणि आपल्या प्रियजनांच्या सुखदुःखात सहभागी होऊ न शकल्याचं शल्य घेऊन जगणारे स्थलांतरित यांच्यापैकी कोण अधिक बिचारं आहे, हे ठरवण्याची जबाबदारी लेखिका वाचकांवर सोपवून मोकळी होते. 'इथल्या' आणि 'तिथल्या' भावंडांतील सुरुवातीचं प्रेम-काळजी पुढे कशी स्पर्धा, असूया, गैरसमज, हतबलता यात परिवर्तित होत जाते, याचे दाखले कथानकाच्या ओघात मिळतात. परदेशांत शेजारी-पाजारी, मित्र, सहकारीच कसे हळूहळू नातेवाईकांच्या भूमिकेत शिरत जातात आणि कधी मदतीला येतात तर कधी किती तापदायक ठरतात याची उदाहरणंही यात आहेत.

जोकिमची पत्नी एमिल्डाच्या निमित्ताने भारतात ख्रिश्चन मिशनरीच्या छत्रछायेत वाढलेल्या अनाथ मुलींचं आयुष्य, तिथल्या वातावरणाचा त्यांच्या आयुष्यावर असलेला ठसा, पक्के झालेले समज यांचीही झलक मिळते. नातेवाईक एका घरात राहणारे असोत वा जगाच्या दोन वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत राहणारे; परस्परांना अनेक वर्षांतून कधी तरी एकदाच अल्पावधीसाठी भेटत असतील, तरीही तेवढेच हेवेदावे कसे काय बाळगू शकतात, असा प्रश्न यातील वर्णनं वाचताना पडतो.

पुस्तकात परदेशांत वाढलेल्या मुलांची द्विधा मांडली असली, तरी बाहरेनमध्ये प्रचंड संख्येने असलेल्या भारतीयांमुळे ही द्विधा काहीशी सौम्य झाल्याचं दिसतं. हिंदी, कोंकणी, कन्नड, मल्याळम बोलणाऱ्यांच्या आणि भारतीय मूल्यव्यवस्थेवर विश्वास असणाऱ्यांच्या सहवासामुळे या मुलांचा मायदेशातल्या संस्कृतीशी परिचय आहेच, पण लैंगिक- धार्मिक पूर्वग्रह अद्याप मागे टाकू न शकलेल्या जुन्या पिढीशी नव्या पिढीचा संघर्ष काही तिथेही टळलेला नाही.

जोकिमच्या पुतण्याच्या निमित्ताने आपल्या काकाच्या पावलावर पाऊल टाकून स्वतःही तीच तथाकथित समृद्धी प्राप्त करण्याची मनीषा बाळगणारा, पण तिथवर पोहोचताना प्रचंड धडपडणारा, परत उठण्याचा प्रयत्न करणारा तरुणही दिसतो. एकूण तीन पिढ्यांची ही कहाणी आहे- 'ग्रेट अरब ड्रीम'भोवती फिरणारी.

कादंबरीत व्यथांचीच जंत्री एवढी आहे की शेवटी काहीशी नकारात्मक भावनाच मागे उरते. त्याच वेळी एवढ्या बिकट स्थितीत घरापासून दूरवर राहणं ज्यांना भाग पडतं, त्यांची इथली अवस्था किती भीषण असेल याचाही अंदाज येतो. दुरून साजिऱ्या दिसणाऱ्या या डोंगराचं हे भेगाळलेलं वास्तव अस्वस्थ करणारं आहे, हे मात्र निश्चित.

बुक-नेट

रसायनशास्त्रानंतर काव्यआघाडी...



'लेसन्स इन केमिस्ट्री' या पुस्तकावर आलेली टीव्ही मालिकाही गाजली आणि त्या मालिकेमुळे नंतर पुस्तकही जगात दूरवर पोहोचले. पुस्तकाच्या लेखिका बॉनी गार्मस या तर गेल्या चार वर्षांतल्या मुलाखतींमधून आपल्याला नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या घटनेचे आभार मानतायत आणि ९८ प्रकाशकांनी नाकारल्यानंतर जन्माला आलेल्या या पहिल्या पुस्तकाने केलेल्या खपाच्या विक्रमाकडे आश्चर्याने पाहातायत. जयपूर साहित्य महोत्सवासह जगभरातील पुस्तक महोत्सव गाजविण्याच्या व्यापातच गेलेल्या या चार वर्षांत त्यांनी दुसरी कादंबरीदेखील लिहिली, हे विशेष. 'पेक ॲण्ड पेक' नावाची ही कादंबरी ऐंशीच्या दशकातील अमेरिकेत घडते. कादंबरीचे कथानक काव्याला वाहिलेल्या ज्या मासिकाभोवती फिरते, त्याचेही नाव 'पेक ॲण्ड पेक' हेच. कवी-मासिकाचे संपादक-मालक आणि शब्दांच्या पसाऱ्यात चालणारे कथायुद्ध यात आलेय. आता नव्या पुस्तकाच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या नव्या मुलाखत-माळांतील काही आवर्जून वाचाव्या अशा खालील दुव्यांवर.

- https://tinyurl.com/23yhefpv
- https://tinyurl.com/3dkp7cxb

केन पारितोषिक आणि एआय वाद...

आफ्रिकेचे बुकर ही ओळख असलेले आणि फक्त कथेसाठी दिले जाणारे 'केन' पारितोषिक यंदा वेगळ्याच कारणासाठी अधिक चर्चेत आले. पारितोषिक झिम्बाब्वेमधील 'ब्लू फायटर' नामक कथेला जाहीर झाले. पण त्यानंतर काहीच दिवसांनी 'द अटलांटिक'च्या संकेतस्थळावर आलेल्या लेखात ही कथा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून लिहिली गेल्याचा आरोप करण्यात आला. हरारे येथील कुटुंबात रंगीत मासे पाळणाऱ्या कफल्लक कुटुंबप्रमुखाची गोष्ट 'ब्लू फायटर'मध्ये आलीय. त्या कथेची पडताळणी या पारितोषिकासाठी आलेल्या पूर्वीच्या कथांशी केली गेली. आधीच्या साऱ्या गोष्टी या मानवी असून यंदाची विजेती कथाच एआयचा आधार घेऊन लिहिण्यात आल्याचा दावा अटलांटिकच्या लेखात आलाय. त्यामुळे कथा, अटलांटिकचा लेख आणि नंतरचे वाद असा सगळाच कुतूहल उत्प्रेरक भाग खालील दुव्यांमध्ये सापडेल.

- https://tinyurl.com/yc7prnfy , https://tinyurl.com/myyjafjh,
- https://tinyurl.com/6f5y8by, https://tinyurl.com/3md4vm2p

रॉबर्ट फ्रॅन्कचे घर...



एक युरोपातील छायाचित्रकार १९५५ साली शीष्यवृत्तीच्या बळावर युद्धोत्तर अमेरिकेच्या १० हजार मैलांची वाट तुडवतो आणि त्यात तब्बल २८ हजार छायाचित्र काढतो. फ्रान्समध्ये १९५८ साली प्रकाशित झालेल्या 'अमेरिकन्स' हे ८३ छायाचित्रांचे पुस्तक आजही दृश्यकलादर्दींच्या निवडकांमध्ये गणले जाते. या पुस्तकाचा कर्ता छायाचित्रकार रॉबर्ट फ्रॅन्क याच्या घरावर लिहिला गेलेला दीर्घ लेख या आठवड्यापुरता प्लाऊशेअरच्या ताज्या अंकात वाचायला मिळतोय. लेख वाचनाआधी अभ्यास म्हणून गेल्याच वर्षी 'गार्डियन'ने या पुस्तकाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा छायाचित्रनिबंध प्रकाशित केला आहे. तो वाचून झाल्यानंतर पुस्तकाची यूट्युब रपेट फक्त पूरक दृश्यवाचन म्हणून.

- https://tinyurl.com/22ywn4wa
- https://tinyurl.com/8xu8sa2d
- https://tinyurl.com/bddc8cb6

जनपत्रकारितेचे जंतर-मंतर

बातम्यांचे केवळ ग्राहक (कन्झ्यूमर) असणारे लोक आज बातम्यांचे उत्पादकही (प्रोड्यूसर) होऊ लागले आणि आता 'यांचे काय करायचे' हा प्रश्न व्यवस्थेला पडला...

'जंतर' हा यंत्र या शब्दाचा अपभ्रंश आणि 'मंतर' म्हणजे मंत्र. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या तंत्रप्रगतीमुळे, त्यातून निर्माण झालेल्या समाजमाध्यमांमुळे पत्रकारितेचे हे जंतर-मंतर सर्वसामान्य लोकांहाती आलेले आहे. आणि आज अशी परिस्थिती आलेली आहे, की या जनपत्रकारितेचे काय करायचे, हेच विद्यमान व्यवस्थेला कळेनासे झालेले आहे. आपण पत्रकार आहोत असा दावा जर सगळेच करू लागले, तर सारे अवघड होऊन जाईल, ही सर्वोच्च न्यायालयाची याबाबतची टिप्पणी. त्यातून या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात येते. हा मुद्दा आजच चर्चेस येण्यास कारणीभूत ठरले ते जंतर-मंतर आणि दिल्लीतील अन्य काही भागांत झालेले विद्यार्थी आंदोलन. त्या आंदोलनांत अनेक पत्रकारांना - त्यातही मुक्त पत्रकारांना आणि 'सिटिझन जर्नालिस्ट' या अर्थी जनपत्रकारांना - पोलिसांनी एखाद्या समाजकंटकाप्रमाणे 'हाताळले'. त्या बाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त वक्तव्य केले. असे असले, तरी हा प्रश्न केवळ ते आंदोलन, त्यातील ते मुक्त आणि जनपत्रकार, ते यूट्यूबर्स आणि प्रभावक यांच्यावरली पोलिसी हडेलहप्पी एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. यातून काही मूलभूत मुद्दे समोर आलेले आहेत. आगामी काळात ते अधिकाधिक तीव्र आणि व्यापक होत जाण्याची शक्यता असल्याने, त्याची चर्चा आवश्यक ठरते.

यातील पहिला मुद्दा आहे तो 'पत्रकार' म्हणजे कोण? सामान्यतः एखाद्या माध्यमसंस्थेत कार्यरत असणारे वा स्वतःची माध्यमसंस्था असणारे वार्ताहर, प्रतिनिधी, संपादक ते पत्रकार. त्यातील काही जण नाना 'उद्योग' करतात, हा भाग वेगळा. मात्र सार्वजनिक महत्त्वाच्या घटना, घडामोडी, समस्या यांची माहिती गोळा करून, तिची सत्यता पडताळून, त्यातील विविध बाजू मांडून, विश्लेषण करून ती माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांचे प्राथमिक काम. नियतकालिके, अनियतकालिके, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी आदी त्यासाठीची माध्यमे. त्यांद्वारे ते बातम्या देतात. बाकीचे लोक हे त्या बातम्यांचे ग्राहक. कालपर्यंत पत्रकारितेचा व्यवसाय हा असाच एकरेषीय होता. आता तसे राहिलेले नाही. संगणकीय प्रगती, त्यातही 'डेस्क टॉप पब्लिशिंग'ची सुलभ व स्वस्त उपलब्धता, त्यानंतर आलेली विविध प्रकारची समाजमाध्यमे, त्यातही विशेषतः व्हॉट्सॲप हा संदेशवहन मंच यांनी पत्रकारितेचे व्यावसायिक व्याकरण मोठ्या प्रमाणावर बदलले. सर्वसामान्यांच्या हातात आलेल्या मोबाइल दूरध्वनीने तर त्यात क्रांतीच केली. याला - भारतापुरते बोलावयाचे झाल्यास - जोड मिळाली ती माहिती अधिकार कायद्याची. सामान्य नागरिक आणि पत्रकार यांच्यातील एक फरक या कायद्याने अक्षरशः धुळीस मिळवला. जी शासकीय माहिती केवळ व्यावसायिक पत्रकारांनाच मिळू शकत होती ती आता सामान्यांनाही एका अर्जावर उपलब्ध होऊ लागली. या माहितीच्या आधारे सामान्य लोकही 'बातम्या' करू लागले. आपल्या मोबाइलद्वारे सभोवती घडणाऱ्या घटना-घडामोडी टिपू लागले. समाजमाध्यमांवरून त्या प्रसारित करू लागले. ऑल्विन टॉफ्लर म्हणतात ते 'प्रोझ्यूमर' म्हणजे हेच लोक. कालपर्यंत बातम्यांचे केवळ ग्राहक (कन्झ्यूमर) असणारे लोक आज बातम्यांचे उत्पादकही (प्रोड्यूसर) होऊ लागले. यातून केवळ 'यूट्यूबर्स', 'ब्लॉगर्स', 'पॉडकास्टर्स', 'रील मेकर्स'च उभे राहिले असे नाही, तर 'अनंत काळचे सामान्य जन आणि क्षणाचे पत्रकार'ही दिसू लागले.

एखाद्या आडगावातील शाळकरी कन्या हातातील छत्रीचा 'बूम' करून, मोबाईलचा कॅमेरा वापरून रस्त्याच्या दुर्दशेची बातमी करते, तेव्हा ती क्षणाची पत्रकारच असते. एखादा मोबाईलधारक एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे गैरकृत्य चव्हाट्यावर आणतो, एखादा 'प्रभावक' कोण्या नेत्याच्या गाडीची 'नंबरप्लेट' कशी कायदेभंग करणारी आहे हे दाखवून देतो, एखादा मुक्त पत्रकार पोलिसी अत्याचाराची दृश्ये दाखवतो, तेव्हा ते राज्यघटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क वापरून सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे, कायद्याचे राज्य

पाळतशाहीने निर्माण झालेल्या 'गारठ्याने' - 'चिलिंग इफेक्ट'ने - माणसे स्वतःस सेन्सॉर करू लागतात हे खरे. हे पत्रकारांबाबतही घडते. परंतु हा गारठा कायमस्वरूपी नसतो...

वाचवण्याचेच काम करीत असतात. वास्तविक ही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची जबाबदारी. त्यात ती कच खात आहेत, प्रसंगी त्यातील बहुतांश माध्यमे सत्ताधाऱ्यांची भाटगिरी करून आपल्या महसुलाच्या तुंबड्या भरण्याचे धंदे करीत आहेत, हे जसजसे लक्षात येत गेले, तसतशी ही जनपत्रकारिता जोर धरू लागली. यावर कोणी असे विचारू शकतो की, त्या माहितीची सत्यता, बातमीची योग्यायोग्यता यांच्या उत्तरदायित्वाचे काय? प्रश्न रास्तच आहे. अर्धवट माहिती, प्रचारी बातम्या, आपणच न्यायनिवाडा करण्याची हौस असे अनेक दुर्गुण जनपत्रकारितेत दिसतात, हे खरे. पण त्यापासून मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, त्यातही आजच्या राष्ट्रीय समजल्या जाणाऱ्या वृत्तवाहिन्या दूर आहेत असे कोण म्हणू शकेल? याचा अर्थ जनपत्रकारांना मोकळे रान असावे असे नाही. याचा अर्थ एवढाच, की बहुतांश पत्रकारितेची विश्वासार्हतेची यत्ता उणे बालवाडी असताना केवळ जनपत्रकारांनाच त्याबाबत फासावर चढवणे योग्य नाही. अर्थात एकूणच हा चर्चेचा वेगळा मुद्दा.

त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा हा की, जनपत्रकारांची संख्यावाढ हे एका अर्थी पत्रकारितेचे लोकशाहीकरण. या पत्रकारितेच्या तंत्ररूपामुळे त्यात ध्वनी आणि चित्रांस अधिक महत्त्व. त्यामुळेच आज दृक्श्राव्य जनपत्रकारिता वृत्तवाहिन्यांची प्रमुख स्पर्धक म्हणून पुढे आलेली आहे. काही वृत्तसादरकर्ते त्यांच्या राष्ट्रीय कोलाहल-कार्यक्रमांतून यूट्यूबर पत्रकारांबद्दल ज्या स्वाभाविक तुच्छतेने बोलतात त्यातून दिसतो तो त्यांनी या जनपत्रकारांचा घेतलेला धसकाच. ''आमच्या क्षेत्रात तुमच्यासारख्या 'झुरळां'चे काय काम? तुम्ही आहात कोण?'' हा त्यांचा छुपा सवाल असतो. तसाही 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' हा एक राष्ट्रीय न्यूनगंडात्मक सवाल झालेला आहे. तो या वृत्तसादरकर्त्यांनी आडूनआडून विचारावा यात नवल ते काय? आता तर त्याहीपुढे जाऊन 'या समस्येवर कसा मार्ग काढावा' असा विचार सुरू झाल्याचे दिसत आहे. त्याचा प्रारंभ या जनपत्रकारांना पत्रकार म्हणून संरक्षण कसे द्यावे या विचारणेतून झाला आहे. त्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे हवीतच, असे मत मांडण्यात येत आहे. या आवश्यकतेबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याच तत्त्वांचे जाचक निर्बंधात रूपांतर झाले तर मात्र काळजीचे कारण असेल. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे अवकाश आकसत चालल्याचा हा काळ. अशा काळाचा 'स्वभाव' हा असतो की, जोवर 'ते' आपल्या बाजूने बोलतात, तोवर लाडके. मग त्या समाजमाध्यमवीरांच्या बैठका घ्या. त्यातील 'प्रभावकां'चा उदोउदो करा. सरकारी योजनांच्या, कामांच्या प्रचारासाठी त्यांना मोबदला द्या. पण त्यातलेच काही विरोधात बोलू लागले. सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार उघड करू लागले. अन्यायाविरोधात लोकांच्या बाजूने बोलू लागले, की ते दोडके होतात. अशांवर दांडके चालवण्यास मग मार्गदर्शक तत्त्वेच उपयोगी ठरू शकतात. या दिशेने आपण जाणार की काय हा खरा आजचा प्रश्न आहे.

त्यातही, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे जवळपास अशक्यप्राय. चीनसारख्या सेन्सॉरसंपृक्त आणि पाळतशाही असलेल्या देशासही ते पुरेसे जमलेले नाही. पाळतशाहीने निर्माण झालेल्या 'गारठ्याने' - 'चिलिंग इफेक्ट'ने - माणसे स्वतःस सेन्सॉर करू लागतात हे खरे. हे पत्रकारांबाबतही घडते. परंतु हा गारठा कायमस्वरूपी नसतो. अतिभय माणसास अनेकदा निर्भय बनवते. याचा प्रत्यय काही प्रमाणात आज येतो आहे. जनपत्रकारितेचे फोफावणे, त्या पत्रकारांनी व्यवस्थेला सवाल करणे हे घडताना दिसत आहे. पुन्हा यातील सारेच पत्रकार विशिष्ट सत्ताधाऱ्यांच्या वा पक्षांच्या विरोधात आहेत, असे समजणे हा बिनडोकपणा ठरेल. या पत्रकारांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलणारेही काही कमी नाहीत. ते कसेही असले, तरी त्या सर्वांच्याच अभिव्यक्तीला घटनेच्या मर्यादित संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. जनपत्रकार झाले, तरी अखेर ते या लोकशाही देशाचे राज्यघटनेने संरक्षित केलेले नागरिक आहेत. पत्रकारितेचे हे जंतर-मंतरही लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

प्रारंभाच्या प्रथा

ऑलिम्पिक आख्यान

सिद्धार्थ केळकर
siddharth.kelkar
@expressindia.com



सर्गेइ बुब्का हा ८० आणि ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध पोल व्हॉल्टपटू. त्याने तब्बल ३५ वेळा स्वतःचाच विश्वविक्रम मोडला! पण त्याच्या दृष्टीने ऑलिम्पिक सुवर्णपदक हाच त्याच्या आयुष्यातील सर्वांत महान क्षण...

'तुझ्या दृष्टीने तुझ्या आयुष्यातील सर्वांत आवडता क्षण कोणता?'... 'मला १९८८ च्या सोल (सेऊल) ऑलिम्पिक स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाले, तो.' इति सर्गेइ बुब्का. कोण हा बुब्का? 'जेन झी'चा जन्म व्हायच्या आधीच ज्याने, 'कदाचित २१व्या शतकात शक्य होईल,' असे म्हटले जाई, असा इतिहास हे शतक उजाडण्यापूर्वीच रचला, तो. त्याने कारकीर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा तो सोव्हिएत महासंघाच्या झेंड्याखाली खेळला, सोव्हिएत महासंघ कोसळल्यानंतर तो युक्रेनियन झाला. आताही आहे. सर्गेइ बुब्का नावाचा हा अवलिया ८० आणि ९०च्या दशकातील प्रसिद्ध पोल व्हॉल्टपटू, ज्याने तब्बल ३५ वेळा स्वतःचाच विश्वविक्रम मोडला. गंमत अशी, की त्याला जेव्हा जेव्हा त्याच्या क्रीडा आयुष्यातील सर्वांत आवडता क्षण कोणता, असे विचारले गेले, तेव्हा त्याला या लागोपाठ विक्रम रचण्या-मोडण्याचे फार अप्रूप वाटले नाही. त्याच्या दृष्टीने ऑलिम्पिक सुवर्णपदक हाच आयुष्यातील सर्वांत महान क्षण. असे का?

सर्गेइ बुब्काचा जन्म ४ डिसेंबर १९६३ चा, लुहान्स्कमधला. आता युक्रेनमध्ये असलेले शहर, तो जन्मला तेव्हा सोव्हिएत महासंघाचा भाग होते. बुब्का अवघ्या १९ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकला. १९८३ च्या जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक पटकावून त्याचा पोल व्हॉल्टमधील दर्जा सिद्ध केला. तोवर या खेळात आघाडी होती फ्रेंच पोल व्हॉल्टपटू थिओरी व्हिनेरॉनची, ज्याचा उल्लेख बुब्काने आपल्या पाच सर्वांत कणखर स्पर्धकांत केला आहे. रोममध्ये १९८४ मध्ये झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत या दोघांनी एकमेकांचे विक्रम मोडण्याचीच स्पर्धा केली होती. त्यात अखेर बुब्का विजेता ठरला होता. बुब्काचे वैशिष्ट्य असे, की त्याने १९८३ नंतर पुढे १४ वर्षांत झालेल्या पाचही जागतिक स्पर्धा सलग जिंकल्या. हाही विक्रमच. आणि सोव्हिएत महासंघातील कम्युनिस्ट राजवटीने प्रत्येक क्षेत्रात आपणच श्रेष्ठ आहोत, हे दाखवण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रात घेतलेल्या प्रचंड मेहनतीचे फळही. 'विक्रम रचा आणि रोख पैसे मिळवा,' अशा चक्क योजनाच आणून या काळात सोव्हिएत महासंघाने खेळाडू तयार केले. बुब्काही त्याच योजनेचा लाभार्थी.



युक्रेनमधील डोनेत्स्क शहरातील सर्जी बुब्का यांचा पुतळा

निराळे तंत्र

पोल व्हॉल्टसारख्या खेळात एखाद्या जिम्नॅस्टसारखी ताकद व चपळता, धावपटूसारखा वेग आणि नेमबाजासारखी अचूकता लागते. 'पोल'च्या म्हणजे ज्या लवचीक काठीच्या आधारे खेळाडू उडी मारतो, ती विशिष्ट ठिकाणी रोवून किती वाकवली, की शरीर हवेत उंच फेकले जाईल, याचा अभ्यास करून सराव केला जातो. बुब्का आणि त्याचा प्रशिक्षक व्हिताली पेत्रोव्ह यांनी थोडे वेगळे तंत्र वापरले. उडीच्या वेळी काठी घट्ट रोवून, वाकवून त्या आधारे उडीची उंची वाढवण्याऐवजी, ती अलगद रोवून, अधिक उभी ठेवून अधिक उंची गाठायची असे तंत्र त्यांनी तयार केले. त्यात उडी मारण्यासाठी येताना धावण्याच्या वेगाचाही विचार केला गेला. बुब्का शालेय जीवनात १०० मीटर शर्यतीतील स्पर्धक म्हणून उत्तम असल्याने त्याचा त्याला फायदा झाला. त्यावरच बुब्काने प्रचंड यश मिळविले. त्याच्या संपूर्ण कारकीर्दीत खरे तर त्याची स्पर्धा स्वतःशी, स्वतःच्या विक्रमांशीच होत राहिली.

बुब्काने पहिला विश्वविक्रम रचला १९८४ मध्ये. त्या वेळेस त्याने ५.८५ मीटर एवढ्या उंचीवरून उडी मारली. हा तो काळ होता, जेव्हा पोल व्हॉल्टमध्ये सहा मीटर उंचीचे अंतर कुणी पार करू शकेल, असे वाटतही नव्हते. बुब्काने मग तेच लक्ष्य ठेवले. त्याला नाव दिले, 'मिशन इम्पॉसिबल'. एकेक सेंटीमीटरने आपली कामगिरी सुधारत बुब्काने वर्षभरातच म्हणजे जून १९८५ मध्ये सहा मीटरची उंची गाठली. अशक्य वाटणारे असेच हे लक्ष्य. त्यातही सुधारणा करत दहा वर्षांत बुब्काने आणखी विक्रम रचले. त्यातील १९९४ मध्ये रचलेला ६.१४ मीटरचा विश्वविक्रम पुढे दोन दशके अबाधित राहिला. विक्रम मोडण्यासाठीच असतात, त्यामुळे बुब्काचा हा विक्रम कधी तरी मोडला जाणारच होता. पण, बुब्का स्वतः खेळत असताना बुब्काचे विक्रम बुब्कानेच मोडण्यासाठी रचलेले असतात, असे समीकरण होते, इतकी बुब्काने पोल व्हॉल्टमध्ये निर्विवाद 'उंची' गाठली होती. म्हणूनच तो सार्वकालिक महान.

पदकांच्या हुलकावण्या

अशा सार्वकालिक महान खेळाडूला तरीही ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदकच का सर्वांत महत्त्वाचे वाटले असेल? कारण, कारकीर्दीच्या सर्वोत्तम टप्प्यावर असतानाच्या तीन ऑलिम्पिक्समध्ये त्याला ते एकदाच मिळाले. कोणत्याही खेळाडूचे स्वाभाविक स्वप्न असते, तसे बुब्काचेही स्वप्न कायम ऑलिम्पिक सुवर्णपदकाचेच होते. त्याला ते मिळविण्याची पहिली संधी होती १९८४ च्या लॉस एंजलिस ऑलिम्पिक्समध्ये. पण, सोव्हिएत महासंघाने या स्पर्धेवरच बहिष्कार घातल्याने त्याला स्पर्धेलाच जाता आले नाही. नंतर १९८८ मध्ये झालेल्या सेऊल ऑलिम्पिक्समध्ये ही संधी मिळाली, जिचे त्याने सुवर्णपदक जिंकून सर्वार्थाने 'सोने' केले. पण, ही स्पर्धा जिंकताना त्याने नोंदवलेली ५.९० मीटर उंची ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी नव्हती. कारण, त्यापूर्वी तीनच वर्षांपूर्वी त्याने जागतिक स्पर्धेत सहा मीटर उंची गाठून 'मिशन इम्पॉसिबल' फतेह केले होते. ही 'उंची' आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये गाठता आली नाही, याची सल बुब्काच्या मनात राहूनच गेली.



बुब्का (पुढे, धूसर) आणि अर्मांड डुप्लान्तिस

ती काढून टाकण्यासाठी त्याने १९९२ च्या बार्सिलोना ऑलिम्पिक्ससाठी खडतर मेहनत घेतली होती. पण, या स्पर्धेतील अंतिम फेरीत त्याचे ५.७० मीटर उंची गाठण्याचे पहिले दोन आणि नंतर ५.७५ मीटरचा एक, असे तिन्ही प्रयत्न फोल ठरले. या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा मॅक्सिम तारासोव्ह हा बुब्का ज्या तालमीत तयार झाला, त्याच सोव्हिएत काळातील प्रशिक्षण सुविधांत शिकलेला. बुब्का म्हणतो, 'मी त्याच्याकडून हरलो, कारण मी कशा प्रकारे स्पर्धेला सामोरे जाईन, याबाबतचे सगळे अंदाज त्याला सहज बांधता आले. माझ्यासाठी हा मोठा धडा होता.' मग पुढचे लक्ष्य १९९६ चे ॲटलांटा ऑलिम्पिक्स.

लक्षात घ्या, या ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरू व्हायच्या आधीची दहा वर्षे सर्गेइ बुब्का पोल व्हॉल्ट प्रकारात अक्षरशः राज्य करत होता. त्याचा ६.१४ मीटरचा विश्वविक्रम १९९४ मध्येच प्रस्थापित झाला होता. एका अर्थाने अटलांटातील ऑलिम्पिक स्पर्धा ही त्याच्या कारकीर्दीतील सर्वोत्तम काळात होत असलेली स्पर्धा होती. पण स्पर्धेला सुरुवात व्हायच्या काही काळ आधी बुब्काला दुखापतीमुळे स्पर्धेतूनच माघार घ्यावी लागली. या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेला फ्रान्सचा जीन गाल्फिओनी काय, किंवा बार्सिलोनात जिंकलेला मॅक्सिम तारासोव्ह काय, आता हे खेळाडू कुणाला फारसे माहीतही नसतील. पण, बुब्काच्या सर्वोत्तम काळात त्यांनी पोल व्हॉल्टमध्ये ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकले, याची नोंद इतिहासात कधीचीच झाली आहे. ऑलिम्पिक पदकाची 'उंची' ही अशी असते. बुब्काने या घटिताचे खूप छान विश्लेषण केले आहे. तो म्हणतो, 'ऑलिम्पिक ही कायमच विशेष स्पर्धा असते. त्यात काय होईल, याचा अंदाज कधीच बांधता येत नाही. एखाद्या क्रीडा प्रकारात तुम्ही तुमची कितीही महानता सिद्ध केलेली असो, ऑलिम्पिकच्या वेळी तुम्ही यशस्वी व्हालच असे नाही. ही स्पर्धा अशाच खेळाडूला 'यशस्वी भव' म्हणते, जो नेमक्या क्षणी कामगिरी उंचावतो.'

पुढे २००० चे सिडनी ऑलिम्पिक्स येईपर्यंत बुब्काची कारकीर्द ओसरत आली होती. या स्पर्धेत त्याला ५.७० मीटरची प्राथमिक उंचीही गाठता न येऊन तो स्पर्धेबाहेर पडला. नव्या शतकाची ती नांदी होती. अर्थात, त्याचा ६.१४ मीटरचा विश्वविक्रम मोडण्यासाठी नव्या शतकाची १४ वर्षे खर्ची पडावी लागली. बुब्काच्याच मायदेशात - युक्रेनमधील डोनेत्स्कमध्ये- बुब्काच्याच उपस्थितीत २०१४ साली तो मोडला गेला. फ्रेंच पोल व्हॉल्टपटू रेनाँ लॅविलेनीने ही कामगिरी केली.

सुरुवातच '६'पासून...

आजघडीला पोल व्हॉल्टमध्ये राज्य करतो आहे स्वीडनचा अर्मांड डुप्लान्तिस. त्याने याच वर्षी मार्चमध्ये ६.३१ मीटर इतकी उंची गाठून स्वतःचाच विश्वविक्रम १५ व्यांदा मोडला! तो बुब्काचा खरा वारसदार. बुब्काचा ६.१४ मीटरचा विक्रम मोडताना लॅविलेनीने ६.१६ मीटर उंची गाठली होती, पण ती एकदाच. ती पार करायला पुढची सहा वर्षे जावी लागली. २०२० मध्ये डुप्लान्तिसने ६.१७ मीटरचा विश्वविक्रम रचला. तो मोडत मोडत आता हा विक्रम ६.३१ मीटर या उंचीला पोहोचला आहे.

डुप्लान्तिसचा जन्म १९९९ सालचा. म्हणजे, ज्या काळात बुब्काची कारकीर्द शेवटाकडे आली होती, त्या वेळचा. बुब्काने आपल्या सर्वोत्तम पाच स्पर्धकांत शेवटचा, पाचवा सर्वांत कठीण स्पर्धक म्हणून उल्लेख केला होता, तो त्याच्यानंतर येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा. बुब्का म्हणतो, 'मी सहा मीटर उंची पार केली, तेव्हा ती अशक्य कोटीतील बाब वाटत होती. पण एकदा ती पार केल्यावर तो इतरांसाठी प्रारंभबिंदू झाला. माझ्यानंतर आलेल्या प्रत्येक पोल व्हॉल्टपटूने शून्यापासून नाही, तर सहा मीटरपासून सुरुवात केली.'

डुप्लान्तिसने तर असे १५ नवे प्रारंभ रचले आहेत, तेही दोन ऑलिम्पिक सुवर्णपदके जिंकत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने बुब्काच्या एक पाऊल पुढे. कोणत्याही खेळात अशा नवनव्या प्रारंभाच्या प्रथाच आवश्यक असतात. कारण, त्यामुळे व्यक्तीपेक्षाही खेळ जिंकत राहतो!

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

सर्वांसाठी समान, पारदर्शी...

'मस्क वाल' मक्तेदार या अग्रलेखात (१६ ऑक्टोबर) सरकारच्या धोरणांतील विरोधाभास आणि मुक्त स्पर्धेच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या मक्तेदारीचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकेकाळी सरकारी साधनसंपत्तीच्या लिलावाचा आग्रह धरणारे आणि प्रशासकीय वाटपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे सत्ताधारी, सत्तेत आल्यानंतर त्याच पद्धतीचे समर्थन करू लागले, तर त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा होणे अपरिहार्य आहे. धोरण कोणते, यापेक्षाही ते सर्वांसाठी समान आणि पारदर्शकपणे लागू होते का, हा खरा प्रश्न आहे. देशातील बहुतांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प, दूरसंचार, ग्राहकवस्तू आणि मनोरंजन क्षेत्रांत वारंवार मोजक्याच उद्योगसमूहांचे वर्चस्व दिसत असेल, तर 'क्रोनी कॅपिटलिझम' अर्थात सत्तेशी जवळीक असलेल्या उद्योगसमूहांना अनुचित लाभ मिळण्याच्या व्यवस्थेबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. स्पर्धक उद्योगसमूहांचे मौन म्हणजे व्यवस्था निष्पक्ष असल्याचा पुरावा नव्हे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसारख्या सार्वजनिक संस्थांना आधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि स्पर्धेच्या समान संधी का मिळाल्या नाहीत, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे. सार्वजनिक संस्थांची घसरण आणि खासगी उद्योगसमूहांचे वाढते वर्चस्व यांचा संबंध आहे का, याची स्वतंत्रपणे तपासणी आवश्यक आहे. प्रश्न इलॉन मस्क विरुद्ध भारतीय उद्योगपती असा नाही; प्रश्न आहे निष्पक्ष स्पर्धा विरुद्ध संभाव्य मक्तेदारी असा. उद्योगपतींचे सामर्थ्य देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोगी ठरावे, सत्तेच्या जवळिकीमुळे विशेषाधिकार मिळवण्यासाठी नव्हे.

■ **मिलिंद अवसरे,** मुंबई

गांधी फक्त 'मीम' पुरते नाहीत

'रुग्ण सेवेची आठ दशके' हा (१५ ऑक्टोबर) हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. महात्मा गांधींबद्दल असंख्य गोष्टी माहित होत्या. पण उरळीकांचन येथील निसर्गोपचार केंद्र त्यांनी सुरू केले, हे माहीत नसलेले वाचायला मिळाले. जनसामान्यांच्या आरोग्याची इतक्या बारकाईने काळजी करणाऱ्या व्यक्तीचे विचार किती व्यापक असतील हे यातून दिसून येते. परंतु, दुर्दैव हेच की आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांसाठी गांधी मात्र 'मीम' मटेरियल बनून राहिले आहेत. गांधी समजून घेत नाहीत, तोवर आपण कितीही हातपाय मारले तरी जे साध्य करायचे ते जरा कठीणच आहे. गांधी कळलेली व्यक्ती तिच्या आयुष्यात इतर काही नाही झाली, तरी ती चांगला माणूस नक्कीच होईल. तथागत गौतम बुद्धांचे वाक्य आहे, 'जो माझी सेवा करू इच्छितो त्याने रुग्णांची सेवा करावी.' गेली आठ दशके गांधीविचाराने प्रेरित होऊन रुग्णसेवेसाठी राबत आले त्यांना सलाम.

■ **प्रथमेश वाघ,** अंबड, जालना

डिजिटल इंडिया कागदावरच

''डिजिटल इंडिया'त कागदपत्रांचा ससेमिरा'' हा अक्षय शेळके यांचा हा लेख (१६ ऑक्टोबर) शब्दःश खरा आहे. पत्त्यासाठी आधार कार्ड चालणार नाही, रेशनकार्ड चालणार नाही असे प्रत्येक विभागाचे नियम लावून पैसे काढायचा मार्ग मोकळा केला आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑनलाइन आहे असे म्हणतात पण प्रत्यक्ष गेल्याशिवाय व पैसे दिल्याशिवाय ते मिळत नाही. एसटीला आधार कार्ड चालत नाही. तिथे जेष्ठ नागरिक वय ६५. इतर ठिकाणी वय ६०. पॅनकार्ड काढताना कागदपत्रे दिलेली असतात, पण त्यावरची जन्मतारीख इतरत्र चालत नाही. अनेक प्रकारची कार्ड्स काढायला लावून चरायला अनेक कुरणे निर्माण केली आहेत. त्यामुळे डिजिटल इंडिया फक्त कागदावरच आहे.

■ **दीपक घाटे,** सांगली

सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे काय?

'सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर फटाकेबंदी' ही बातमी वाचून (१६ ऑक्टोबर) आनंदी व्यक्त करावा की दुःखी व्हावे असे झाले. रस्ते वगळता सार्वजनिक जागा ही गोष्ट इतकी संदिग्ध आहे की हा निर्णय अंमलबजावणी पातळीवर किती क्लिष्ट आहे याची जाणीव न्यायालयाला नसावी याचे आश्चर्य वाटते...! मुंबई आणि इतरत्रही असणाऱ्या लोकवस्तीचे स्वरूप पाहता रस्त्यालगतची इमारत आणि त्याचे आवार ही सुध्दा सार्वजनिक जगाच ठरते. एखाद्या व्यापारी संकुलात कुणी फटाके वाजविले तर त्याला काय म्हणणार ?

■ **संदीप दातार,** बदलापूर

विजेच्या 'स्मार्ट मीटर'ना सायबर हल्ल्यांचा कितपत धोका?

विशेष विश्लेषण

हर्षवर्धन वाबगावकर
baw_ h1@yahoo.com

फ्रान्समध्ये घडलेल्या एका विचित्र घटनेच्या उदाहरणातून महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांनीही पुढचे धोके ओळखले पाहिजेत...

ही चर्चा आत्ताच कशासाठी?

महाराष्ट्रात विजेची स्मार्ट मीटर्स लावण्यात येत आहेत. पण त्यापासून काही समस्या निर्माण होऊ शकतात काय, हा प्रश्न फ्रान्समधील १२ ऑक्टोबरच्या घटनेने अधोरेखित केला आहे. फ्रान्समधील बहुसंख्य सुपरमार्केटमध्ये थंड (थिजलेले, फ्रोझन) पदार्थ ठेवलेल्या शीतकपाटांमधील तापमान अचानक बऱ्याच प्रमाणात वाढल्यामुळे, त्यांत ठेवलेले पदार्थ नासले व ते सर्व फेकून द्यावे लागले. यामुळे अक्षरशः कोट्यवधी युरोंचे नुकसान झाले. तपासाअंती असे लक्षात आले की, तापमान नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांवर (थर्मोस्टॅट) सायबर हल्ला करून वरील शीतकपाटांमधील तापमान ५० अंश सेल्शिअस (१२२ अंश फॅरेनहाईट) इतके वाढवण्यात आले होते. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी आगीदेखील लागल्या आणि ग्राहकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला. फ्रान्सशिवाय, पोर्तुगाल, स्पेन व हॉलंड इ. देशांतही या हल्ल्याची झळ बसली.

विजेवर चालणारी उपकरणे 'सायबर हल्ल्या'चे सावज कशी ठरली?

ही शीतकपाटे, अन्य यंत्रे विजेवर चालणारी असली तरी, अशा स्वरूपाचा हल्ला करणे शक्य झाले याचे कारण, इंटरनेट अथवा तत्सम संपर्कप्रणालीद्वारे ही यंत्रे जोडलेली होती. सायबर हल्ला करणे शक्य झाले याचे तपशीलात्मक कारण असे की, यंत्रणेतील सॉफ्टवेअर जुने होते; पासवर्ड इ. बऱ्याच काळ बदलले नव्हते. सायबर हल्लेखोरांनी या संपर्कयंत्रणेत बाहेरून अनधिकृतपणे प्रवेश मिळवत तापमान परस्पर बदलवून टाकले. ही यंत्रणा सुटी (स्टॅण्ड अलोन) असती, तर तिचा बाहेरच्या जगताशी संपर्क होऊ शकला नसता व सायबर हल्लेखोरांना या नियंत्रकांवर अशा प्रकारे ताबा मिळवता आला नसता.

यातून हल्लेखोरांना काय मिळणार?

फ्रान्समधील सायबर हल्ल्यामागचे हेतू उघड झाले नसले तरी, पुढच्या काळातील एक शक्यता अशी की, हे 'हल्ले' कोणत्याही मानवी हेतूविनाही केले जाऊ शकतात. 'क्लॉड' एआय बॉटची निर्माण करणाऱ्या अँथ्रोपिक या कंपनीने अलीकडेच एक गंभीर आरोप केला आहे : 'एआय एजंट आता नजीकच्या काळात स्वतःच्या प्रतिकृती (नकला) बनवून विविध उपलब्ध (जोडल्या गेलेल्या) उपकरणांमध्ये लपून बसतील (एआय किडे वा वर्म). एआय एजन्ट हे माहितीचे भुकेले असतात व सतत माहिती गोळा करत राहणे व स्वतःला अद्ययावत ठेवणे हा त्यांचा प्रमुख उद्योग असतो. हे वरकरणी निरुपद्रवी वाटत असले, तरी हे किडे कधी तरी 'काड्या' करतील हे नक्की!' काही काळापूर्वी हे सगळे 'लांडगा आला रे...' अशा स्वरूपाचे कल्पनेचे खेळ वाटत होते; पण बऱ्याच गोष्टी अनपेक्षित वेगाने घडत आहेत व त्या मानाने एकंदर मानव समाजाची तयारी अपुरी पडत आहे.

याचा आपल्या स्मार्ट मीटरशी काय सबंध?

महाराष्ट्रात सध्या विजेची जुनी मीटर्स बदलून त्यांच्या जागी स्मार्ट मीटर्स लावणे सुरू आहे. जुनी मीटर्स फक्त एखाद्या घरी किती वीज बाहेरून (वाहात) घरामध्ये आली याचे मोजमाप करतात. त्यामुळे, किती वीज वापरली गेली हे पाहायचे तर प्रत्यक्ष मीटरसमोर उभे राहून त्या मीटरच्या पडद्यावर दिसणार

Lifetime Free Newspapers Access

FREE • LIFETIME ACCESS • ALL CHANNELS

EDITORIALS PDF

- **English Editorials PDF**
  with International Newspapers Editorials [35–40 pages]
- **Hindi Editorials PDF**
- **Daily Vocabulary PDF**

MAGAZINE CHANNEL

National & International
[General & Exam related]

INTERNATIONAL NEWSPAPERS

Newspapers around the world.
Asian, European & American

INDIAN NEWSPAPERS CHANNEL

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

HINDI NEWSPAPERS

1. दैनिक जागरण
2. जनसत्ता
3. हरिभूमि
4. हिंदुस्तान
5. लोकमत
6. लोकसत्ता
7. दैनिक भास्कर

CLICK HERE ▼

Tap the button above to get free access